



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-24032021-226073
CG-HR-E-24032021-226073

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 23, 2021/चैत्र 2, 1943

No. 110]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 23, 2021/CHAITRA 2, 1943

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा और संघ राज्य क्षेत्र के लिए)

अधिसूचना

गुरुग्राम, 22 मार्च, 2021

सं. जेईआरसी:28/2021.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की 36) की धारा 36, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 51, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65 और धारा 86 के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पिछले प्रकाशनों के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः:

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और सीमा

- 1.1. इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ) विनियम, 2021 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कहा जाएगा।
- 1.2. ये विनियम वित्त वर्ष 2022-23 से और वित्त वर्ष 2024-25 तक, अर्थात् 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक, जब तक कि अन्यथा समीक्षा/ संशोधित/ विस्तारित न हो, इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले सभी मामलों में टैरिफ निर्धारण करने के लिए लागू होंगे।
- 1.3. ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन एंड दीव, पुडुचेरी और चंडीगढ़ पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ

2.1 इन विनियमों में, जब तक अन्यथा संदर्भ में आवश्यकता न हो:

1. **"लेखांकन विवरण"** का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष, तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और टिप्पणियों सहित सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से है:

बशर्ते कि बिजली के वितरण के व्यवसाय में लगे किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, लेखांकन विवरण का अर्थ ऊपर उल्लिखित अनुसार ऐसी मदों से है, जिन्हें ऐसे स्थानीय प्राधिकारी पर लागू संबंधित अधिनियमों या विधियों के अनुसार तैयार और बनाए रखा गया है:

बशर्ते कि जब आयोग द्वारा विनियामक लेखाओं को प्रस्तुत करने के लिए विनियमों को अधिसूचित कर दिया जाता है, तो टैरिफ निर्धारण और टूटिंग अप का अनुप्रयोग विनियामक लेखा पर आधारित होगा;

2. **"अधिनियम"** का अर्थ विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) होगा, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित किया जाता है;
3. **"कुल राजस्व आवश्यकता"** या **"एआरआर"** का अर्थ वार्षिक राजस्व आवश्यकता होगा जिसमें इन विनियमों के अनुसार टैरिफ के माध्यम से रिकवरी के लिए उत्पादक कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी से संबंधित पूंजी पर स्वीकार्य खर्च और पूंजी पर प्रतिलाभ शामिल होगा;
4. **"आवंटन विवरण"** का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष से है, जिसमें एक विवरण द्वारा किसी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देयता, आरक्षित या प्रावधान आदि की मात्रा दर्शाते हुए डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और किसी वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच विभाजन या आवंटन का निर्धारण दर्शाया जाएगा;
5. **"आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता"** का अर्थ होगा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी दीर्घावधि उपभोक्ता या मध्यम अवधि के उपभोक्ता को इंजेक्शन के निर्दिष्ट बिंदु(ओं) और आहरण के बिंदु(ओं) के बीच मेगावाट में बिजली हस्तांतरण और सामान्य परिस्थितियों में "ट्रांसमिशन क्षमता का आवंटन" अभिव्यक्ति का अर्थ तदनुसार माना जाएगा;
6. **"आवेदक"** का अर्थ ऐसी उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी से है, जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन किया है और इसमें उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी शामिल होंगे जिनका टैरिफ आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान आधार पर या टूटिंग-अप प्रक्रिया के भाग के रूप में निर्धारित किया जा रहा है;
7. **"आपूर्ति क्षेत्र"** का अर्थ उस क्षेत्र से होगा जिसके तहत किसी वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति के लिए उसके लाइसेंस द्वारा अधिकृत किया गया है;
8. **"प्राधिकरण"** का अर्थ अधिनियम की धारा 70 में उल्लिखित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से है;
9. **"सहायक ऊर्जा खपत"** या **"एयूएक्स"** का अर्थ किसी उत्पादन स्टेशन के मामले में किसी अवधि के संबंध में ऐसे उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरणों द्वारा खपत ऊर्जा की मात्रा से है, जैसे कि संयंत्र और मशीनरी के प्रचालन के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा उपकरण जिसमें उत्पादन स्टेशन का स्विचयार्ड और उत्पादन स्टेशन के भीतर ट्रांसफार्मर हानि शामिल है, जिसे उत्पादन स्टेशन की सभी यूनिटों के जनरेटर टर्मिनलों पर उत्पन्न सकल ऊर्जा के योग के एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है:

बशर्ते कि सहायक ऊर्जा खपत में आवास कॉलोनी और उत्पादन स्टेशन पर अन्य सुविधाओं के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु इस्तेमाल की गई ऊर्जा और उत्पादन स्टेशन पर निर्माण कार्यों के लिए इस्तेमाल की गई बिजली शामिल नहीं होगी:

बशर्ते आगे यह भी कि संशोधित उत्सर्जन मानकों के अनुपालन के लिए सहायक ऊर्जा खपत पर आयोग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा;

10. किसी दी गई अवधि के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में **"उपलब्धता"** का अर्थ घंटों में समय से होगा जिस अवधि के दौरान ट्रांसमिशन प्रणाली दी गई अवधि में कुल घंटों के प्रतिशत में व्यक्त अपनी रेटेड वोल्टेज पर बिजली का ट्रांसमिशन करने में सक्षम है;
11. **"बैंक दर"** का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित बैंक दर होगा;
12. **"आधार वर्ष"** का अर्थ नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष से तुरंत पहले का वर्ष होगा;
13. **"बल्क पावर ट्रांसमिशन करार"** का अर्थ एक निष्पादित समझौता होगा जिसमें नियम और शर्तें शामिल हैं जिसके तहत ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली को प्राप्त करने का हकदार है;
14. **"वहन लागत"** का अर्थ होगा प्लस 100 आधार अंक सहित 1 अप्रैल को संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को एक (1) वर्ष का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर;
15. **"कानून में परिवर्तन"** का अर्थ निम्नलिखित घटनाओं में से कोई एक घटना होगी:
 - क) अधिनियम को किसी भी नए भारतीय कानून के प्रभाव या प्रख्यापन में लाना; या
 - ख) किसी भी मौजूदा भारतीय कानून को अपनाना, संशोधन, आशोधन, निरसन या पुनः अधिनियमन करना या
 - ग) किसी सक्षम न्यायालय, अधिकरण या भारतीय सरकारी दस्तावेज द्वारा किसी भी भारतीय कानून की व्याख्या या आवेदन में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या या आवेदन के लिए कानून के तहत अंतिम प्राधिकार है; या
 - घ) किसी स्थिति या किसी सहमति या मंजूरी या अनुमोदन या परियोजना के लिए उपलब्ध लाइसेंस में किसी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन; या
 - ङ) भारत सरकार और किसी अन्य संप्रभु सरकार के बीच कोई द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता/ संधि करना या परिवर्तन करना, जिसका उत्पादन स्टेशन या इन विनियमों के तहत विनियमित ट्रांसमिशन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता हो;
16. **"केंद्रीय आयोग"** या **"सीईआरसी"** का अर्थ होगा अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में संदर्भित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग;
17. **"आयोग"** का अर्थ अधिनियम की धारा 83 में संदर्भित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग होगा;
18. **"नियंत्रण अवधि"** का अर्थ 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2025 तक तीन (3) वर्ष की अवधि होगी;
19. **"केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता"** या **"सीटीयू"** का अर्थ कोई भी सरकारी कंपनी होगा जिसे केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (1) के तहत सूचित कर सकती है;
20. **"अंतिम तारीख"** का अर्थ होगा परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से छत्तीस महीने के बाद कैलेंडर महीने का अंतिम दिन:

बशर्ते कि आयोग द्वारा अंतिम तारीख को बढ़ाया गया हो यदि दस्तावेजी सबूतों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि अंतिम तारीख के भीतर पूंजीकरण नहीं किया जा सका क्योंकि परिस्थितियां परियोजना विकासकर्ता के नियंत्रण से परे थीं;
21. **"उपभोक्ता"** कोई भी व्यक्ति होगा जिसे लाइसेंसधारी या सरकार द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम या किसी अन्य कानून, जो लागू हो, के तहत जनता को बिजली की आपूर्ति करने का कार्य सौंपा गया है, और इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर वर्तमान में किसी लाइसेंसधारी, सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति, जैसा मामला हो, के कार्यों के साथ बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा है, लेकिन यह राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक सीमित होगा;

22. **"अनुबंधित क्षमता"** का अर्थ किसी ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा अनुबंधित क्षमता मेगावाट में होगी;
23. **"दिन"** का अर्थ एक दिन 00:00 घंटे से शुरू होकर 24:00 घंटे में समाप्त होगा;
24. ट्रांसमिशन प्रणाली के मामले में **"वाणिज्यिक प्रचालन की तिथि"** या **"सीओडी"** का अर्थ होगा किसी ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा 00:00 घंटे से घोषित तारीख जिसके लिए बिजली ट्रांसमिशन के सफल परीक्षण प्रचालन के बाद ट्रांसमिशन प्रणाली का एक घटक नियमित रूप से सेवा में हो, और संचार संकेतक प्रेषण से प्राप्त तक जा रहा हो:
- बशर्ते कि जहां किसी विशेष उत्पादन स्टेशन से बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन लाइन या सबस्टेशन समर्पित है, वहां उत्पादन कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी जहां तक व्यावहारिक हो, उत्पादन स्टेशन और ट्रांसमिशन प्रणाली को एक साथ स्थापित करने का प्रयास करेंगे और इसे उचित कार्यान्वयन समझौते के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे:
- बशर्ते कि यदि ट्रांसमिशन प्रणाली या उसके किसी घटक को संबंधित उत्पादन स्टेशन के चालू होने या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन प्रणाली को चालू करने में विलंब के कारण नियमित सेवा से रोका जाता है, लेकिन जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या उसके आपूर्तिकर्ता या उसके ठेकेदार जिम्मेदार न हों, तो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी ऐसी ट्रांसमिशन प्रणाली या उसमें मौजूद घटक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के अनुमोदन के लिए आयोग को एक उपयुक्त आवेदन देगा:
- बशर्ते कि उत्पादन स्टेशन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख लागू सीईआरसी टैरिफ विनियम में परिभाषित की जाएगी;
25. **"डी-कैपिटलाइजेशन"** का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार परिसंपत्तियों को हटाने से संबंधित परियोजना की सकल निश्चित परिसंपत्तियों में कमी करना होगा;
26. **"वितरण व्यवसाय"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली को बढ़ाने के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव का व्यवसाय होगा;
27. **"वितरण लाइसेंसधारी"** का अर्थ वह लाइसेंसधारी होगा जो अपने आपूर्ति क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली का प्रचालन करने और उसे बनाए रखने के लिए अधिकृत है;
28. **"डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की व्हीलिंग के लिए वितरण प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव व्यवसाय होगा;
29. **"टैरिफ और प्रभार से अपेक्षित राजस्व"** का अर्थ मौजूदा टैरिफ पर विनियमित व्यवसाय से उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को अर्जित होने का अनुमानित राजस्व होगा;
30. **"बिजली आपूर्ति कोड"** का अर्थ अधिनियम की धारा 50 के तहत विनिर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संहिता होगा;
31. **"मौजूदा परियोजना"** का अर्थ 1 अप्रैल, 2022 से पहले वाणिज्यिक प्रचालन के तहत घोषित किसी परियोजना से होगा;
32. **"अप्रत्याशित परिस्थितियां घटना"** का अर्थ होगा, किसी भी पार्टी के संबंध में, किसी भी घटना या परिस्थिति या घटनाएं या परिस्थितियां, जो तर्कसंगत रूप से नियंत्रण से परे हैं, और संबंधित पार्टी द्वारा निर्णय न लिए जाने के कारण उत्पन्न नहीं हुई हैं, और जिससे उचित देखभाल और परिश्रम करके भी बचा नहीं जा सकता था, तथा कोई भी रोक लगाने से सामान्य सिद्धांत के प्रभाव से बचा नहीं जा सकता था, के तहत निम्नलिखित घटनाएं शामिल होंगी:
- क) प्राकृतिक आपदाएं जैसे बिजली गिरना, सूखा पड़ना, आग लगना और विस्फोट होना, भूकंप आना, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, आंधी, बवंडर, अप्रत्याशित भौगोलिक स्थितियां, या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम स्थितियां जो पिछले सौ वर्षों की घटनाओं से अधिक भयावाह रही हों: या
- ख) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई का कोई भी कार्य: या
- ग) उद्योग-व्यापी हड़ताल और श्रमिक अशांति जिसका भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ता है;

33. **"उत्पादन कंपनी"** का अर्थ कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट निकाय या संघ या व्यक्तिगत निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, या कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, जो किसी उत्पादन स्टेशन का मालिक या प्रचालन या रखरखाव करता है और इन विनियमों के उद्देश्य से इसमें नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी शामिल नहीं होगी;
34. **"उत्पादन स्टेशन"** का अर्थ बिजली उत्पन्न करने के लिए कोई भी स्टेशन होगा, जिसमें किसी भी इमारत और संयंत्रके साथ स्टेप-अप ट्रांसफार्मर, स्विचगियर, स्विच यार्ड, केबल या अन्य सहायक उपकरण, यदि कोई हों, शामिल हैं जिनका इस उद्देश्य और उसके स्थल के लिए उपयोग किया जाता है; कोई साइट जिसका उपयोग उत्पादन स्टेशन के लिए किया जाता है, और किसी भी इमारत का उपयोग उत्पादन स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास के लिए किया जाता है, और जहां बिजली जल-शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसमें पेनस्टॉक, प्रारंभिक और अंतिम कार्य, मुख्य और नियंत्रित जलाशय, बांध और अन्य हाइड्रोलिक कार्य शामिल हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में कोई सब-स्टेशन शामिल नहीं है और इन विनियमों के उद्देश्य से नवीकरणीय स्रोतों से बिजली पैदा करने वाले स्टेशनों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा;
35. **"ग्रिड"** का अर्थ परस्पर जुड़ी ट्रांसमिशन लाइनें, सब-स्टेशन और उत्पादन संयंत्रों की उच्च वोल्टेज आधार प्रणाली होगी;
36. **"ग्रॉस स्टेशन हीट रेट"** या **"जीएचआर"** का अर्थ है थर्मल उत्पादन स्टेशन के जनरेटर टर्मिनलों पर विद्युत ऊर्जा का एक किलोवाट उत्पन्न करने के लिए आवश्यक किलोकैलोरी में ताप ऊर्जा इनपुट;
37. **"एकीकृत उपयोगिता"** का अर्थ है गोवा राज्य में बिजली विभाग और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, अपने वर्तमान रूप में या उत्तराधिकारी संस्थाएं अपने पुनर्गठन के बाद उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण के कार्यों में से एक से अधिक निष्पादन करती हैं;
38. **"लाइसेंसप्राप्त व्यवसाय"** का अर्थ समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के विनियम 2 में परिभाषित किया जाएगा;
39. **"लाइसेंसधारी"** का अर्थ होगा ऐसा व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत लाइसेंस प्रदान किया गया है और इन विनियमों के उद्देश्य से एक एकीकृत उपयोगिता भी शामिल होगी;
40. **"एमसीएलआर"** का अर्थ होगा उधार दर आधारित एक वर्ष (1) भारतीय स्टेट बैंक की निधियों की सीमांत लागत;
41. **"मध्यावधि समीक्षा"** का अर्थ इन विनियमों के विनियम 11 के अनुसार की जाने वाली समीक्षा होगी;
42. **"माह"** का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक कैलेंडर महीना होगा;
43. **"नई परियोजना"** का अर्थ 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद वाणिज्यिक प्रचालन के तहत घोषित एक परियोजना होगी;
44. **"नैर-टैरिफ आय"** का अर्थ अन्य व्यवसाय से प्राप्त किसी आय को छोड़कर टैरिफ के अलावा लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय से संबंधित आय होगा, और वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के मामले में, इसमें क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और व्हीलिंग शुल्क पर अतिरिक्त अधिभार के कारण व्हीलिंग और प्राप्तियों से आय शामिल नहीं होगी;
45. **"प्रचालन और रखरखाव खर्च"** या **"ओएंडएम खर्च"** का अर्थ होगा किसी उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के संबंध में उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रणाली के प्रचालन और रखरखाव पर किया गया खर्च, जिसमें जनशक्ति, मरम्मत, पुर्जों, उपभोग्य सामग्री, बीमा और ऊपरी शीर्ष आदि पर व्यय शामिल है;

46. **"मूल परियोजना लागत"** का अर्थ है उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा, जैसा कि मामला हो, अंतिम तारीख तक परियोजना के मूल कार्यक्षेत्र में आयोग द्वारा स्वीकृत अनुसार किया गया पूंजीगत व्यय;
47. **"अन्य व्यवसाय"** का अर्थ गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के विनियम 2(i)(च) में परिभाषित होगा;
48. **"विवेकसम्मत जांच"** का अर्थ होगा किया गया व्यय या प्रस्तावित व्यय, वित्तपोषण योजना, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, अधिक लागत और समय लगने और ऐसे अन्य कारकों के औचित्य की जांच करना जैसा कि टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा उचित समझा जाएगा;
49. **"रेटेड वोल्टेज"** का अर्थ विनिर्माता के डिजाइन वोल्टेज से होगा जिसके आधार पर ट्रांसमिशन प्रणाली को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है या ऐसा कम वोल्टेज जिस पर ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं के परामर्श से वर्तमान में लाइन चार्ज की जाती है;
50. **"खुदरा आपूर्ति व्यवसाय"** का अर्थ अपने लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अपने उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की बिक्री का व्यवसाय होगा;
51. **"राज्य"** का अर्थ गोवा राज्य होगा, और इसमें जेईआरसी के अधिकार क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश शामिल होंगे;
52. **"राज्य ग्रिड संहिता"** का अर्थ अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) का खंड (ज) के तहत आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य ग्रिड संहिता होगा;
53. **"राज्य भार प्रेषण केंद्र"** या **"एसएलडीसी"** का अर्थ अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित केंद्र होगा;
54. **"ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी"** का अर्थ ट्रांसमिशन लाइनों को स्थापित करने या संचालित करने के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी होगा;
55. **"ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी या ओपन एक्सेस उपयोगकर्ता, जैसा मामला हो, होगा जो बिजली के ट्रांसमिशन के उद्देश्य से अंतर-राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग करता है;
56. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से ट्रांसमिशन प्रणाली और वितरण प्रणाली की एक यूनिट के संबंध में **"उपयोगी आयु"** इन विनियमों के परिशिष्ट I में परिभाषित अनुसार होगी;
57. **"कार्य दिवस"** का अर्थ वह दिन होगा जिस दिन बैंक व्यवसाय के लिए खुले होंगे;
58. **"वर्ष"** या **"वित्तीय वर्ष"** का अर्थ वह वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) होगा, जो कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त होने वाले शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन अधिनियम या ग्रिड संहिता या सीईआरसी टैरिफ विनियमों या राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित किया गया है, का क्रमशः उन्हें अधिनियम या ग्रिड संहिता या सीईआरसी टैरिफ विनियमों या राज्य ग्रिड संहिता में दिया गया अर्थ होगा और यहां उपयोग किए जाने वाले शब्द और अभिव्यक्तियां लेकिन जिन्हें विशेष रूप से यहां या अधिनियम या ग्रिड संहिता या सीईआरसी टैरिफ विनियमों या राज्य ग्रिड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, का आम तौर पर उन्हें विद्युत उद्योग द्वारा दिया गया अर्थ होगा।

2.3 इन विनियमों की व्याख्या में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

- क) एकवचन या बहुवचन शब्द, जैसा मामला हो, को क्रमशः बहुवचन या एकवचन शब्द में शामिल किया गया माना जाएगा;
- ख) "शामिल" या "सहित" शब्दों का पालन "लेकिन सीमित नहीं" माना जाएगा, भले ही ऐसे शब्दों में ऐसे वाक्यांशों या शब्दों का प्रयोग किया गया हो;

- ग) "विनियमों" के संदर्भों को इन विनियमों के संदर्भ के रूप में माना जाएगा या लागू कानूनों के अनुसार आयोग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित या आशोधित किया जा सकता है;
- घ) विनियमों के भीतर शीर्षक को सुविधा के लिए डाला जाता है और इन विनियमों की व्याख्या के उद्देश्य से नीचे दिए गए पाठ के साथ पढ़ा जाता है;
- ङ) संविधियों, विनियमों या दिशा-निर्देशों के संदर्भों में सभी सांविधिक प्रावधानों को ऐसे संविधियों, विनियमों या दिशा-निर्देशों, जैसा मामला हो, को समेकित, संशोधित या प्रतिस्थापित, जैसा कि मामला हो, किया गया माना जाएगा;
- च) इन विनियमों के किसी भी प्रावधान और आयोग द्वारा पारित किसी अन्य विनियमों या आदेशों के बीच विसंगति के मामले में, इन विनियमों के प्रावधान लागू होंगे।

3. विनियम का कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग की सीमा

3.1 आयोग उन सभी मामलों, जिनके लिए आयोग का अधिनियम के तहत क्षेत्राधिकार है, बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के भीतर टैरिफ का निर्धारण करेगा, जिसमें निम्नलिखित मामलों को शामिल किया गया है:

क) किसी वितरण लाइसेंसधारी को किसी उत्पादन कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति:

बशर्ते कि जहां आयोग का मानना है कि बिजली की आपूर्ति की कमी है, तो वह वहां बिजली का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, किसी उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच या वितरण लाइसेंसधारियों के बीच किए गए समझौते के अनुसरण में बिजली की बिक्री या खरीद के लिए टैरिफ की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकती है;

ख) अंतर-राज्य बिजली का पारेषण;

ग) बिजली की अंतर-राज्य व्हीलिंग;

घ) बिजली की खुदरा आपूर्ति:

बशर्ते कि दो या अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा एक ही क्षेत्र में बिजली वितरण के मामले में, आयोग वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की खुदरा बिक्री हेतु टैरिफ की अधिकतम सीमा तय कर सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां आयोग ने अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के तहत कुछ उपभोक्ताओं को ओपन एक्सेस की अनुमति दी है, ऐसे उपभोक्ता, अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधानों के बावजूद, ऐसी निबंधन एवं शर्तों (टैरिफ सहित) पर बिजली की आपूर्ति या खरीद के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ समझौता कर सकते हैं, जैसा कि उनके बीच सहमति हो सकती है। ऐसे ओपेन एक्सेस को समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

3.2 विनियम 49, विनियम 51 और विनियम 58 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित की कुल राजस्व आवश्यकता निर्धारित करेगा:

क) डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस; और

ख) खुदरा आपूर्ति व्यवसाय।

3.3 वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट विनियम 49 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए अलग-अलग विवरण देते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.4 व्हीलिंग शुल्क डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता पर आधारित होगा।

3.5 बिजली की खुदरा बिक्री के लिए खुदरा आपूर्ति टैरिफ खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता पर आधारित होगा।

- 3.6 आयोग गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण) विनियम, 2017 के अनुसार अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के पहले परंतुक के तहत व्हीलिंग प्रभार के अलावा क्रॉस-सब्सिडी अधिभार का निर्धारण करेगा।
- 3.7 आयोग गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (4) के तहत अतिरिक्त अधिभार का निर्धारण भी करेगा।
- 3.8 इन विनियमों में निहित किसी बात के होते हुए, यदि ऐसे टैरिफ का निर्धारण अधिनियम की धारा 63 के अनुरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है, तो आयोग ऐसे टैरिफ को अपनाएगा।

4. प्रचालन मानदंड अधिकतम सीमा मानदंड होंगे

- 4.1 किसी संदेह को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के तहत निर्दिष्ट प्रचालन के मानदंड अधिकतम सीमा के मानदंड हैं और इससे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा मामला हो, और आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार प्रचालन के ऐसे उन्नत मानदंडों को लाभार्थियों द्वारा स्वीकार करने से रोका नहीं जाएगा और ऐसे उन्नत मानदंड टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

अध्याय 2: सामान्य सिद्धांत

5. एमवाईटी ढांचे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

- 5.1 आयोग 1 अप्रैल, 2022 से बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के तहत विनियम 3.1 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के तहत शामिल मामलों के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा।
- 5.2 उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ और शुल्क से समग्र राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) नियंत्रण अवधि शुरू होने से पहले, अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत संपूर्ण नियंत्रण अवधि हेतु लाइसेंसधारी के लिए व्यावसायिक योजना;

ख) विस्तृत बहुवर्षीय टैरिफ आवेदन जिसमें संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए समग्र राजस्व आवश्यकता का वर्षवार पूर्वानुमान और आवेदक द्वारा समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत पहले वर्ष का टैरिफ और प्रभार से अपेक्षित राजस्व का निर्धारण शामिल है:

बशर्ते कि निष्पादन मापदंडों, जिनके अनुमान को इन विनियमों या व्यावसायिक योजना या आयोग द्वारा अनुमोदित बहु वर्षीय टैरिफ आदेश में निर्दिष्ट किया गया है, पूरे नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता में इन निष्पादन मापदंडों के अनुमान का आधार बनेगी:

ग) संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए आयोग द्वारा वर्षवार कुल राजस्व आवश्यकता का निर्धारण और उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ;

घ) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा जिसे अनुमोदित पूर्वानुमान और नियंत्रित और गैर-नियंत्रित कारकों के निष्पादन में भिन्नता से तुलना करते हुए वर्गीकृत किया जाएगा;

ङ) नियंत्रण अवधि के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ का वार्षिक निर्धारण अनुमोदित पूर्वानुमान के आधार पर, वार्षिक निष्पादन की समीक्षा, मध्यावधि समीक्षा और टूटिंग अप प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा;

च) अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना में लेखा-परीक्षित लेखों के आधार पर तथा आवेदक (नियंत्रणीय कारकों) के नियंत्रण में कारकों के कारण उत्पन्न होने वाले और आवेदक (गैर-नियंत्रणीय कारकों) के नियंत्रण से परे

कारकों के कारण निष्पादन में भिन्नता के वर्गीकरण का आयोग द्वारा पिछले वर्ष/ (वर्षों) के व्यय और राजस्व के साथ समायोजन किया जाएगा;

छ) इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानि को आगे अंतरित करने की प्रणाली;

ज) इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियंत्रणीय कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानि के बंटवारे की प्रणाली।

6. आधार वर्ष का मूल्य

6.1 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के मूल्यों का निर्धारण पिछले तीन (3) वर्षों के लेखा परीक्षित लेखों या अनंतिम लेखों और आयोग द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले अन्य कारकों के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि, पिछले तीन (3) वर्षों के लेखा परीक्षित लेखों या अनंतिम लेखों की उपलब्धता के अभाव में, आयोग आधार वर्ष के मूल्यों को निर्धारित करने हेतु अन्य समान उपयोगिताओं के साथ मापदंडों को बेंचमार्क कर सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग आधार वर्ष के लिए मूल्यों को बदल सकता है और इसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षित लेखों से वास्तविक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए नियंत्रण अवधि के लिए मापदंडों के अनुमान को परिवर्तित कर सकता है।

6.2 आयोग विनियम 11 के अनुसार की गई मध्यावधि समीक्षा के दौरान नियंत्रण अवधि के निष्पादन लक्ष्यों पर पुनर्विचार कर सकता है।

7. खुदरा आपूर्ति और डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस का पृथक्करण

7.1 वितरण लाइसेंसधारी लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय को डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लेखों को अलग-अलग करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए एआरआर का प्रयोग व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए एआरआर, जिसमें विनियम 58 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए एआरआर शामिल होगा, का उपयोग खुदरा आपूर्ति टैरिफ निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

7.2 ऐसी अवधि के लिए जब तक लेखों को अलग नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारी संबंधित व्यवसायों को लागत और राजस्व बांटने के लिए विनियम 49 में प्रदान किए गए आवंटन विवरण का उपयोग करेंगे।

8. व्यवसाय योजना

8.1. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी अधिकतम 15 मई, 2021 तक पूरी नियंत्रण अवधि के लिए आयोग द्वारा व्यवसाय योजना के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित एक याचिका दायर करेंगे:

बशर्ते कि उत्पादन कंपनी को नियंत्रण अवधि के लिए व्यवसाय योजना दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8.2. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यावसायिक योजना में डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के अलग-अलग सेक्शन होंगे।

8.3. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यावसायिक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) ट्रांसमिशन नेटवर्क में लोड को बढ़ाने का पूर्वानुमान;

ख) लोड में वृद्धि नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **पूँजी निवेश योजना**, ट्रांसमिशन हानि में कमी का अनुमान और विनियम 8.5 के अनुसार व्यवसाय योजना में प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार उपायों के अनुरूप है;

ग) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की **पूँजीगत संरचना** और वित्तपोषण की लागत (ऋण पर ब्याज और इक्विटी पर प्रतिलाभ), मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तें आदि;

- घ) **निष्पादन लक्ष्य** मदों जैसे ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप ट्रांसमिशन हानि, ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता, ट्रांसफार्मर विफलता दर, और नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता के लिए कोई भी अन्य मापदंड;
- ङ) प्रस्तावित भर्तियों और सेवानिवृत्ति के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान **कर्मचारियों की संख्या के अनुमान**;
- च) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **अन्य व्यवसाय से आय के संबंध में प्रस्ताव**।

8.4. **वितरण लाइसेंसधारी** द्वारा दायर व्यावसायिक योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **पूंजी निवेश योजना** लोड वृद्धि, वितरण हानि में कमी अनुमान और विनियम 8.5 के अनुसार व्यवसाय योजना में प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार उपायों के अनुरूप है;
- ख) प्रत्येक योजना की **पूंजीगत संरचना** और वित्तपोषण की लागत (ऋण पर व्याज और इक्विटी पर प्रतिलाभ), मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तें आदि;
- ग) विनियम 8.6 के अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेणियों के लिए **बिक्री पूर्वानुमान**;
- घ) विनियम 8.7 के अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए बिक्री पूर्वानुमान और वितरण हानि अनुमान के आधार पर **बिजली खरीद योजना**;
- ङ) लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि का **लक्ष्य**;
- च) प्रस्तावित भर्तियों और सेवानिवृत्ति के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान **कर्मचारियों की संख्या का अनुमान**;
- छ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **अन्य व्यवसाय से आय के संबंध में प्रस्ताव**।

8.5. **पूंजी निवेश योजना**

- क) व्यवसाय योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली पूंजी निवेश योजना में नियंत्रण अवधि के दौरान नियोजित नई परियोजनाओं का विवरण, निवेश का उद्देश्य, पूंजी संरचना, कार्यान्वयन अनुसूची, तिमाही-वार पूंजी व्यय और पूंजीकरण अनुसूची, वित्तपोषण योजना, लागत-लाभ विश्लेषण, प्रस्तावित निवेश के कारण नियंत्रण अवधि में परिकल्पित परिचालन दक्षता में सुधार और चल रही परियोजनाओं के ऐसे विवरण शामिल होंगे जो औचित्य सहित समीक्षा के तहत नियंत्रण अवधि में फैल जाएंगे;
- ख) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना प्राधिकारी/ केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता द्वारा बनाई गई योजनाओं और वितरण लाइसेंसधारी की पूंजी निवेश योजना के अनुरूप होगी;
- ग) वार्षिक निष्पादन समीक्षा के दौरान, आयोग अनुमोदित पूंजीगत व्यय की तुलना में लाइसेंसधारी द्वारा किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय की प्रगति की निगरानी करेगा। लाइसेंसधारी वार्षिक निष्पादन समीक्षा, टू-अप और टैरिफ दायर करने के निर्धारण के साथ-साथ वास्तविक पूंजीगत व्यय को प्रस्तुत करेगा;
- घ) नई परियोजनाओं के लिए खर्च की गई पूंजीगत लागत और मौजूदा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त पूंजीगत लागत का भुगतान वार्षिक आधार पर किया जाएगा।

बशर्ते यदि वर्ष दर वर्ष आधार पर की गई वास्तविक पूंजी लागत वाणिज्यिक प्रचालन लागत की तारीख के अनुसार अनुमानित पूंजीगत लागत के आधार पर या अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत लागत के आधार पर आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुमोदित पूंजीगत लागत से बीस (20) प्रतिशत या उससे अधिक तक कम हो, तो आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार अतिरिक्त पूंजी लागत के अनुरूप अतिरिक्त टैरिफ/ प्राप्त राजस्व की लागत वाहक लागत के 1.10 गुना व्याज के साथ संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन को लागू दर के अनुसार, टू-अप के समय संबंधित वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता से समायोजित किया जाएगा।

बशर्ते यदि वर्ष दर वर्ष आधार पर की गई वास्तविक पूंजी लागत वाणिज्यिक प्रचालन लागत की तारीख के अनुसार अनुमानित पूंजीगत लागत के आधार पर या अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत लागत के आधार पर आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अनुमोदित पूंजीगत लागत से बीस (20) प्रतिशत या उससे अधिक हो, तो आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार लाइसेंसधारी की तुलना में किए गए व्यय के अनुसार अतिरिक्त पूंजीगत लागत के अनुरूप प्राप्त टैरिफ/ राजस्व में कमी को संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल के पहले दिन लागू वाहक लागत के 0.9 गुना ब्याज सहित, टू-अप के समय संबंधित वर्ष की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए अनुमति दी जाएगी।

ड.) यदि आपातकालीन कार्य के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है जिसे पूंजी निवेश योजना में अनुमोदित नहीं किया गया है, तो लाइसेंसधारी आयोग से अनुमोदन लेने के लिए प्रस्तावित कार्य की आपात प्रकृति को न्यायोचित ठहराने के कारणों सहित आवेदन में सभी प्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि यदि आपातकालीन कार्य या अप्रत्याशित स्थिति के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है ताकि जान-माल के खतरे को कम किया जा सके और यदि आयोग को उसकी पूर्व सूचना देने से कोई अपूरणीय क्षति या हानि होगी, तो लाइसेंसधारी ऐसा पूंजीगत व्यय कर सकता है और आयोग को वास्तविक अनुमोदन के लिए पर्याप्त औचित्य के साथ विवरण प्रस्तुत कर सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि उपर्युक्त विनियम 8.5(ड.) के उद्देश्य से, ऐसे अनुमोदित पूंजीगत व्यय को लाइसेंसधारी द्वारा किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय और आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत व्यय दोनों का एक भाग माना जाएगा;

(च) लाइसेंसधारी प्रत्येक तिमाही के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें आयोग द्वारा समीक्षा के लिए संबंधित तिमाही के बाद वाले महीने की अंतिम तारीख को या उससे पहले पूंजी निवेश योजना में प्रस्तावित अनुसार पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण की प्रगति का ब्यौरा दिया जाएगा।

8.6. बिक्री का पूर्वानुमान

क) वितरण लाइसेंसधारी प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेणियों के लिए विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर, अपनी व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, आयोग की समीक्षा और अनुमोदन के लिए बिक्री का पूर्वानुमान लगाएगा;

ख) यह पूर्वानुमान पिछले वर्षों में बिजली की वास्तविक मांग, आने वाले वर्षों में मांग में प्रत्याशित वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि, लोड वृद्धि, खपत के पैटर्न में परिवर्तन, लक्षित वितरण हानि और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित होगा;

ग) लाइसेंसधारी व्यापारियों या किसी अन्य लाइसेंसधारियों को बिजली की बिक्री और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को श्रेणी-वार बिक्री को अलग-अलग दर्शाएगा।

8.7. बिजली खरीद योजना

क) वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद के लिए एक योजना तैयार करेगा और व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदन के लिए आयोग को ऐसी योजना प्रस्तुत करेगा:

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि ऐसी बिजली खरीद योजना में इन विनियमों के अनुसार दीर्घावधि (~5 से 25 वर्ष), मध्यावधि (~1 से 5 वर्ष) और बिजली खरीद के अल्पावधि (1 वर्ष तक) स्रोत शामिल हो सकते हैं;

ख) वितरण लाइसेंसधारी की बिजली खरीद योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) असीमिति आधार लोड और आपूर्ति के अपने क्षेत्र के भीतर बिजली के लिए पीक लोड का मात्रात्मक पूर्वानुमान;
- (ii) बिजली खरीद के चयनित स्रोतों से बिजली आपूर्ति की मात्रा का अनुमान, जिसमें स्वयं का उत्पादन भी शामिल है, यदि कोई हो;

- (iii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए प्रस्तावित उपाय;
- (iv) बेस लोड और पीक लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली की उपलब्धता का अनुमान लगाना:
बशर्ते कि मांग और आपूर्ति का ऐसा अनुमान मेगावाट (मेगावाट) में माह-वार आधार पर होगा और साथ ही इसे मिलियन यूनिटों (एमयू) में व्यक्त किया जाएगा;
- (v) आयोग के संबंधित विनियमों के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानक बनाए रखे जाएंगे;
- (vi) बिजली खरीद के नए स्रोतों की आवश्यकता, जिसमें निजी उत्पादन क्षमता में वृद्धि, यदि कोई हो, और आपूर्ति के पहचाने गए नए स्रोत, जो उपर्युक्त (i) से (v) के आधार पर हों;
- (vii) ऐसी खरीद के लिए बिजली, मात्रा और लागत अनुमान के स्रोत:

बशर्ते कि लंबी अवधि की खरीद योजना में निहित पूर्वानुमान या अनुमानों को खरीदी जाने वाली बिजली की मात्रा (एमयू में) और अधिकतम मांग (मेगावाट में) के संदर्भ में पीक और ऑफ-पीक अवधि के लिए अलग-अलग किया जाएगा:

बशर्ते कि नियंत्रण अवधि के लिए पूर्वानुमान या अनुमान नियंत्रण अवधि में प्रत्येक महीने के लिए तैयार किए जाएंगे:

यह भी प्रावधान किया गया है कि दीर्घकालिक खरीद योजना आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों की लागतों के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर एक लागत प्रभावी योजना बनाई जाएगी;

- ग) पूर्वानुमान या अनुमान पिछले आंकड़ों, बिक्री पूर्वानुमान, हानि में कमी की पहल के प्रभाव, उत्पादन स्टेशन संयंत्र लोड कारकों में सुधार, समग्र आर्थिक विकास, बिजली के गहन क्षेत्रों की खपत में वृद्धि, बिजली क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होने और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर पूर्वानुमान तकनीकों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाएगा;
- घ) जहां आयोग ने सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के सह-उत्पादन या नवीकरणीय स्रोतों से खरीदे जाने वाले वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का कोई प्रतिशत निर्दिष्ट किया है, तो बिजली खरीद योजना में कम से कम निर्दिष्ट स्तर तक ऐसे स्रोतों से खरीद की योजना शामिल होगी;
- ङ) वितरण लाइसेंसधारी विद्युत खरीद योजना तैयार करते समय राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता से भी परामर्श करेगा, और ट्रांसमिशन प्रणाली योजना के साथ ऐसी योजना की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी विद्युत खरीद योजना की एक प्रति राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता को भेजेगा;
- च) बिजली खरीद के लिए प्रत्येक दीर्घावधि/ मध्यावधि समझौते या व्यवस्था, जिसमें उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा या आपूर्ति के किसी अन्य स्रोत से, स्टैंडबाय आधार शामिल है, और किसी मौजूदा समझौते या व्यवस्था में कोई भी परिवर्तन आयोग के पूर्व अनुमोदन से लागू होगा:
बशर्ते कि अपनी नवीकरणीय खरीद बाध्यता (आरपीओ) को पूरा करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सामान्य/ वरीय टैरिफ पर बिजली नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की खरीद हेतु आयोग के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता न हो।
- छ) वितरण लाइसेंसधारी, इन विनियमों के तहत खरीद योजना प्रस्तुत करने के समय पहले से ज्ञात या उपलब्ध नहीं अतिरिक्त जानकारी के परिणामस्वरूप, मध्यावधि समीक्षा के लिए अपनी याचिका के भाग के रूप में शेष नियंत्रण अवधि के लिए बिजली खरीद योजना में आशोधन के लिए आवेदन कर सकता है;
- ज) आयोग खरीद योजना के अनुमोदन के समय आयोग को अतिरिक्त सूचना के पहले से ज्ञात या उपलब्ध नहीं होने के परिणामस्वरूप, यदि वह उचित समझे, स्वतः संज्ञान लेते हुए या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर याचिका पर मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में शेष नियंत्रण अवधि के लिए वितरण लाइसेंसधारी की खरीद योजना में संशोधन कर सकता है;

झ) आयोग द्वारा अनुमोदित नियंत्रण अवधि के लिए विद्युत खरीद योजना के अलावा, वितरण लाइसेंसधारी वर्ष के दौरान अतिरिक्त बिजली की खरीद कर सकता है, जहां वर्ष के दौरान बिजली की मांग में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है या आपूर्ति के किसी अनुमोदित स्रोत से बिजली की आपूर्ति में कमी या विफलता हुई है या जब मौजूदा अनुबंधित स्रोतों से बिजली की सोर्सिंग अन्य उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों की तुलना में महंगी हो जाती है, तो वितरण लाइसेंसधारी बिजली की खरीद के लिए अतिरिक्त समझौता या व्यवस्था कर सकता है।

बशर्ते कि वर्ष की छमाही के पहले या दूसरे ब्लॉक के दौरान, खरीदी गई बिजली की मात्रा या लागत में कोई भी भिन्नता, जिसमें पहले से अनुमोदित स्रोत के अलावा कोई अन्य स्रोत भी शामिल है, जिसके आयोग द्वारा अनुमोदित पांच प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है, के लिए पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता होगी:

ज) बशर्ते कि पांच प्रतिशत की सीमा निजी उत्पादन के लिए ईंधन की कीमत में परिवर्तन या एफपीपीसीए प्रणाली के माध्यम से वसूली की अनुमति दी जाने वाली बिजली खरीद की निश्चित या परिवर्तनीय लागत के कारण खरीदी गई बिजली की लागत में भिन्नता पर लागू नहीं होगी;

ट) वितरण लाइसेंसधारी वितरण प्रणाली की स्थिरता को खतरा पैदा करने वाली आपात स्थिति से निपटने के लिए आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना बिजली की खरीद के लिए अल्पकालिक व्यवस्था या समझौता कर सकता है:

बशर्ते कि अल्पावधि बिजली खरीद, जिसके लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, के लिए कोई समझौता या व्यवस्था करने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, वितरण लाइसेंसधारी आयोग को इसका विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें मात्रा, टैरिफ गणना, अवधि, आपूर्तिकर्ता भाग, आपूर्तिकर्ता चयन की विधि और ऐसे अन्य विवरण शामिल होंगे जैसा कि आयोग को आवश्यक हो सकते हैं ताकि यह पता लग सके कि इस विनियम में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन किया गया है;

ठ) जहां आयोग के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किया गया करार या व्यवस्था विनियम 8.7(झ) और 8.7(ज) में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वह इनसे उत्पन्न होने वाले अनुमोदित स्तर पर बिजली खरीद की कुल लागत में की गई किसी भी वृद्धि या इसके परिणामस्वरूप वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए किसी भी नुकसान को उपभोक्ताओं पर डालने से मना कर सकता है।

9. बहु वर्षीय टैरिफ अनुप्रयोग

9.1. आवेदक नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान और नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष का टैरिफ प्रस्ताव, इन विनियमों में प्रदान की गई पद्धति और आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा। आवेदन के साथ ऐसे शुल्क देय होंगे, जैसा कि आयोग द्वारा 30 नवंबर, 2021 तक समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि आवेदन के साथ नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित लेखों और वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान वास्तविक निष्पादन के आधार पर चालू वर्ष के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा और बाद के छह महीनों के लिए अनुमानों के आधार पर टू-अप याचिका भी प्रस्तुत की जाएगी।

9.2. आवेदक व्यक्तिगत परिवर्तनों के व्यवहार से संबंधित अनुमानों का उपयोग करके समग्र राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाएगा जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल राजस्व आवश्यकता शामिल है, और इसमें अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत श्रेणीवार बिक्री और मांग अनुमान, बिजली खरीद योजना, पूंजी निवेश योजना, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों और प्रारूपों के अनुसार इन विनियमों और व्यावसायिक योजना में निर्दिष्ट मापदंडों का अनुमान शामिल है।

9.3. आवेदक निम्नलिखित के आधार पर टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व का पूर्वानुमान लगाएगा:

क) उत्पादन कंपनी के मामले में, नियंत्रण अवधि के भीतर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक यूनिट/ स्टेशन द्वारा उत्पादित की जाने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान;

ख) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के मामले में, नियंत्रण अवधि के भीतर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं को आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता का अनुमान;

- ग) किसी वितरण लाइसेंसधारी के मामले में, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान और नियंत्रण अवधि के भीतर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा संचालित किया जाएगा;
- घ) आवेदन करने की तारीख को लागू टैरिफ।
- ङ) प्रस्तावित टैरिफ।
- 9.4. कुल राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान तथा नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी, नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ का प्रस्ताव करेंगे:
- बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ विनियम 68 और इन विनियमों के अनुसार हों।
- 9.5. आवेदक पूर्वानुमान के समर्थन में पूर्ण विवरण प्रदान करेगा, जिसमें पिछले निष्पादन का विवरण, दक्षता या उत्पादकता लाभ, तकनीकी अध्ययन, संविदात्मक व्यवस्था और/या माध्यमिक अनुसंधान के लिए प्रस्तावित पहल शामिल है लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं होगी, ताकि आयोग पूर्वानुमान के औचित्य का आकलन कर सके।
- 9.6. आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग या तो:
- क) संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के टैरिफ को अनुमोदित करने का आदेश जारी करेगी; या
- ख) आवेदन को अस्वीकार करेगा, जिसके कारणों को जैसा आयोग उचित समझे, लिखित में दर्ज किया जाएगा:
- बशर्ते कि आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

10. विशिष्ट परिवर्तनों के लिए अनुमान

- 10.1. आयोग, व्यवसाय योजना और/या बहुवर्षीय टैरिफ याचिका को मंजूरी देने समय, कुछ परिवर्तनों के लिए अनुमान लगा सकता है, जिसमें सहायक खपत, स्टेशन ताप दर, ओएंडएम व्यय, टीएंडडी हानि आदि शामिल हो सकती हैं लेकिन ये इन तक ही सीमित नहीं होंगी:
- बशर्ते कि उपयोगिताएं बहुवर्षीय टैरिफ याचिका पर आदेश में निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करेंगी:
- यह भी प्रावधान किया गया है कि उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा कि मामला हो, शेष नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के समय समीक्षा की मांग कर सकता है।

11. मध्यावधि समीक्षा

- 11.1. लाइसेंसधारियों द्वारा मध्यावधि समीक्षा के लिए एक याचिका दायर की जा सकती है, जिसमें पहले वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2022-23 के टू-अप के लिए आवेदन और नियंत्रण अवधि के तीसरे वर्ष, अर्थात् वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ निर्धारण शामिल होगा:
- बशर्ते कि याचिका में ऐसी जानकारी शामिल होगी जैसा आयोग द्वारा लेखा विवरणों, बही खातों के उद्धरण और अन्य विवरणों के साथ निर्धारित किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कुल राजस्व आवश्यकता का अनुमोदित पूर्वानुमान लगाने तथा टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व से परिचालन तथा वित्तीय निष्पादन में किसी भी अंतर के कारणों और सीमा का आकलन करने के लिए आवश्यक होगा।
- 11.2. मध्यावधि समीक्षा का कार्यक्षेत्र नियंत्रण अवधि के पहले तीन वर्षों के लिए अनुमोदित पूर्वानुमान की तुलना में वास्तविक परिचालन और वित्तीय निष्पादन; और कुल राजस्व आवश्यकता का संशोधित पूर्वानुमान, मौजूदा टैरिफ से अपेक्षित राजस्व, अपेक्षित राजस्व अंतर, और नियंत्रण अवधि के चौथे और पांचवें वर्ष के लिए विशिष्ट परिवर्तन के लिए प्रस्तावित अनुमान का तुलनात्मक होगा:

बशर्ते कि मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ नियंत्रण अवधि के पहले तीन वर्षों के लिए उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर उचित माने जाने वाली श्रेणीवार बिक्री, बिजली खरीद व्यय, ओएंडएम् व्यय, पूंजीगत व्यय से संबंधित व्ययों को अलग-अलग संशोधित कर सकता है:

आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि मध्यावधि समीक्षा में किए गए संशोधनों के आवश्यक औचित्य को मध्यावधि समीक्षा आदेश में उल्लेख किया जाएगा।

- 11.3. विनियम 11.2 के तहत समीक्षा के पूरा होने पर, आयोग विनियम 13 के तहत निर्दिष्ट परिवर्तनों के लिए, याचिकाकर्ता (नियंत्रणीय कारकों) के नियंत्रण वाले कारकों या उसके नियंत्रण से परे कारकों (नियंत्रणीय कारकों) के लिए निष्पादन में कोई परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन करेगा:

बशर्ते कि विनियम 13.1 के तहत निर्दिष्ट परिवर्तनों के अलावा अन्य परिवर्तनों के लिए निष्पादन में किसी भी भिन्नता या अपेक्षित भिन्नता की आमतौर पर नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी और इसे पूरी तरह से नियंत्रणीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि, जहां याचिकाकर्ता का मानना है कि विनियम 13.1 के तहत निर्दिष्ट किसी भी परिवर्तन के लिए, गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण किसी भी वर्ष के निष्पादन में कोई सामग्री भिन्नता या अपेक्षित भिन्नता है, तो वह ऐसे परिवर्तन को शामिल करने के लिए आयोग में आवेदन कर सकता है।

12. नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा, टूटिंग-अप और टैरिफ निर्धारण

- 12.1. उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा और व्ययों और राजस्व को टूट अप किए जाने के अधीन होंगे।

- 12.2. उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी चालू वर्ष की वार्षिक निष्पादन समीक्षा के लिए आवेदन दायर करेंगे, जो पिछले वर्ष या उस वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखा में उपलब्ध हैं और प्रत्येक वर्ष के 30 नवंबर से पहले आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूपों में टैरिफ का निर्धारण किया गया है:

बशर्ते कि उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा मामला हो, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनुसार आयोग को लेखा परीक्षित लेखों के साथ, बही खातों के उद्धरण के साथ सूचना प्रस्तुत करेगा, और ऐसे अन्य विवरण के रूप में आयोग को कुल राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान तथा टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व से वित्तीय निष्पादन में किसी भी भिन्नता के कारणों और सीमा का आकलन करने की आवश्यकता हो सकती है।

- 12.3. वार्षिक निष्पादन समीक्षा, टूटिंग अप और टैरिफ निर्धारण का कार्यक्षेत्र कुल राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व के अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के निष्पादन की तुलना होगी और इसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

- क) **टू-अप:** वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक के लेखा-परीक्षित वित्तीय और वास्तविक परिचालनात्मक निष्पादन की तुलना जिसके लिए विवेकसम्मत जांच के अधीन ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ टू-अप किया जा रहा है;
- ख) **वार्षिक निष्पादन समीक्षा:** चालू वित्त वर्ष के लिए आवेदक के संशोधित निष्पादन लक्ष्यों के अनुमान की तुलना चालू वित्तीय वर्ष की नियंत्रण अवधि के अनुरूप टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ विवेक जांच के अधीन होगी;
- ग) वर्ष के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के संशोधित पूर्वानुमान के आधार पर नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष के लिए **टैरिफ निर्धारण**;
- घ) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;
- ङ) अन्य प्रासंगिक विवरण, यदि कोई हो।

- 12.4. प्रक्रिया के पूरा होने पर, आयोग नीचे विनियम 13 के तहत निर्दिष्ट परिवर्तन के लिए निष्पादन में कोई भी परिवर्तन या अपेक्षित परिवर्तन करेगा, जिसके कारक आवेदक (नियंत्रणीय कारकों) के नियंत्रण में होंगे या

आवेदक (गैर-नियंत्रणीय कारकों) के नियंत्रण से परे होंगे:

बशर्ते कि विनियम 13.1 के तहत निर्दिष्ट परिवर्तनों के अलावा परिवर्तनों के लिए निष्पादन में किसी भी भिन्नता या अपेक्षित भिन्नता की आमतौर पर नियंत्रण अवधि के दौरान आयोग द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी और इसे पूरी तरह से नियंत्रणीय कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि, जहां याचिकाकर्ता का मानना है कि विनियम 13.1 के तहत निर्दिष्ट किसी भी परिवर्तन के लिए, कि गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण किसी भी वर्ष के लिए निष्पादन में कोई सामग्री भिन्नता या अपेक्षित भिन्नता है, तो यह आयोग पर निर्भर करेगा कि वह ऐसे परिवर्तन को शामिल करे।

12.5. प्रक्रिया पूरा होने पर, आयोग यह रिकार्ड करते हुए आदेश पारित करेगा कि:

- क) गैर-नियंत्रणीय कारकों से संबंधित अनुमोदित लागत के घटक, जो पिछले वर्ष के दौरान वसूल नहीं किए गए थे, इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार टैरिफ में पारित किए जाएंगे:

बशर्ते कि, उत्पादन कंपनी के लिए, उपर्युक्त प्रक्रिया लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगी।

- ख) नियंत्रणीय कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को कुल लाभ या हानि, और इन विनियमों के विनियम 15 के अनुसार साक्षा किए जा सकने वाले ऐसे लाभ या हानि की मात्रा के लिए मंजूरी दी गई है:

बशर्ते कि, उत्पादन कंपनी के लिए, उपर्युक्त प्रक्रिया लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगी।

- ग) उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को उस अवधि के लिए राजस्व अंतर की राशि पर लागत वहन लागत की अनुमति दी जाएगी जिस तारीख से ऐसा अंतर हुआ है अर्थात् वर्ष के अंत से जिसके लिए टू-अप किया गया है, से लेकर इसके समाधान वाले वर्ष के अंत तक राजस्व में घाटे के वित्त-पोषण के लिए लाइसेंसधारी द्वारा लिए गए ऋण की वास्तविक दर के आधार पर इसका समाधान किया जाता है:

बशर्ते कि राजस्व अंतर की राशि पर वहन लागत विवेकसम्मत जांच और वर्ष से पहले के वर्षों में वहन लागत खर्च करने के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने की शर्त पर अनुमति दी जाएगी जिसमें राजस्व अंतर का समाधान किया गया हो:

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि राजस्व घाटे के वित्तपोषण के लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है, तो आयोग एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ उसके किसी भी प्रतिस्थापन पर साधारण ब्याज के आधार पर वहन लागत की अनुमति देगा, जो आरबीआई द्वारा वर्तमान में 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किए गए अनुसार होगा, जैसा कि प्रासंगिक वर्ष तथा 100 आधार अंकों के आधार पर 1 अप्रैल को लागू हो सकता है;

यह भी प्रावधान किया गया है कि राजस्व अधिशेष के मामले में, आयोग लाइसेंसधारी से उस तारीख से वहन लागत वसूलेगा जिस पर ऐसा अधिशेष देय हो गया है, अर्थात् उस वर्ष के अंत से, जिसके लिए टू-अप किया गया है, से लेकर वर्ष के अंत तक, जिसका साधारण ब्याज पर एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ किसी भी प्रतिस्थापन पर समाधान किया जाता है जो आरबीआई द्वारा वर्तमान में 1 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किए गए अनुसार होगा, जैसा कि प्रासंगिक वर्ष तथा 100 आधार अंकों के आधार पर 1 अप्रैल को लागू हो सकता है;

- घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानों और टैरिफ में संशोधन।

13. नियंत्रणीय और गैर-नियंत्रणीय कारक

13.1 इन विनियमों के उद्देश्य के लिए, ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारी के लिए "गैर-नियंत्रणीय कारक" शब्द में निम्नलिखित कारक शामिल होंगे, जिनका लाइसेंसधारी द्वारा उपशमन नहीं किया जा सकता था:

- क) अप्रत्याशित घटनाएं;

- ख) विधि, न्यायायिक घोषणाओं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयोग के आदेशों में परिवर्तन;

- ग) उपभोक्ताओं की संख्या या मिश्रण में भिन्नता या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा;
- घ) अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन हानि;
- ङ) स्वीकृत स्रोतों से बिजली खरीद की दर में भिन्नता के कारण बिजली खरीद की लागत में भिन्नता, बिजली खरीद समझौते या आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की शर्तों के अधीन;
- च) ईंधन लागत में भिन्नता;
- छ) बिजली खरीद मिश्रण में परिवर्तन;
- ज) मुद्रास्फीति;
- झ) वितरण लाइसेंसधारी के लिए ट्रांसमिशन प्रभार;
- ञ) दीर्घावधि ऋणों के लिए बाजार व्याज दरों में भिन्नता;
- ट) कर्मचारियों के वेतन आयोग और अंतिम देयताओं की आवश्यकता के लिए एक-बारगी भुगतान तक सीमित कर्मचारी व्यय;
- ठ) कर और सांविधिक शुल्क;
- ड) आय पर कर;
- ढ) अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालने से प्राप्त आय;

बशर्ते कि जहां आवेदक का मानना है, ऊपर निर्दिष्ट नहीं किसी भी परिवर्तन के लिए गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए निष्पादन में सामग्री भिन्नता या अपेक्षित भिन्नता है, तो ऐसे आवेदक ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए इस विनियम के तहत आयोग के विवेक पर ऐसे परिवर्तन को शामिल करने के लिए आयोग पर आवेदन कर सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि उत्पादन कंपनी के लिए गैर-नियंत्रणीय कारक सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

- 13.2 इन विनियमों के उद्देश्य से, ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारी के लिए "नियंत्रणीय कारक" शब्द में उन कारकों को शामिल किया जाएगा जो लाइसेंसधारी के नियंत्रण में थे, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) पूंजीगत व्यय परियोजना के कार्यान्वयन में समय और/या लागत वृद्धि/क्षमता के कारण पूंजीकरण में भिन्नता, ऐसी परियोजना के कार्यक्षेत्र में अनुमोदित परिवर्तन, सांविधिक शुल्क में परिवर्तन या अप्रत्याशित स्थितियों के कारण न हों;
- ख) व्याज और वित्त प्रभारों में भिन्नता, इक्विटी पर प्रतिलाभ, और पूंजीकरण में भिन्नता के कारण मूल्यह्रास, जैसा कि ऊपर खंड (क) में निर्दिष्ट है;
- ग) वितरण लाइसेंसधारी की तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में भिन्नता;
- घ) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन हानि;
- ङ) ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता;
- च) निष्पादन मापदंडों में भिन्नता;
- छ) समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (वितरण लाइसेंसधारियों के लिए निष्पादन मानक) विनियम, 2015 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता;
- ज) श्रम उत्पादकता में भिन्नता;
- झ) मुद्रास्फीति की सीमा को छोड़कर ओएंडएम् व्ययों में भिन्नता;

ज) विनियम 63 के प्रावधानों के अनुसार बढ़े खाते में डाला गया अशोध्य ऋण:

यह भी प्रावधान किया गया है कि उत्पादन कंपनी के नियंत्रणीय कारक लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट होंगे।

14. गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को आगे देने के लिए प्रणाली

14.1. गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित कुल लाभ या हानि को ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के टैरिफ में समायोजन के रूप में ऐसी अवधि में डाला जाएगा, जैसा कि इन विनियमों के तहत पारित आयोग के आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है:

बशर्ते कि उत्पादन कंपनी के लिए गैर-नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को आगे देने की प्रणाली लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट की जाएगी।

14.2. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा सत्यापन के लिए अपेक्षित अनुसार विस्तृत गणनाओं और सहायक दस्तावेजों के साथ आयोग को किए गए व्यय और अर्जित राजस्व और आयोग द्वारा अनुमोदित आंकड़ों के बीच भिन्नता का विवरण निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

15. नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को बांटने की प्रणाली

15.1. नियंत्रणीय कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित कुल लाभ लाइसेंसधारी और उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा:

15.2. नियंत्रणीय कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को अनुमोदित कुल हानि, यदि कोई हो, जो लाइसेंसधारी के कारण होगी, को उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा।

15.3. उत्पादन कंपनी के लिए नियंत्रणीय कारकों के कारण लाभ या हानि को बांटने की प्रणाली लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट होगी।

16. टैरिफ का निर्धारण

16.1. टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यवाही समय-समय पर यथा संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कार्य संचालन) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।

16.2. इन विनियमों में निहित किसी भी बात के होते हुए, आयोग को निबंधन एवं शर्तों सहित हर समय टैरिफ निर्धारित करने, चाहे स्वतः आधार पर हो या उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर याचिका पर हो, का अधिकार होगा:

बशर्ते कि टैरिफ का ऐसा निर्धारण किसी समझौते या व्यवस्था के अनुसार हो या अन्यथा आयोग द्वारा पहले अनुमोदित किया हो अथवा नहीं तथा इन विनियमों की प्रयोज्यता से पहले या बाद में किसी भी समय किया गया हो।

16.3. इन विनियमों में निहित किसी भी चीज के बावजूद, आयोग सभी टैरिफ को अपनाएगा, यदि इस तरह के टैरिफ का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है:

बशर्ते कि आवेदक ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी आयोग को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यकता हो सकती है कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है।

16.4. मौजूदा उत्पादन स्टेशन के लिए टैरिफ का निर्धारण:

क) जहां आयोग ने इन विनियमों के लागू होने की तारीख से पहले किसी भी समय उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी के बीच बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था को मंजूरी दी है या मौजूदा उत्पादन इकाई/ स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए उसमें निहित टैरिफ को अपनाया है, उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी से बिजली आपूर्ति का टैरिफ ऐसे बिजली खरीद समझौते या ऐसी अवधि के लिए की गई व्यवस्था के अनुसार लिया जाएगा।

ख) जहां, इन विनियमों को लागू करने की तारीख के रूप में, मौजूदा उत्पादन केंद्र से बिजली की आपूर्ति के लिए किसी उत्पादन कंपनी और वितरण लाइसेंसधारी के बीच विद्युत खरीद समझौते या व्यवस्था को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसमें दिए गए टैरिफ को आयोग द्वारा नहीं अपनाया गया है या जहां कोई विद्युत खरीद समझौता या व्यवस्था नहीं है, वहां ऐसी उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को की गई बिजली की आपूर्ति आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत खरीद समझौते के अनुसार होगी:

बशर्ते कि ऐसे बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था के अनुमोदन के लिए वितरण लाइसेंसधारी द्वारा आयोग को इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) महीने की अवधि के भीतर एक आवेदन दिया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि वर्तमान समझौते या व्यवस्था, जैसा भी मामला हो, के तहत बिजली की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि आयोग ऐसे खरीद समझौते को मंजूरी नहीं दे देता और यदि आयोग ऐसे बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था को अस्वीकार करता है तो उसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा, और उसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा।

16.5. नए उत्पादन स्टेशन के लिए टैरिफ का निर्धारण:

क) उत्पादन कंपनी द्वारा वितरण लाइसेंसधारी को नई उत्पादन इकाई/ स्टेशन के लिए बिजली की आपूर्ति का टैरिफ, टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत खरीद समझौते के अनुसार होगा।

16.6. ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ का निर्धारण:

क) आयोग, ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर विनियम 17 के अनुसार निम्नलिखित के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा:

- (i) इन विनियमों के अध्याय 5 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बिजली का पारेषण;
- (ii) इन विनियमों के अध्याय 6 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस; और
- (iii) इन विनियमों के अध्याय 7 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार खुदरा आपूर्ति व्यवसाय।

17. दायर करने की प्रक्रिया

17.1. आवेदक आयोग को अपनी याचिका के भाग के रूप में, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट ऐसे प्रारूपों में, टैरिफ और प्रभारों से कुल राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित राजस्व की अपनी गणना का पूरा विवरण प्रदान करेगा, और तत्पश्चात्, ऐसी आगामी जानकारी या विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जैसा कि आयोग को ऐसी गणना का आकलन करने के लिए आवश्यकता हो सकती है:

बशर्ते कि याचिका के साथ, जहां प्रासंगिक होगा, टैरिफ और प्रभार संशोधन प्रस्ताव में नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के लिए कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली का श्रेणीवार टैरिफ दर्शाया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग आवेदक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के लिए अतिरिक्त/ विकल्प फॉर्मेट निर्दिष्ट कर सकता है, जिसकी समग्र राजस्व आवश्यकता का आकलन करने और टैरिफ का निर्धारण करने के लिए यथोचित आवश्यकता हो सकती है।

17.2. इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी अपेक्षित जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के साथ एक पूर्ण याचिका प्राप्त होने पर, याचिका प्राप्त मानी जाएगी और आयोग याचिका की स्वीकृति के संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।

17.3. याचिका के साथ आवेदन में उल्लिखित तथ्यों से परिचित व्यक्ति के समर्थन में एक हलफनामा संलग्न किया जाएगा।

17.4. आवेदक, आयोग द्वारा याचिका की स्वीकृति के बाद सात (7) दिनों के भीतर, संबंधित क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले कम से कम दो अंग्रेजी और दो स्थानीय भाषा दैनिक समाचार-पत्रों में अपनी याचिका का नोटिस प्रकाशित करेगा:

बशर्ते कि याचिका के नोटिस में निम्नलिखित मापदंड शामिल होंगे:

- i. श्रेणीवार बिक्री की मात्रा;
- ii. बिजली खरीद मात्रा और लागत;
- iii. वितरण हानि;
- iv. सहायक खपत;
- v. ट्रांसमिशन/ उत्पादन प्रणाली की उपलब्धता;
- vi. वार्षिक राजस्व आवश्यकता;
- vii. वार्षिक टैरिफ प्रस्ताव;
- viii. आयोग द्वारा समय से अधिसूचित कोई अन्य मापदंड

बशर्ते कि आवेदक किसी भी व्यक्ति को, ऐसे स्थानों पर और ऐसी दरों पर पूरी याचिका की एक हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार आयोग के समक्ष निर्धारित तरीके से सभी विनियामक फाइलिंग, सूचना, विवरण और दस्तावेजों सहित अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर पाठ खोजे जाने वाले प्रारूप में या डाउनलोड करने वाली स्प्रेडशीट प्रारूप में विस्तृत गणना भी प्रस्तुत करेगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक की इंटरनेट वेबसाइट पर ऐसी जानकारी के लिए वेब लिंक आसानी से सुलभ होगा, जिसे डाउनलोड करने के लिए संग्रहीत और प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आवेदक को आयोग द्वारा ऐसी किसी जानकारी, विवरण या दस्तावेज उपलब्ध कराने से छूट दी जा सकती है, जो गोपनीय प्रकृति की हो।

- 17.5. टैरिफ निर्धारण के प्रस्ताव पर कोई सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, तो उन्हें प्रकाशित नोटिस में किसी भी व्यक्ति द्वारा संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए) के सचिव के समक्ष आवेदक को एक प्रति के साथ दायर किया जा सकता है।
- 17.6. आवेदक उपर्युक्त के रूप में नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर, प्रकाशित नोटिस का विवरण शपथ-पत्र पर आयोग को प्रस्तुत करेगा और उन समाचार-पत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जहां नोटिस प्रकाशित किया गया है।
- 17.7. आवेदक आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन के प्रत्युत्तर में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर अपनी टिप्पणियां दायर करेगा।

18. टैरिफ आदेश

- 18.1. आयोग पूरी याचिका को स्वीकार करने की तारीख से एक सौ बीस (120) दिनों के भीतर, याचिकाकर्ता द्वारा बाद में आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रदान करने के अधीन होगा:

क) टैरिफ आदेश जारी करेगा; या

ख) यदि ऐसा आवेदन अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों या विद्यमान किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार के अनुसार नहीं है तो आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक को उसके आवेदन को अस्वीकार करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

- 18.2. इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ उक्त आदेश में निर्दिष्ट तिथि से लागू होगा और जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता, तब तक ऐसी अवधि के लिए लागू रहेगा जैसा कि उसमें निर्धारित किया जा सकता है।

- 18.3. आवेदक कम से कम दो अंग्रेजी और दो स्थानीय भाषा दैनिक समाचार-पत्रों में आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ प्रकाशित करेगा, जहां उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा मामला हो, के आपूर्ति क्षेत्र के राज्य में स्थान का व्यापक परिचालन हो, वह अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर अनुमोदित टैरिफ अनुसूची प्रदर्शित करेगा, और उचित कॉपी करने के शुल्क का भुगतान करने पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैरिफ को एक बिक्री पुस्तिका के रूप में उपलब्ध कराएगा।

19. टैरिफ आदेश का पालन

- 19.1. किसी भी टैरिफ या किसी भी टैरिफ के भाग को आमतौर पर वर्ष में एक बार से अधिक बार संशोधित नहीं किया जा सकता है, सिवाय उसके जहां किसी ईंधन अधिभार फार्मुले की शर्तों के तहत, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाए, किसी परिवर्तन के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई हो।
- 19.2. यदि कोई भी उत्पादन कंपनी या लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 62 के तहत आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से अधिक मूल्य या शुल्क की वसूली करता है और इन विनियमों के अनुसार, अतिरिक्त राशि उस व्यक्ति को देय होगी जिसने संबंधित अवधि के दौरान लागू बैंक दर के बराबर ब्याज के साथ-साथ ऐसी कीमत या शुल्क का भुगतान किया है, जो किसी अन्य देयता के बिना होगी, जिसके लिए ऐसी उत्पादक कंपनी या लाइसेंसधारी जिम्मेदार हो सकते हैं:

बशर्ते कि किसी भी पक्ष को देय ऐसे ब्याज को लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि लाइसेंसधारी इसके द्वारा भुगतान किए गए या भुगतान किए गए ब्याज का अलग विवरण रखेगा, और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

20. टैरिफ का वार्षिक निर्धारण

- 20.1. आयोग नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए एक बहुवर्षीय टैरिफ ढांचे के तहत कवर करने वाली एक उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के टैरिफ का निर्धारण करेगा, जो निम्नलिखित के संबंध में विनियम 18 में निर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार होगा:

- क) ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारियों के टैरिफ और प्रभारों से समग्र राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित राजस्व का अनुमोदित पूर्वानुमान, जिसमें मध्यावधि समीक्षा के समय अनुमोदित संशोधन, यदि कोई हो, शामिल होगा; और
- ख) अनुमोदित लाभ और हानि, जिसमें पिछले वर्ष के टूटिंग अप के बाद टैरिफ के माध्यम से आगे दिए जाने वाले प्रोत्साहन भी शामिल होंगे।

21. सब्सिडी प्रणाली

- 21.1. यदि सरकार को आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में किसी भी उपभोक्ता या वर्ग के उपभोक्ताओं को कोई सब्सिडी देने की आवश्यकता है, तो सरकार किसी भी निर्देश के बावजूद, जैसा कि अधिनियम की धारा 108 के तहत दिया गया हो, सब्सिडी प्रदान करने से प्रभावित वितरण लाइसेंसधारी /व्यक्ति, लाइसेंसधारी या किसी अन्य संबंधित व्यक्ति को एक शर्त के रूप में सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी को लागू करने के लिए मुआवजा देने हेतु अग्रिम राशि का इन विनियमों में निर्दिष्ट तरीके से भुगतान करेगा::

बशर्ते कि यदि इन विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार भुगतान नहीं किया जाता है तो सरकार का ऐसा कोई निर्देश लागू नहीं होगा और इस संबंध में आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होगा।

अध्याय 3: वित्तीय सिद्धांत

22. उत्पादन कंपनी के लिए वित्तीय सिद्धांत

- 22.1. उत्पादन कंपनी के लिए पूंजीगत लागत आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी, जो विवेकसम्मत जांच के अधीन, बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने वाले लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के संगत प्रावधानों द्वारा निर्देशित होगी। इस प्रकार निर्धारित पूंजीगत लागत मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगी।
- 22.2. उत्पादन कंपनी के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण और नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए मानदंड लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों, बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने के अनुसार होंगे।
- 22.3. इक्विटी अनुपात के लिए ऋण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों, इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, विदेशी मुद्रा जोखिम भिन्नता, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, आय पर कर पद्धति, उत्पादन कंपनी के लिए कार्यशील पूंजी हेतु मानदंड आदि सहित वित्तीय सिद्धांतों को बिजली के उत्पादन को नियंत्रित करने के लिए लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

23. ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय के लिए वित्तीय सिद्धांत

- 23.1. इन विनियमों के इस अध्याय के बाद की धाराओं में निर्दिष्ट वित्तीय सिद्धांत ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंसधारी पर लागू होंगे।

24. पूंजीगत लागत

- 24.1. पूंजी निवेश परियोजना के लिए पूंजीगत लागत में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) निर्माण और वित्तपोषण शुल्क, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद स्वीकार किया गया है, के दौरान ब्याज सहित किया जाने वाला या अनुमानित खर्च;
- ख) इस विनियम में निर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारंभिक अतिरिक्त पुर्जे;
- ग) लाइसेंसधारी द्वारा मार्गाधिकार प्राप्त करने पर किया गया व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद स्वीकार किया गया है;
- घ) विनियम 25 के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त पूंजीकरण;
- ङ) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक प्राप्त ऋण राशि से संबंधित विदेशी विनिमय दर भिन्नता के कारण कोई लाभ या हानि, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद स्वीकार किया गया है:

बशर्ते कि वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक प्राप्त ऋण राशि से संबंधित विदेशी विनिमय दर में भिन्नता से होने वाले किसी लाभ या हानि को केवल पूंजीगत लागत के ऋण घटक के खिलाफ समायोजित किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि परियोजना का भाग बनाने वाली परिसंपत्तियों की पूंजीगत लागत, जिसका उपयोग नहीं किया गया है या उपयोग में नहीं हैं, को पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा:

यह भी प्रावधान किया है कि लाइसेंसधारी इस्तेमाल की जा रही परिसंपत्तियों के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा।

- 24.2 विवेकसम्मत जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकार की गई पूंजीगत लागत, टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगी:

बशर्ते कि विवेक पूर्वक की गई जांच में पूंजीगत व्यय के औचित्य की जांच, वित्तपोषण की पसंद और तरीके सहित वित्त-पोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, अधिक लागत और समय लगने, और ऐसे अन्य मामलों को शामिल किया जाएगा जिन्हें आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए उपयुक्त माना जा सकता है।

24.3 अनुमोदित पूंजीगत लागत टैरिफ के निर्धारण पर विचार किया जाएगा और यदि पूंजीगत लागत में किसी भी वृद्धि के लिए औचित्य प्रदान किया जाता है, तो आयोग द्वारा विवेक पूर्वक की गई जांच के अधीन इस पर विचार किया जा सकता है:

बशर्ते कि यदि वास्तविक पूंजीगत लागत अनुमोदित पूंजीगत लागत से कम हो, तो लाइसेंसधारी के टैरिफ के निर्धारण के लिए वास्तविक पूंजी लागत पर विचार किया जाएगा।

24.4 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के लेखा परीक्षित लेखों के आधार पर कार्य के मूल कार्यक्षेत्र के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को वास्तविक पूंजीगत व्यय पर माना जा सकता है जो आयोग द्वारा विवेक पूर्वक की गई जांच के अधीन होगा।

24.5 जहां बल्क पावर ट्रांसमिशन समझौते में पूंजीगत लागत की अधिकतम सीमा का प्रावधान है, वहां पूंजीगत लागत ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

24.6 पूंजीगत लागत में निम्नलिखित अधिकतम मानदंडों के अधीन संयंत्र के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जों और अंतिम तारीख तक मशीनरी लागत शामिल हो सकती है:

क) ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन	1.0%
ख) ट्रांसमिशन सब-स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन (ग्रीन फील्ड)	4.0%
ग) ट्रांसमिशन सब-स्टेशन (ब्राउन फील्ड)	6.0%
घ) सीरिज मुआवजा उपकरण और एचवीडीसी स्टेशन	4.0%
ड.) गैस इंसुलेटेड सब-स्टेशन (जीआईएस)	5.0%
च) संचार प्रणाली	3.5%

24.7 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के लिए लागू पुरानी चल परिसंपत्तियों पर उनकी आयु के आधार पर बदलने, नवीकरण और आधुनिकीकरण या विस्तार पर किया गया कोई भी व्यय को मूल पूंजीगत लागत से ऐसी बदली गई परिसंपत्तियों के निवल मूल्य को बढ़े खाते में डालने के बाद विचार किया जाता है जिसकी गणना निम्न प्रकार से की जाएगी:

प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों का निवल शुद्ध मूल्य = ओसीएफए – एडी- सीसी

जहां;

ओसीएफए: प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की मूल पूंजी लागत

विज्ञापन: प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों से संबंधित संचित मूल्यह्रास

प्रतिलिपि: कुल उपभोक्ता प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों से संबंधित योगदान:

यह भी प्रावधान किया गया है कि इसके प्रतिस्थापन की आवश्यकता वाली किसी भी परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्राप्त बीमा आय की राशि, यदि कोई हो, को पहले बकाया वास्तविक या मानक ऋण की दिशा में समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, को ऐसी प्रतिस्थापित परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा, और आगे किसी भी शेष राशि को गैर-टैरिफ आय के रूप में माना जाएगा।

25 अतिरिक्त पूंजीकरण

25.1 नई परियोजना या मौजूदा परियोजना के संबंध में, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद और अंतिम तारीख तक, आयोग द्वारा विवेक पूर्वक की गई जांच के अधीन, कार्य के मूल कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मामलों पर वास्तव में खर्च या अनुमानित पूंजीगत व्यय,

- भुगतान न की गई देनदारियां, जो भावी तारीख में देय होंगी;
- निष्पादन के लिए आस्थगित कार्य;

- (iii) विनियम 24.6 के प्रावधानों के अनुसार, मूल कार्य क्षेत्र के भीतर प्रारंभिक पूंजीगत अतिरिक्त पुर्जों की खरीद;
- (iv) मध्यस्थता निर्णय को पूरा करने के लिए या आदेश या विधि न्यायालय के डिक्री के अनुपालन के लिए देनदारियां; और
- (v) कानून में बदलाव या किसी भी मौजूदा कानून का अनुपालन:
बशर्ते कि व्यय के अनुमानों के साथ मूल कार्यक्षेत्र में शामिल परिसंपत्ति-वार/ कार्य-वार कार्यों का ब्यौरा, भावी तारीख में देय होने वाली देनदारियों और निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों को टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

25.2 मूल कार्यक्षेत्र में और अंतिम तारीख के बाद निम्नलिखित मामलों पर नई परियोजना के संबंध में किए जाने वाले पूंजीगत व्यय या अनुमान को आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच के अध्यक्षीन स्वीकार किया जाएगा:

- (i) मध्यस्थता निर्णय को पूरा करने के लिए या आदेश या विधि न्यायालय के डिक्री के अनुपालन के लिए देनदारियां;
- (ii) कानून में बदलाव या किसी मौजूदा कानून का अनुपालन;
- (iii) वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देनदारियों के निर्वहन की सीमा तक अंतिम तारीख के बाद आयोग द्वारा स्वीकार किए गए कार्यों के लिए देयता;
- (iv) अंतिम तारीख से पहले निष्पादित कार्यों के लिए कोई भी देयता, ऐसी निष्प्रयोज्य देयता के विवरण की जांच के बाद, पैकेज की कुल अनुमानित लागत, भुगतान पर रोक लगाने और ऐसे भुगतानों को जारी करने के कारण, आदि।

25.3 मौजूदा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित पर मूल कार्यक्षेत्र से अधिक और अंतिम तारीख के बाद किया जाने वाला या अनुमानित व्यय को आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच के अध्यक्षीन स्वीकार किया जाएगा:

- (i) मध्यस्थता निर्णय को पूरा करने के लिए या आदेश या विधि न्यायालय के डिक्री के अनुपालन के लिए देनदारियां;
- (ii) कानून में बदलाव या किसी मौजूदा कानून का अनुपालन;
- (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा/ आंतरिक सुरक्षा के लिए उत्तरदायी उपयुक्त सरकारी एजेंसियों या सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा सलाह या निर्देशित पूंजीगत परिसंपत्ति की आवश्यकता के कारण किया जाने वाला कोई भी खर्च;
- (iv) अंतिम तारीख से पहले निष्पादित कार्यों के लिए कोई भी देयता, ऐसी निष्प्रयोज्य देयता के विवरण की जांच के बाद, पैकेज की कुल अनुमानित लागत, भुगतान पर रोक लगाने और ऐसे भुगतानों को जारी करने के कारण, आदि।
- (v) आयोग द्वारा वास्तविक भुगतानों द्वारा ऐसी देनदारियों के निर्वहन की सीमा तक अंतिम तारीख के बाद स्वीकार किए गए कार्यों के लिए कोई देयता;
- (vi) कोई भी अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, जो ट्रांसमिशन प्रणाली के कुशल प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया है। इस दावे को परिसंपत्तियों के खराब होने की स्थिति में स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण परिणामों, प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के मामले में स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी के पुरानेपन, तकनीकी कारण से क्षमता को बढ़ाने जैसे दोष स्तर में वृद्धि को परीक्षण परिणामों द्वारा विधिवत रूप से समर्थित तकनीकी औचित्य के साथ प्रमाणित किया जाएगा; और
- (vii) ट्रांसमिशन प्रणाली के मामले में, रिले जैसी वस्तुओं पर कोई अतिरिक्त व्यय, नियंत्रण और इंस्ट्रुमेंटेशन, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, डीसी बैटरी, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के कारण प्रतिस्थापन, दोष का स्तर लेवल बढ़ने के कारण स्विचयार्ड उपकरणों का प्रतिस्थापन, टॉवर सुदृढीकरण, संचार उपकरण, आपातकाल बहाली प्रणाली, इंसुलेटर सफाई अवसंरचना, पॉलिमर इंसुलेटर के साथ

पोर्सिलेन इंसुलेटर का प्रतिस्थापन, बीमा के दायरे में नहीं आने वाले क्षतिग्रस्त उपकरणों का प्रतिस्थापन और ट्रांसमिशन प्रणाली के सफल और कुशल प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया है।

बशर्ते कि छोटी वस्तुओं या परिसंपत्तियों को खरीदने पर कोई भी व्यय जिसमें उपकरण और साजो-सामान, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कंप्यूटर, पंखे, वाशिंग मशीन, हीट कन्सेक्टर, गद्दे, कालीन आदि शामिल हैं, जिन्हें अंतिम तारीख के बाद खरीदा गया है, पर टैरिफ के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजी देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि नवीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) या ओएंडएम व्यय के तहत मरम्मत और रखरखाव के तहत किसी भी व्यय का दावा किया गया है, तो इस विनियम के तहत समान व्यय का दावा नहीं किया जा सकता है।

25.4 टैरिफ पर अतिरिक्त पूंजीकरण में भिन्नता के प्रभाव, जैसा मामला हो, पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान विचार किया जाएगा।

25.5 किसी उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी की परिसंपत्तियों का पूंजीकरण हटाने, जैसा भी मामला हो, के लिए ऐसी परिसंपत्ति की मूल लागत को पूंजीकरण की तारीख को सकल निश्चित परिसंपत्ति के मूल्य से घटाया जाएगा और वर्ष में संबंधित ऋण के साथ-साथ इक्विटी को बकाया ऋण और इक्विटी से क्रमशः घटाया जाएगा, तथा ऐसा पूंजीकरण संचयी मूल्यहास और संचयी ऋण के संचयी पुनर्भुगतान में इसका समायोजन करके किया जाता है, जिसमें इसे पूंजीकृत किया गया था।

26 उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, अनुदान और पूंजीगत राजसहायता

26.1 उपयोगकर्ताओं से आंशिक या पूरी धनराशि प्राप्त करने के बाद ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किए गए कार्यों को जमा कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

26.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत धनराशि सहित राज्य और केंद्र सरकारों से प्राप्त अनुदानों का उपयोग करने वाले पूंजीगत कार्यों को अनुदान की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा;

26.3 समान प्रकृति के किसी अन्य अनुदान या ऐसी राशि के प्राप्त होने जिसके लौटाने की कोई बाध्यता न हो, से किए गए कार्यों और ऐसी आर्थिक सहायता से संबद्ध कोई ब्याज लागत न हो, को भी उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजी सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से किए गए कार्यों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाएगा।

26.4 ऐसे पूंजीगत व्यय पर होने वाले व्यय को इस प्रकार माना जाएगा:

- क) इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार मानक ओएंडएम खर्चों की अनुमति दी जाएगी;
- ख) उपभोक्ता योगदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि में कटौती के बाद इक्विटी अनुपात के लिए ऋण पर विनियम 27 के अनुसार विचार किया जाएगा;
- ग) उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से किए गए कार्यों की सीमा तक मूल्यहास को विनियम 31 में निर्दिष्ट अनुसार अनुमति नहीं दी जाएगी;
- घ) विनियम 28 में निर्दिष्ट इक्विटी पर प्रतिलाभ से संबंधित प्रावधान उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू नहीं होंगे;
- ङ) विनियम 29 में निर्दिष्ट ऋण पूंजी पर ब्याज से संबंधित प्रावधान, उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू नहीं होंगे।

27 इक्विटी अनुपात के लिए ऋण

27.1 मौजूदा परियोजनाओं के मामले में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अनुमेय इक्विटी अनुपात के लिए ऋण पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते कि परिसंपत्तियों को हटाने या प्रतिस्थापन या पूंजी वापस लेने के मामले में, ऊपर उल्लिखित इक्विटी पूंजी को ऐसी परिसंपत्तियों की मूल लागत से 30% (या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तविक इक्विटी घटक, यदि यह 30% से कम है, की सीमा तक कम हो जाएगा) तक घटाया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि परिसंपत्तियों को हटाने या प्रतिस्थापन या पूंजी वापस लेने के मामले में, ऊपर उल्लिखित ऋण पूंजी को दस्तावेजी साक्ष्यों या मानक ऋण घटक, जैसा कि मामला हो, के आधार पर ऐसी परिसंपत्तियों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक कम किया जाएगा।

27.2 नई परियोजनाओं के लिए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को ऋण-इक्विटी अनुपात टैरिफ के निर्धारण की विवेक पूर्वक जांच के बाद, विनियम 24 के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत लागत की राशि का 70:30 होगा:

बशर्ते कि जहां वास्तव में निवेश की गई इक्विटी पूंजीकृत परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत का 30% से कम है, वहां टैरिफ के निर्धारण के लिए वास्तविक इक्विटी पर विचार किया जाए:

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि वास्तव में निवेश की गई इक्विटी पूंजीगत लागत का 30% से अधिक है, तो 30% से अधिक इक्विटी को टैरिफ के निर्धारण के लिए लाइसेंसधारी के लिए एक मानक ऋण के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी वास्तव में निवेश की गई इक्विटी के लिए दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करेगा और इक्विटी के लिए धन के स्रोत को बताएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी को प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रुपए में दर्शाया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि इस योजना के वित्तपोषण के लिए अपने मुक्त भंडारों से शेयर पूंजी और आंतरिक संसाधनों के निवेश को जारी करते समय लाइसेंसधारी द्वारा लिए गए प्रीमियम को इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना करने के उद्देश्य से प्रदत्त पूंजी के रूप में गिना जाएगा, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया जाए और यह आयोग द्वारा पूंजीगत लागत अनुमोदन के 30% की सीमा के भीतर हो।

27.3 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद किए जाने वाले किसी भी व्यय या अनुमान के अनुसार, आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में और आयु बढ़ाने के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण व्यय को इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार सेवित किया जाएगा।

28 इक्विटी पर प्रतिलाभ

28.1 इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों हेतु विनियम 27 के अनुसार निर्धारित प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर की जाएगी और ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

28.2 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ को ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट इक्विटी पर प्रतिलाभ की दर पश्चात् दर पर उपयोग करने के लिए रखी गई परिसंपत्तियों हेतु विनियम 27 के अनुसार निर्धारित इक्विटी पूंजी पर अनुमति दी जाएगी।

28.3 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ को सोलह (16) प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए विनियम 27 के अनुसार निर्धारित इक्विटी पूंजी पर अनुमति दी जाएगी।

28.4 इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी पूंजी के औसत पर की जाएगी।

29 ऋण पर ब्याज

29.1 उपयोग में रखी गई परिसंपत्तियों पर विनियम 27 में दर्शाए गए अनुसार प्राप्त ऋणों को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल मानक ऋण माना जाएगा:

बशर्ते कि प्रगति में पूंजीगत कार्यों पर ब्याज और वित्त प्रभारों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि परिसंपत्तियों से पूंजी निकालने या हटाने के मामले में, ऋण पूंजी को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर पूंजी निकालने या हटाने या प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक घटाया जाएगा।

29.2 1 अप्रैल, 2022 तक बकाया मानक ऋण, सकल मानक ऋण से 31 मार्च, 2021 तक आयोग द्वारा स्वीकार किए गए संचयी पुनर्भुगतान में कटौती करके निकाला जाएगा।

29.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा कि मामला हो, द्वारा प्राप्त किसी भी स्थगन अवधि के बावजूद, ऋण की अदायगी पर परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से विचार किया जाएगा और यह विनियम 31 के अनुसार अनुमानित वार्षिक मूल्यहास के बराबर होगा।

29.4 ब्याज दर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी पर लागू प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर होगी:

बशर्ते कि टूटिंग अप के समय, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को लागू वर्ष के दौरान वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर को विवेकसम्मत जांच के बाद ब्याज दर के रूप में माना जाएगा:

यह भी प्रदान किया गया है कि यदि किसी विशेष वर्ष के लिए कोई वास्तविक ऋण नहीं है, लेकिन मानक ऋण अभी भी बकाया है, तो वास्तविक ऋण के लिए ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के पास वास्तविक ऋण नहीं है, तो एक (1) वर्ष का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ आरबीआई द्वारा वर्तमान में उसका प्रतिस्थापन अधिसूचित किया गया है, जैसा कि प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल को लागू हो, प्लस 100 आधार अंकों का इस्तेमाल मानक ऋण पर ब्याज की अनुमति देने के उद्देश्य से ब्याज दर के रूप में किया जाएगा।

29.5 ऋण पर ब्याज की गणना भारित औसत ब्याज दर को लागू करके वर्ष के मानक औसत ऋण पर की जाएगी:

बशर्ते कि टूटिंग अप के समय, वर्ष के मानक औसत ऋण पर, वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वास्तविक परिसंपत्ति पूंजीकरण के आधार पर विचार किया जाएगा।

29.6 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नए ऋणों के लिए, ब्याज दर को भारतीय रिजर्व बैंक (1) वर्ष की अवधि के लिए लागू होने वाले समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित (1) वर्ष के प्रतिस्थापन के रूप में माना जाएगा, जैसा कि 1 अप्रैल को प्रासंगिक वर्ष प्लस 100 आधार अंकों पर होगा, और (ii) वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित ब्याज की औसत दर के रूप में लागू हो सकता है।

29.7 उपर्युक्त ब्याज गणना में ऋण राशि, मानक या अन्यथा, उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान द्वारा वित्त पोषित पूंजीगत लागत की सीमा तक, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा लगाया गया ब्याज शामिल नहीं होगा।

29.8 किसी भी वर्ष के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए किए गए वित्त प्रभारों को आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच के अधीन टूटिंग-अप के समय अनुमति दी जाएगी।

29.9 अनुमोदित समापन अनुसूची और पूंजीगत लागत की तुलना में समय और/या लागत में वृद्धि के कारण निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज या योजना पूरा करने की स्थिति पर वास्तविक आवश्यकता आधार पर अनुपातहीन ऋण निधियों के अतिरिक्त आहरण के कारण, आयोग द्वारा विवेकसम्मत जांच के बाद मामला दर मामला आधार पर आंशिक रूप से या पूरी तरह से अनुमति दी जाएगी या नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि जहां निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा नियुक्त किसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता द्वारा देरी किए जाने के कारण होता है, तो ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूले गए किसी भी परिसमापन हर्जाना को पूंजीगत लागत की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि विचार किए जाने वाली परिसमापन क्षति की सीमा निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज की राशि पर निर्भर करेगी जिसकी आयोग द्वारा अनुमति दी गई है।

29.10 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा मामला हो, जब तक ब्याज पर शुद्ध बचत नहीं होती, तब तक ऋण को पुन वित्तपोषित करने का हर संभव प्रयास करेगा और ऐसी स्थिति में ऐसे पुनः वित्त-पोषण से जुड़ी लागत लाभार्थियों द्वारा वहन की जाएगी और शुद्ध बचत लाभार्थियों अर्थात् ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी के उपभोक्ता के बीच समान रूप से साझा की जाएगी।

29.11 वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को, जब यह याचिका दायर की गई है, खुदरा उपभोक्ताओं से नकद में रखी गई सुरक्षा जमा राशि पर ब्याज दिया जाएगा:

बशर्ते कि टूटिंग-अप के समय, वर्ष के लिए सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज पर, वर्ष के दौरान लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज के आधार पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच की जाए।

30 विदेशी विनिमय दर भिन्नता

30.1 लाइसेंसधारी विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली के लिए अधिग्रहीत विदेशी ऋण के पुनर्भुगतान के संबंध में आंशिक या अपने विवेक पर पूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव कर सकता है।

30.2 लाइसेंसधारी को संबंधित वर्ष में विदेशी ऋण के अनुरूप विदेशी विनिमय दर भिन्नता से बचने के लिए लागत की वसूली करने की अनुमति दी जाएगी, आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच के अध्यक्षीन ऐसी भिन्नता के अनुरूप अतिरिक्त रुपए की देयता को विदेशी ऋण से बचने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

30.3 इस सीमा तक कि विदेशी मुद्रा जोखिम से बचा न गया हो, संबंधित वर्ष में विदेशी मुद्रा ऋण के अनुरूप ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के प्रति किसी अतिरिक्त रुपए की देयता को आयोग द्वारा विवेक पूर्वक जांच के अधीन अनुमति दी जाएगी।

31 मूल्यहास

31.1 मूल्यहास के उद्देश्य के लिए मूल्य आधार, आयोग द्वारा स्वीकार की गई परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत होगी:

बशर्ते कि सेवानिवृत्त या प्रतिस्थापित या पूंजीकृत परिसंपत्तियों की अनुमोदित मूल लागत को घटाने के बाद मूल्यहास की अनुमति दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत सब्सिडी या अनुदान के माध्यम से वित्तपोषित परिसंपत्तियों पर किसी मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

31.2 परिसंपत्ति के रक्षित मूल्य को 10% माना जाएगा और मूल्यहास को परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत के अधिकतम 90% तक की अनुमति दी जाएगी।

बशर्ते आगे यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के निस्तारण मूल्य को स्वीकार्य पूंजीगत लागत का शून्य (0) प्रतिशत माना जाएगा।

31.3 पट्टे के तहत रखी गई भूमि के अलावा अन्य भूमि मूल्यहास योग्य संपत्ति नहीं होगी और परिसंपत्तियों के मूल्यहास की गणना करते समय इसकी लागत को पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा।

31.4 मौजूदा परिसंपत्तियों के मामले में, 1 अप्रैल, 2022 तक शेष मूल्यहास मूल्य, आयोग द्वारा 31 मार्च, 2021 तक स्वीकृत संचयी मूल्य को परिसंपत्तियों के सकल मूल्यहास से घटाकर निकाला जाएगा।

31.5 मूल्यहास वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से लिया जाएगा। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के अनुमानित वाणिज्यिक प्रचालन के मामले में, परिसंपत्तियों के प्रारंभिक और समापन मूल्य के औसत के आधार पर मूल्यहास की गणना की जाएगी:

बशर्ते कि आयोग की विवेक सम्मत जांच के अध्यक्षीन आवेदक द्वारा पूंजीकृत परिसंपत्ति के दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के समय पूंजीकृत परिसंपत्तियों के लिए टूटिंग-अप के दौरान मूल्यहास की पुन गणना की जाएगी।

31.6 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए, मूल्यहास की गणना ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट दरों और मानदंडों पर की जाएगी।

31.7 वितरण लाइसेंसधारी के लिए मूल्यहास की गणना वार्षिक आधार पर, सीधी रेखा विधि के आधार पर, इन विनियमों के परिशिष्ट I में निर्दिष्ट दरों पर परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर की जाएगी।

31.8 स्वीकार्य मूल्यहास के अलावा, वितरण लाइसेंसधारी मूल्यहास (एएडी) पर अग्रिम का हकदार होगा, जिसकी यहां नीचे दिए गए तरीके से गणना की गई है:

एएडी = ऋण चुकौती अवधि के आधार पर ऋण (पूंजीगत व्यय के लिए जुटाया गया) पुनर्भुगतान राशि, इन विनियमों के आधार पर गणना के अनुसार ऋण राशि की 1/10वीं सीमा के अधीन होगा:

बशर्ते कि मूल्यहास पर अग्रिम की अनुमति तभी दी जाएगी जब किसी विशेष वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक संचयी मूल्यहास से अधिक हो:

यह भी प्रावधान किया गया है कि एक वर्ष में मूल्यहास पर अग्रिम उस वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान और संचयी मूल्यहास के बीच अंतर की सीमा तक सीमित होगा।

31.9 वितरण लाइसेंसधारी नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों की सूची और वार्षिक निष्पादन समीक्षा, टूट-अप और आगामी वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण की याचिका के साथ वर्ष में मूल्यहास का 90% पूरा करने वाली परिसंपत्तियों की सूची प्रदान करेगा।

31.10 वितरण लाइसेंसधारी के लिए शेष मूल्यहास, पूरे ऋण के भुगतान पर परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन तक लागू रहेगा।

32 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

32.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड इन विनियमों के अध्याय 5 में निर्दिष्ट होंगे।

32.2 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड क्रमशः इन विनियमों के अध्याय 6 और अध्याय 7 में निर्दिष्ट किए जाएंगे।

32.3 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, बावजूद इसके कि लाइसेंसधारी ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्यशील पूंजी ऋण नहीं लिया है या मानक आंकड़ों के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण का भुगतान किया है।

32.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर एक (1) वर्ष के भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ उसके किसी भी प्रतिस्थापन के बराबर होगी, जिसे एक (1) वर्ष की अवधि के लिए लागू समय के लिए आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया गया है, जैसा कि वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को लागू हो सकता है, जिसमें 200 आधार अंक पर याचिका दायर की गई है।

33 आय पर कर

33.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए आय पर कर का उपचार लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगा।

33.2 आयोग अपने एमवाईटी आदेश में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए देय आयकर, यदि कोई हो, को वास्तविक आयकर के आधार पर अनंतिम रूप से अनुमोदित करेगा, जिसमें विवेकसम्मत जांच के अधीन वितरण लाइसेंसधारी के लिए उपलब्ध नवीनतम लेखा-परीक्षित लेखों के अनुसार उस पर उप-कर और अधिभार, यदि कोई हो, शामिल होंगे।

33.3 वितरण लाइसेंसधारियों के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय की आय स्ट्रीम पर वास्तव में भुगतान किए गए आयकर, जिसमें उस पर उप-कर और अधिभार, यदि कोई हो, शामिल है और अनुमोदित, यदि कोई हो, के बीच भिन्नता की प्रतिपूर्ति प्रत्येक वर्ष की टूटिंग अप के समय वितरण लाइसेंसधारियों से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर की जाएगी, जो विवेकसम्मत जांच के अधीन होगी।

33.4 ऐसे कर के कारण उपभोक्ताओं से किसी भी राशि की कम वसूली या अधिक वसूली को प्रत्येक वर्ष आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर आकलन के आधार पर समायोजित किया जाएगा, जैसा कि सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया गया है। वितरण लाइसेंसधारी इस भिन्नता में अपनी टूटिंग अप याचिका शामिल कर सकते हैं:

बशर्ते कि प्रमुख व्यवसाय के अलावा किसी भी आय स्ट्रीम पर टैक्स टैरिफ में आगे देने का घटक नहीं होगा और ऐसी अन्य आय पर कर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा वहन किया जाएगा।

34 छूट

34.1 बिलों के शीघ्र भुगतान के लिए वितरण लाइसेंसधारी को उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगी।

34.2 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित ऐसी छूट पर वितरण लाइसेंसधारी की गैर-टैरिफ आय के तहत विचार किया जाएगा।

34.3 लाभार्थियों को उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा प्रदान की गई किसी भी छूट को उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, जैसा मामला हो, के लिए एक खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

35 विलंब भुगतान अधिभार

35.1 यदि किसी लाभार्थी के ट्रांसमिशन प्रभारों के बिलों के भुगतान में विलंब लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अवधि से अधिक हो जाता है, तो लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बिल की राशि पर विलंब भुगतान अधिभार लगाया जाएगा।

35.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित विलंबित भुगतान शुल्क को उसकी गैर-टैरिफ आय के तहत नहीं माना जाएगा।

35.3 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उत्पादन कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को देय भुगतान या विलंबित भुगतान शुल्क को ऐसे वितरण लाइसेंसधारी के व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा।

36 अन्य व्यवसाय से आय

36.1 जहां ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, वहां ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय की गणना समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार की जाएगी, और इसे लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता से घटाया जाएगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारी ट्रांसमिशन या वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए उचित आधार का पालन करेगा तथा समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार लेखा विवरण तैयार करेगा, और उसे टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों की कुल राशि ऐसे अन्य व्यवसाय के राजस्व से अधिक है, वहां ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि नहीं जोड़ी जाएगी।

अध्याय 4: उत्पादन

37 प्रयोज्यता

37.1 इस अध्याय में निहित विनियम, राज्य में स्थित उत्पादन स्टेशन से वितरण लाइसेंसधारी को बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।

37.2 आयोग को निम्नलिखित मामलों में वितरण लाइसेंसधारी को उत्पादन कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारण इस अध्याय में निहित निबंधन एवं शर्तों द्वारा निर्देशित होगा:

- क) जहां ऐसा टैरिफ बिजली खरीद समझौते या इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के बाद दर्ज की गई व्यवस्था के अनुसार है; या
- ख) जहां ऐसा टैरिफ इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख से पहले किए गए विद्युत खरीद समझौते या व्यवस्था के अनुसार होते हैं और या तो आयोग ने पहले ऐसे समझौते/ व्यवस्था को अनुमोदित नहीं किया है या करार/ व्यवस्था में यह परिकल्पना की गई है कि टैरिफ आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियमों पर आधारित होगा; या
- ग) जहां वितरण लाइसेंसधारी बिजली उत्पादन के व्यवसाय में लगा हुआ है, वहां वितरण लाइसेंसधारी के उत्पादन केंद्र द्वारा अपने खुदरा आपूर्ति व्यवसाय को बिजली की आपूर्ति उसके मूल्य का निर्धारण करने के आधार पर की जाती है।

37.3 इस अध्याय 4 में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, यदि ऐसे टैरिफ का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है तो आयोग टैरिफ को अपनाएगा।

38 टैरिफ के घटक

38.1 उत्पादन कंपनी के लिए कुल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) इक्विटी पर प्रतिलाभ ;
- ख) ऋण पर ब्याज और वित्त शुल्क;
- ग) मूल्यहास;
- घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- ङ) प्रचालन और रखरखाव खर्च;
- च) आयकर।

38.2 उपर्युक्त घटकों में से प्रत्येक का उपचार बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने वाले लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगा।

38.3 उत्पादन कंपनी के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और ईंधन लागत की वसूली बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने वाले लागू सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार होगी।

39 प्रचालन के मानदंड

39.1 उत्पादन केंद्र के लिए प्रचालन मानदंड जिनमें मानक वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएफ), मानक वार्षिक संयंत्र भार कारक (एनएपीएफएफ), सकल स्टेशन ताप दर, सहायक खपत आदि शामिल हैं, बिजली उत्पादन को नियंत्रित करने वाले लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होंगे।

अध्याय 5: अंतर-राज्य ट्रांसमिशन

40 प्रयोज्यता

40.1 इस अध्याय में निहित विनियम राज्यों में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली की पहुंच और उपयोग के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

41 टैरिफ के घटक

41.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क, नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली प्रदान करेगा, जिसे समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार पिछले वर्ष के अन्य व्यवसाय से आय और अल्पकालिक ट्रांसमिशन शुल्क से गैर-टैरिफ आय की राशि में से घटाया जाएगा:

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 63 के अनुसरण में प्रतिस्पर्धी रूप से प्रदान की गई ट्रांसमिशन प्रणाली परियोजनाओं के मामले में और ट्रांसमिशन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क ऐसी प्रतिस्पर्धी ट्रांसमिशन परियोजनाओं द्वारा उद्धृत वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा शुल्क (टीएससी) के अनुसार होगा।

41.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा की गई समग्र राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के आवेदन के आधार पर किया जाएगा।

41.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए कुल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) इक्विटी पर प्रतिलाभ ;
- ख) मूल्यहास;
- ग) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार;
- घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा राशि;
- ङ) प्रचालन और रखरखाव खर्च;
- च) आय कर

घटा:

- क) समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार ओपन एक्सेस शुल्क से आय;
- ख) गैर-टैरिफ आय;
- ग) इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यवसाय से आय:

बशर्ते कि इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, मूल्यहास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा की गई राशि और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों के आय कर को इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग द्वारा विवेकसम्मत जांच के अध्यधीन मामला-दर-मामला आधार पर लेखा परीक्षित लेखों के अनुसार टूटिंग अप के समय पूर्व-अवधि आय/ व्यय की अनुमति दी जाएगी।

42 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय

42.1 प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;
- ख) बीमा शुल्क सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय, यदि कोई हो; और
- ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

42.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित लेखों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक का अनुमान, विवेकसम्मत जांच और आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाएगा।

42.3 नियंत्रण अवधि के एन^{वें} वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा:

$$\text{ओएंडएम}_{\text{एन}} = (\text{आर एंड एम}_{\text{एन}} + \text{ईएमपी}_{\text{एन}} + \text{एएंडजी}_{\text{एन}}) \times (1 - \text{एक्स}_{\text{एन}}) + \text{अंतिम देयताएं}$$

जहां,

$$\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} = \text{के} \times \text{जीएफए}_{\text{एन}-1} \times (1 + \text{डब्ल्यूपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ईएमपी}_{\text{एन}} = (\text{ईएमपी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{जी}_{\text{एन}}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ए एंड जी}_{\text{एन}} = (\text{एएंडजी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

'के' स्थिर (% में व्यक्त) है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की फाइलिंग के आधार पर बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए की तुलना में अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्यय तथा आयोग द्वारा उपयुक्त विचार किया गया कोई अन्य कारक शामिल होगा;

सीपीआई_{मुद्रास्फीति} - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि तत्काल पूर्व तीन (3) वर्ष की है;

डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आधार वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन (3) वर्षों की औसत वृद्धि है;

ईएमपी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का कर्मचारी व्यय है;

एएंडजी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंडएम_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाव व्यय;

जीएफए_{एन-1} - एन-1^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल अचल परिसंपत्ति;

एक्स_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। एक्स_{एन} का मूल्य आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त उपयुक्त माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

जी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए एक विकास कारक है। जी_{एन} का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उचित माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

42.4 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारी कर्मचारियों की अंतिम देनदारियों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगा या बीमांकिक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों के कारण किसी भी भिन्नता को आयोग द्वारा विवेक सम्मत जांच के अधीन अलग से अनुमति दी जाएगी।

42.5 अनुमान के उद्देश्य के लिए, कारकों का समान मूल्य - सीपीआई_{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आयोग उस वर्ष के लिए टूटिंग अप प्रक्रिया के दौरान कारकों - सीपीआई_{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - के वास्तविक मूल्यों पर विचार करेगा जिसके लिए टूटिंग अप किया जा रहा है और उस वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय का टूटिंग अप केवल मुद्रास्फीति की सीमा तक किया गया है।

42.6 नए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए, वर्षवार ओएंडएम मानदंडों का निर्धारण मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि यह उन नई परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा, जिन्हें प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर प्रदान किया जाता है।

टिप्पण: "न्यू ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी" शब्द का अर्थ ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी होगा जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के बाद ट्रांसमिशन लाइसेंस प्रदान किया जाता है, और जिनकी ट्रांसमिशन परियोजना परिसंपत्तियों को 1 अप्रैल, 2022 को या उसके बाद स्थापित किया जाता है।

बशर्ते कि टूटिंग अप के समय, मानक और वास्तविक ओएंडएम खर्चों में भिन्नता को विनियम 15 के अनुसार निपटाया जाएगा।

43 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड

43.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी को लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार गणना किए गए वित्तीय वर्ष हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज दिया जाएगा।

44 गैर-टैरिफ आय

44.1 आयोग द्वारा अनुमोदित ट्रांसमिशन व्यवसाय से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि की कटौती ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के वार्षिक ट्रांसमिशन प्रभारों के निर्धारण में कुल राजस्व आवश्यकता से की जाएगी:

बशर्ते ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ-साथ गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण आयोग को प्रस्तुत करेगा।

44.2 गैर-टैरिफ आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) भूमि या भवनों पर किराए से आय;
- ख) निस्तारण मूल्य के 10% से अधिक के कबाड़ की बिक्री से आय;
- ग) सांविधिक निवेश से आय;
- घ) आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज;
- ङ) स्टाफ क्वार्टर से किराया;
- च) ठेकेदारों से किराया;
- छ) संपर्ककर्ताओं और अन्य लोगों से भाड़े के शुल्क से आय;
- ज) विज्ञापनों आदि से आय;
- झ) समानांतर ऑपरेशन शुल्क की तरह विविध प्राप्ति;
- ञ) वार्षिक लेखों के अनुसार अनुदान, सब्सिडी आदि से आस्थगित आय;
- ट) भौतिक सत्यापन पर पाया गया अधिशेष;
- ठ) निवेश, सावधि और कॉल डिपॉजिट और बैंक शेष पर ब्याज;
- ड) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अनुरूप इक्विटी पर प्रतिलाभ से अर्जित निवेश से अर्जित ब्याज/ लाभांश को गैर-टैरिफ आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

45 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए प्रचालन के मानदंड

45.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के लिए प्रचालन के मानदंड लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार लागू होंगे।

बशर्ते कि लाभार्थियों के पास प्रचालन के मानदंडों से अधिक प्रोत्साहन की शेयरिंग, यदि कोई हो, लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगी।

46 ट्रांसमिशन हानि

46.1 राज्य भार प्रेषण केंद्र द्वारा निर्धारित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की ट्रांसमिशन प्रणाली में ऊर्जा हानि, अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग के अनुपात में ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी।

47 अंतर-राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए प्रभार का बंटवारा

47.1 आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता, सभी दीर्घकालिक उपयोगकर्ताओं और ट्रांसमिशन प्रणाली के मध्यम अवधि के उपयोगकर्ताओं द्वारा कुल आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता के अनुपात में मासिक आधार पर निम्नलिखित सूत्र के अनुसार साझा की जाएगी,:

$$\text{एटीसी}_{\text{एन}} = (\text{ट्रांसमिशन एआरआर} / 12) \times (\text{सीसीएन} / \text{एससीसी})$$

जहां,

$\text{एटीसी}_{\text{एन}} = \text{एन}^{\text{वै}} \text{ दीर्घकालिक उपयोगकर्ता या ट्रांसमिशन प्रणाली के मध्यम अवधि के उपयोगकर्ता द्वारा देय वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क;}$

$\text{ट्रांसमिशन एआरआर} = \text{इन विनियमों के अनुसार निर्धारित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता;}$

$\text{सीसी}_{\text{एन}} = \text{एन}^{\text{वै}} \text{ दीर्घावधि प्रयोक्ता उपयोगकर्ता या ट्रांसमिशन प्रणाली के मध्यावधि उपयोगकर्ता द्वारा आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता;}$

$\text{एससीसी} = \text{ट्रांसमिशन प्रणाली के सभी दीर्घकालिक उपयोगकर्ताओं और मध्यावधि के उपयोगकर्ताओं द्वारा आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता का योग;}$

बशर्ते कि $\text{एटीसी}_{\text{एन}}$ प्रत्येक दीर्घकालिक उपयोगकर्ता या ट्रांसमिशन प्रणाली के मध्यम अवधि के उपयोगकर्ता द्वारा मासिक आधार पर देय होगा और इसे राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता (एसटीयू) द्वारा लिया जाएगा।

47.2 अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ता समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार निर्धारित ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान करेंगे।

47.3 अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से लिए गए प्रभारों का 75% दीर्घावधि और मध्यावधि के ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा देय प्रभारों को घटाकर समायोजित किया जाएगा। अल्पकालिक ओपन एक्सेस उपयोगकर्ताओं से लिए गए शेष 25% शुल्क ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी द्वारा बनाए रखे जाएंगे।

48 भारत सरकार की योजना का परिणामी प्रभाव

48.1 अन्य संस्थाओं द्वारा देय ट्रांसमिशन प्रभारों पर ट्रांसमिशन प्रभारों, प्रोत्साहनों और किसी भी संस्था/संस्थाओं के नुकसान को माफ/ कम करने के लिए भारत सरकार की किसी भी योजना के परिणामी प्रभाव का समाधान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अलग-अलग आदेशों के माध्यम से किया जाएगा।

अध्याय 6: डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस

49 वितरण लाइसेंसधारी के लेखों का पृथक्करण

49.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारी डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए लेखों को अलग-अलग रखेगा और आवंटन विवरण तैयार करेगा। वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस से संबंधित व्हीलिंग शुल्क को आयोग द्वारा इन अलग लेखों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि पूर्ण लेखांकन पृथक नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित आवंटन विवरण लागू होगा:

तालिका 1: डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस की पृथक्ता के लिए आवंटन विवरण और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय

विवरण	वायर्स बिजनेस (%)	खुदरा आपूर्ति व्यवसाय (%)
बिजली खरीद व्यय	0%	100%
अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क	0%	100%
अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रभार	0%	100%
कर्मचारी व्यय	40%	60%
प्रशासन और सामान्य व्यय	50%	50%
मरम्मत और रखरखाव व्यय	90%	10%
पूंजीगत लागत	90%	10%
मूल्यहास	90%	10%
दीर्घावधि ऋण पूंजी पर ब्याज	90%	10%
कार्यशील पूंजी और उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज	10%	90%
बट्टे खाते में डाला गया अशोध्य ऋण	0%	100%

विवरण	वायर्स बिजनेस (%)	खुदरा आपूर्ति व्यवसाय (%)
आय कर	90%	10%
गैर-टैरिफ आय	10%	90%
अन्य व्यवसाय से आय	50%	50%

बशर्ते उपर्युक्त आवंटन विवरण व्यय और राजस्व के सभी या किसी भी शीर्ष के लिए लागू होगा, जहां डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच वास्तविक लेखांकन पृथक्करण नहीं किया गया है।

50 प्रयोज्यता

50.1 इस अध्याय में निहित विनियम खुदरा आपूर्ति उपभोक्ताओं के अलावा वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स के उपयोग के लिए व्हीलिंग शुल्क के निर्धारण पर लागू होंगे।

51 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए कुल राजस्व आवश्यकता

51.1 वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए व्हीलिंग शुल्क, कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली के लिए प्रदान करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क) इक्विटी पर प्रतिलाभ;
- ख) ऋण पर ब्याज और वित्त शुल्क;
- ग) मूल्यहास;
- घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा राशि;
- ङ) प्रचालन और रखरखाव व्यय;
- च) आयकर;

घटा:

- छ) गैर-टैरिफ आय;
- ज) इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यवसाय से आय;

बशर्ते कि इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा जमा राशि पर ब्याज, और डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए आय कर पर इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि आयोग द्वारा विवेक सम्मत जांच के अध्यक्षीन, मामला-दर-मामला आधार पर लेखा-परीक्षित लेखाओं के अनुसार, पूर्व अवधि की आय/ व्यय की अनुमति दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया है कि निष्पादन के किसी भी मानकों को पूरा करने में विफलता या नुकसान के लिए लाइसेंसधारी द्वारा देय सभी दंड और मुआवजे को अदालतों, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, और लोकपाल, आदि की आयोग के आदेशों के परिणामस्वरूप, कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंड का अलग विवरण रखेगा और लाइसेंसधारी द्वारा भुगतान या देय क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, को अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

52 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) खर्च

52.1 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय की गणना इस विनियम के अनुसार की जाएगी।

52.2 प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;
- ख) बीमा शुल्क सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय यदि कोई हो; और
- ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

52.3 वितरण लाइसेंसधारी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखा परीक्षित लेखों, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक अनुमानों, विवेक सम्मत जांच के अधीन और आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाएगा।

52.4 नियंत्रण अवधि के एनवें वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा:

$$\text{ओएंडएम}_{\text{एन}} = (\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} + \text{ईएमपी}_{\text{एन}} + \text{एएंडजी}_{\text{एन}}) \times (1 - \text{एक्स}_{\text{एन}}) + \text{अंतिम देयताएं}$$

जहां,

$$\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} = \text{के} \times \text{जीएफए}_{\text{एन}-1} \times (1 + \text{डब्ल्यूपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ईएमपी}_{\text{एन}} = (\text{ईएमपी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{जी}_{\text{एन}}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{एएंडजी}_{\text{एन}} = (\text{एएंडजी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

'के' स्थिर (% में व्यक्त) है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की फाइलिंग के आधार पर बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए की तुलना में अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्यय तथा आयोग द्वारा उपयुक्त विचार किया गया कोई अन्य कारक शामिल होगा;

सीपीआई_{मुद्रास्फीति} - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि तत्काल पूर्व तीन (3) वर्ष की है;

डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आधार वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन (3) वर्षों की औसत वृद्धि है;

ईएमपी_{एन} - एनवें वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का कर्मचारी व्यय है;

एएंडजी_{एन} - एनवें वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंड एमएन - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाव व्यय;

जीएफएन-1 - एन-1^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल अचल परिसंपत्ति;

एक्सएन एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। एक्सएन का मूल्य आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

जीएन एन^{वें} वर्ष के लिए एक विकास कारक है। जीएन का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उचित माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारी इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के अनुसार तीन (3) वर्षों से कम समय के लिए कार्य कर रहा है, तो ओएंडएम व्यय मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

52.5 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारी कर्मचारियों की अंतिम देनदारियों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगा या बीमांकिक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों के कारण किसी भी भिन्नता को आयोग द्वारा विवेक सम्मत जांच के अधीन अलग से अनुमति दी जाएगी।

52.6 अनुमान के उद्देश्य के लिए, कारकों का समान मूल्य - सीपीआई^{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई^{मुद्रास्फीति} - का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आयोग उस वर्ष के लिए टूटिंग अप प्रक्रिया के दौरान कारकों - सीपीआई^{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई^{मुद्रास्फीति} - के वास्तविक मूल्यों पर विचार करेगा जिसके लिए टूटिंग अप किया जा रहा है और उस वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय का टूटिंग अप केवल मुद्रास्फीति की सीमा तक किया गया है।

बशर्ते कि टूटिंग अप के समय, मानक और वास्तविक ओएंडएम व्यय में भिन्नता को विनियम 15 के अनुसार निपटाया जाएगा।

53 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड

53.1 वितरण लाइसेंसधारी को वित्तीय वर्ष के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज दिया जाएगा, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी:

क) एक (1) महीने के लिए ओएंडएम खर्च; प्लस

ख) एक (1) महीने के लिए मरम्मत और रखरखाव व्यय के 40% पर रखरखाव अतिरिक्त पुर्जों; प्लस

ग) मौजूदा टैरिफ पर डिस्ट्रीब्यूशन के उपयोग के लिए शुल्क से अपेक्षित राजस्व के दो (2) महीनों के बराबर प्राप्ति;

घटा

घ) बैंक गारंटी के रूप में आयोजित सुरक्षा जमा को छोड़कर अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत सुरक्षा जमा राशि, यदि कोई हो:

बशर्ते कि किसी भी वर्ष के लिए टूटिंग अप के समय, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पर फिर से गणना की जाएगी।

54 गैर-टैरिफ आय

54.1 डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि के रूप में आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के वहीलिंग शुल्क का निर्धारण करने में कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते वितरण लाइसेंसधारी वहीलिंग शुल्क के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।

54.2 गैर-टैरिफ आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) भूमि या भवनों के किराए से आय;
- ख) निस्तारण मूल्य के 10% से अधिक के कबाड़ की बिक्री से आय;
- ग) सांविधिक निवेश से आय;
- घ) आकस्मिक आरक्षित निवेश पर ब्याज से आय;
- ङ) आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज;
- च) स्टाफ क्वार्टर से किराया;
- छ) ठेकेदारों से किराया;
- ज) संपर्ककर्ताओं और अन्य लोगों से भाड़े के शुल्क से आय;
- झ) विज्ञापनों आदि से आय;
- ञ) विविध प्राप्तियां;
- ट) भौतिक सत्यापन पर पाया गया अधिशेष;
- ठ) वार्षिक लेखों के अनुसार अनुदान, सब्सिडी आदि से आस्थगित आय;
- ड) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के अनुरूप इक्विटी पर प्रतिलाभ से अर्जित निवेश से अर्जित ब्याज/ लाभांश को गैर-टैरिफ आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

55 व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण

55.1 आयोग अधिनियम की धारा 64 की उप-धारा (3) के तहत पारित अपने आदेश में वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के व्हीलिंग प्रभार को निर्दिष्ट करेगा:

बशर्ते कि उपर्युक्त परंतुक के तहत खुदरा उपभोक्ताओं के अलावा, अन्य वितरण प्रणाली प्रयोक्ताओं द्वारा भुगतान किए गए व्हीलिंग प्रभारों से प्राप्त राजस्व का उपयोग गोवा राज्य और समय-समय पर यथा संशोधित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार संबंधित वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस की कुल राजस्व आवश्यकता को घटाया जाएगा।

56 व्हीलिंग घाटा

56.1 वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित वितरण प्रणाली के प्रचालन से होने वाली व्हीलिंग हानियों के अनुमोदित स्तर की वसूली करने की अनुमति दी जाएगी।

अध्याय 7: बिजली की खुदरा आपूर्ति

57 प्रयोज्यता

57.1 ये विनियम अपने उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

58 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कुल राजस्व आवश्यकता

58.1 वितरण लाइसेंसधारी की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ, नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्षों के लिए खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली प्रदान करेगा, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- क) अन्य स्रोतों से स्वयं के बिजली उत्पादन और बिजली खरीद खर्च की लागत;
- ख) अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रभार;
- ग) अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रभार;
- घ) एसएलडीसी शुल्क और प्रभार;
- ङ) समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 उसी वितरण लाइसेंसधारी से बिजली आपूर्ति प्राप्त करने वाल ख़ुदरा उपभोक्ताओं के अलावा वितरण प्रणाली प्रयोक्ताओं द्वारा देय व्हीलिंग प्रभारों से आय की कटौती करने के बाद इन विनियमों के अध्याय 6 के तहत निर्धारित अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेस के लिए कुल राजस्व आवश्यकता संतुलन;
- च) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान;
- छ) इक्विटी पूंजी पर प्रतिलाभ;
- ज) ऑपरेशन और रखरखाव व्यय;
- झ) मूल्यह्रास;
- ञ) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त शुल्क;
- ट) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- ठ) उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज;
- ड) आयकर;

घटा

- द) गैर-टैरिफ आय;
- ण) इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यवसाय से आय;
- त) क्रॉस-सब्सिडी अधिभार के कारण प्राप्तियां;
- थ) अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्तियां;

बशर्ते मूल्यह्रास, ऋण पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज, आकस्मिक भंडार में योगदान, इक्विटी पर प्रतिलाभ, और ख़ुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए आयकर पर इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि पूर्व अवधि आय/ व्यय को आयोग द्वारा लेखा-परीक्षित लेखों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जाएगी जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगा:

यह भी प्रावधान किया है कि निष्पादन के किसी भी मानकों को पूरा करने में विफलता या नुकसान के लिए लाइसेंसधारी द्वारा देय सभी दंड और मुआवजे को अदालतों, उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, और लोकपाल, आदि की आयोग के आदेशों के परिणामस्वरूप, या समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2010 के अनुसार नवीकरणीय खरीद बाध्यता का अनुपालन न करने के लिए लाइसेंसधारियों पर आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना, समग्र राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूली की अनुमति नहीं दी जाएगी:

यह भी प्रावधान किया गया है कि वितरण लाइसेंसधारी ऐसे दंड और भुगतान किए गए मुआवजे, यदि कोई हो, का अलग विवरण रखेगा और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

58.2 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर टैरिफ के निर्धारण की याचिका के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते वितरण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता विनियम 49 में तालिका 1 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेज और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच आवंटित या विभाजित की जाएगी, जब तक कि डिस्ट्रीब्यूशन वायर्स बिजनेज और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए लेखों को अलग नहीं किया जाता है:

यह भी प्रावधान किया गया है कि खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ में उपभोक्ताओं से वसूली के उद्देश्य से निश्चित/ मांग शुल्क, ऊर्जा शुल्क और किसी अन्य शुल्क का कोई संयोजन शामिल हो सकता है, जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:

यह भी प्रावधान किया कि आयोग निष्पादन मापदंडों के आधार पर वितरण लाइसेंस के लिए क्षेत्र-वार टैरिफ का निर्धारण कर सकता है जैसा कि आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

59 बिजली खरीद की लागत

59.1 वितरण लाइसेंसधारी को इसके स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली की लागत की वसूली करने या आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण लाइसेंसधारी की विद्युत खरीद योजना के आधार पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए अनुमोदित स्रोतों से खरीदे जाने की अनुमति दी जाएगी।

59.2 वितरण लाइसेंसधारी समय-समय पर अपने आदेशों में आयोग द्वारा निर्धारित किए जाने वाले फार्मूले और संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के कारण वृद्धिशील लागत की वसूली करेगा। आयोग एफपीपीसीए प्रभार की वसूली के लिए उपभोक्ताओं की श्रेणियों को भी निर्दिष्ट करेगा।

60 ट्रांसमिशन शुल्क

60.1 वितरण लाइसेंसधारी को इन विनियमों के अध्याय 5 के तहत आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार अंतरराज्यीय और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली तक पहुंच और उपयोग के लिए देय ट्रांसमिशन प्रभारों की वसूली करने की अनुमति दी जाएगी।

61 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय

61.1 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय की गणना इस विनियम के अनुसार की जाएगी।

61.2 ओएंडएम व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;
- ख) बीमा शुल्क सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय, यदि कोई हो; और
- ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

61.3 लाइसेंसधारी बहुवर्षीय टैरिफ याचिका के एक भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित लेखों, वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक का अनुमान, विवेकसम्मत जांच और आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाएगा।

61.4 नियंत्रण अवधि के एनवें वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा:

$$\text{ओएंडएम}_{\text{एन}} = (\text{आर एंड एम}_{\text{एन}} + \text{ईएमपी}_{\text{एन}} + \text{एएंडजी}_{\text{एन}}) \times (1 - \text{एक्स}_{\text{एन}}) + \text{अंतिम देयताएं}$$

जहां,

$$\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} = \text{के} \times \text{जीएफए}_{\text{एन}-1} \times (1 + \text{डब्ल्यूपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ईएमपी}_{\text{एन}} = (\text{ईएमपी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{जी}_{\text{एन}}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ए एंड जी}_{\text{एन}} = (\text{एएंडजी}_{\text{एन}-1}) \times (1 + \text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

'के' स्थिर (% में व्यक्त) है। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा लाइसेंसधारी की फाइलिंग के आधार पर बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में निर्धारित किया जाएगा, जिसमें मरम्मत और रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए की तुलना में अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्यय तथा आयोग द्वारा उपयुक्त विचार किया गया कोई अन्य कारक शामिल होगा;

सीपीआई^{मुद्रास्फीति} - उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि तत्काल पूर्व तीन (3) वर्ष की है;

डब्ल्यूपीआई^{मुद्रास्फीति} - थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में आधार वर्ष से तुरंत पूर्ववर्ती तीन (3) वर्षों की औसत वृद्धि है;

ईएमपी^{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का कर्मचारी व्यय है;

एएंडजी^{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंडएम^{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी का मरम्मत और रखरखाव व्यय;

जीएफए^{एन-1} - एन-1^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल अचल परिसंपत्ति;

एक्स^{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। एक्स^{एन} का मूल्य आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उपयुक्त माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

जी^{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए एक विकास कारक है। जी^{एन} का मूल्य आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए बहुवर्षीय टैरिफ आदेश में लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, पूर्व में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग द्वारा उचित माने गए किसी अन्य कारक के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि लाइसेंसधारी इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के अनुसार तीन (3) वर्षों से कम समय से कार्य कर रहा है, तो ओएंडएम व्यय का निर्धारण मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

61.5 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारी कर्मचारियों की अंतिम देनदारियों को लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत वास्तविक के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगा या बीमांकिक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा, वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित परिवर्तनों के कारण किसी भी भिन्नता को आयोग द्वारा विवेक सम्मत जांच के अधीन अलग से अनुमति दी जाएगी।

61.6 अनुमान के उद्देश्य के लिए, कारकों का समान मूल्य - सीपीआई^{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई^{मुद्रास्फीति} - का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आयोग उस वर्ष के लिए टूटिंग अप प्रक्रिया के दौरान कारकों - सीपीआई^{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई^{मुद्रास्फीति} - के वास्तविक मूल्यों पर विचार करेगा जिसके लिए टूटिंग अप किया जा रहा है और उस वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय का टूटिंग अप केवल मुद्रास्फीति की सीमा तक किया गया है।

बशर्ते कि टूटिंग अप के समय, मानक और वास्तविक ओएंडएम व्यय में भिन्नता को विनियम 15 के अनुसार निपटाया जाएगा।

62 एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार

62.1 वितरण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार एसएलडीसी शुल्क और एसएलडीसी को देय शुल्क वसूलने की अनुमति दी जाएगी।

63 अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान

63.1 आयोग पिछले वर्षों में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने की प्रवृत्ति के आधार पर, कुल राजस्व आवश्यकता में पास श्रू के रूप में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने की अनुमति दे सकता है जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगी:

63.2 बशर्ते कि आयोग कुल राजस्व आवश्यकता में बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण का टूट अप करेगा जो माफ किए गए विलंबित भुगतान प्रभार, यदि कोई हो, को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए वास्तविक अशोध्य ऋण पर आधारित होगा जो विवेक सम्मत जांच के अधीन होगा:

यह भी प्रावधान है कि अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान वितरण लाइसेंसधारी की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के 1% तक सीमित होगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी विशेष अशोध्य ऋण के बाद, राजस्व को ऐसे अशोध्य ऋण से प्राप्त किया जाता है, तो उसे उस वर्ष की गैर-टैरिफ आय के तहत एक गैर-नियंत्रणीय मद के रूप में शामिल किया जाएगा जिसमें ऐसा राजस्व प्राप्त होता है।

64 खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड

64.1 वितरण लाइसेंसधारी को वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा आपूर्ति व्यवसाय हेतु कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति दी जाएगी, जिसकी गणना इस प्रकार की जाती है:

- क) एक (1) महीने के लिए ओएंडएम व्यय; प्लस
 - ख) एक (1) महीने के लिए मरम्मत और रखरखाव खर्च के 40% पर रखरखाव कलपुर्जे; प्लस
 - ग) मौजूदा टैरिफ पर उपभोक्ताओं से अपेक्षित राजस्व के दो (2) महीनों के बराबर प्राप्ति; घटा
 - घ) एक (1) महीने के लिए बिजली खरीद लागत; प्लस
 - ङ) बैंक गारंटी के रूप में आयोजित सुरक्षा जमा को छोड़कर उपभोक्ताओं से अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत सुरक्षा जमा के रूप में रखी गई राशि:
- बशर्ते कि किसी भी वर्ष के लिए टूटिंग अप के समय, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पर फिर से गणना की जाएगी।

65 गैर-टैरिफ आय

65.1 आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली की खुदरा आपूर्ति से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ की गणना में कुल राजस्व आवश्यकता से काटी जाएगी:

बशर्ते वितरण लाइसेंसधारी टैरिफ निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा ब्यौरा आयोग को प्रस्तुत करेगा।

65.2 गैर-टैरिफ आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) भूमि या भवनों के किराए से आय;
- ख) निस्तारण मूल्य के 10% से अधिक के कबाड़ की बिक्री से आय;
- ग) सांविधिक निवेश से आय;
- घ) आपूर्तिकर्ताओं/ ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज;
- ङ) स्टाफ क्वार्टर से किराया;
- च) ठेकेदारों से किराया;
- छ) संपर्ककर्ताओं और अन्य लोगों से भाड़े के शुल्क से आय;
- ज) विज्ञापनों आदि से आय;
- झ) मीटर/ मीटरिंग उपकरण/ सर्विस लाइन किराया;
- ञ) सेवा शुल्क;
- ट) उपभोक्ता शुल्क;
- ठ) चोरी और ऊर्जा की चोरी के लिए वसूली;
- ड) बिलों के समय पर भुगतान के कारण प्राप्त छूट;

ढ) विविध प्रामियां;

ण) वार्षिक लेखों के अनुसार अनुदान, सब्सिडी आदि से आस्थगित आय;

त) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के अनुरूप इक्विटी पर प्रतिलाभ से अर्जित निवेश से अर्जित व्याज/ लाभांश को गैर-टैरिफ आय में शामिल नहीं किया जाएगा:

यह भी प्रावधान किया गया है कि मौजूदा विद्युत खरीद समझौतों या वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में आवंटित थोक आपूर्ति क्षमता का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 49 के अनुसार अन्य वितरण लाइसेंसधारियों या उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री से वितरण लाइसेंसधारी द्वारा अर्जित किसी भी आय को टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से वितरण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता से घटाया जाएगा। ऐसी कमी समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार की जाएगी।

66 क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण प्रामियां

66.1 वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्राप्त क्रॉस-सब्सिडी अधिभार की कटौती समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित दर पर वसूली के समय कुल राजस्व आवश्यकता से की जाएगी।

66.2 वितरण लाइसेंसधारी को समय-समय पर यथा संशोधित गोवा राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार प्राप्त अतिरिक्त अधिभार की आयोग द्वारा अनुमोदित दर पर वसूली के समय कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी।

67 वितरण हानि

67.1 वितरण लाइसेंसधारी बिजली की खुदरा आपूर्ति से होने वाली वितरण हानि के अनुमोदित स्तर की वसूली करेगा।

67.2 आयोग बहुवर्षीय टैरिफ आदेश के भाग के रूप में इन विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के लिए वितरण हानि हेतु अनुमान निर्धारित कर सकता है।

67.3 वितरण हानि के वास्तविक स्तर और अनुमोदित स्तर के बीच किसी भी भिन्नता से विनियम 15 के अनुसार टूटिंग अप प्रक्रिया के भाग के रूप में निपटा जाएगा।

68 टैरिफ का निर्धारण

68.1 आयोग उपभोक्ताओं को उनके लोड फैक्टर, पावर फैक्टर, वोल्टेज, किसी भी निर्धारित अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और जिस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की आवश्यकता है, को आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी अन्य कारक के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है।

68.2 आयोग प्रत्येक श्रेणी/ उप-श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आपूर्ति की लागत निर्धारित करने का प्रयास करेगा।

68.3 आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति की लागत के संबंध में उपभोक्ता श्रेणियों के बीच धीरे-धीरे क्रॉस-सब्सिडी को कम करने का प्रयास करेगा।

68.4 लाइसेंसधारी द्वारा टैरिफ प्रस्ताव और आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा:

क) सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ के अधिमानतः दो भाग होंगे, जिसमें नियत और परिवर्तनीय शुल्क शामिल होंगे।

ख) टैरिफ में नियत शुल्क वितरण लाइसेंसधारी द्वारा खर्च की गई वास्तविक नियत लागत को उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करेगा;

- ग) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए समग्र खुदरा आपूर्ति टैरिफ उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों के लिए आपूर्ति की लागत को उत्तरोत्तर प्रतिबिंबित करेगा;
- घ) आवासीय उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ के सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा;
- ङ) टैरिफ को इस तरह से स्थापित किया जाएगा कि यह किसी भी श्रेणी के उपभोक्ताओं को टैरिफ का झटका न दे।

अध्याय 8: विविध

69 आयोग की अंतर्निहित शक्तियों की रक्षा

69.1 इन विनियमों में कुछ भी आयोग की अंतर्निहित शक्ति को सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा ताकि ऐसे आवश्यक से न्याय समाप्त हो जाए या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोका जा सके।

69.2 इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अधिनियम के उपबंधों, किसी प्रक्रिया, जो इन विनियमों के किसी भी उपबंधों के साथ भिन्न है, यदि आयोग किसी मामले या वर्ग के मामलों की विशेष परिस्थितियों और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को ध्यान में रखते हुए, इसे आवश्यक या समीचीन या ऐसे मामले या श्रेणी के मामलों से निपटने से रोक नहीं देता।

69.3 इन विनियमों में कुछ भी स्पष्ट रूप से या निहितार्थ के द्वारा आयोग को किसी भी मामले से निपटने या उस अधिनियम के अंतर्गत किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं रोकेगा जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाए गए हैं, और आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कार्यों से इस तरीके से निपट सकता है जैसा वह उचित समझता है।

70 आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी करना

अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अध्यधीन, आयोग समय-समय पर विभिन्न मामलों पर अपनाई जाने वाली इन विनियमों और प्रक्रिया के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश और व्यवहार संबंधी निर्देश जारी कर सकता है।

71 संशोधन करने का अधिकार

71.1 आयोग किसी भी समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए इन विनियमों के किसी भी उपबंध में भिन्न, परिवर्तन, संशोधन या संशोधन कर सकता है।

72 कठिनाइयों को दूर करने की शक्तियां

72.1 यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकता है जो अधिनियम के उपबंधों के साथ असंगत न हों, जैसा कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकता है।

73 छूट देने का अधिकार

73.1 आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के आधार पर इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को अपने अनुसार या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष किए गए आवेदन पर छूट दे सकता है।

74 व्याख्या

74.1 यदि इन विनियमों के किसी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न उठता है तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./549/2020-21]

परिशिष्ट-1: मूल्यहास अनुसूची और परिसंपत्तियों की उपयोगी आयु**क) उत्पादन और ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां**

उत्पादन और ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन और मूल्यहास दर लागू सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट होंगी।

ख) वितरण संपत्ति

क्र.सं.	परिसंपत्ति वर्ग	उपयोगी आयु (वर्ष)	दर (%)
1	पूर्ण अधिकार सहित स्वामित्व वाली भूमि	असंख्य	0
2	पट्टे के तहत धारित भूमि		
(क)	भूमि में निवेश के लिए	पट्टे की अवधि या पट्टे के सौंपने पर समाप्त होने वाली अवधि	0
(ख)	समाशोधन साइट की लागत के लिए	साइट को साफ़ करने की तारीख में शेष पट्टे की अवधि	0
3	नई खरीदी गई परिसंपत्तियां		
(क)	किसी स्थायी स्वरूप का भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जिसका ऊपर उल्लेख नहीं किया गया है:		
(i)	कार्यालय और शोरूम	50	1.80
(ii)	लकड़ी के ढांचे जैसे अस्थायी निर्माण	5	18.00
(iii)	कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें	50	1.80
(iv)	अन्य	50	1.80
(ख)	ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर (कियोस्क) सबस्टेशन उपकरण और अन्य नियत उपकरण (संयंत्र आधार सहित)		
(i)	100 किलो वोल्ट एम्पेयर्स (केवीए) की रेटिंग वाले ट्रांसफॉर्मर (फाउंडेशन सहित)	25	3.60
(ii)	अन्य	25	3.60
(ग)	केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर	25	3.60
(घ)	लाइटिंग अरेस्टर्स:		
(i)	स्टेशन टाइप	25	3.60
(ii)	पोल टाइप	15	6.00
(iii)	सिंक्रोनस कंडेनसर	35	2.57
(ड.)	बैटरी	5	18.00
(च)	ज्वाइंट बॉक्स और डिस्कनेक्ट बॉक्स सहित भूमिगत केबल	35	2.57
(छ)	केबल डकट प्रणाली	50	1.80

क्र.सं.	परिसंपत्ति वर्ग	उपयोगी आयु (वर्ष)	दर (%)
(ज)	समर्थन सहित ओवरहेड लाइनें:		
(i)	66 केवी से अधिक नाममात्र वोल्टेज पर संचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें	35	2.57
(ii)	स्टील लाइनें 11 केवी से अधिक लेकिन 66 केवी से अधिक नहीं नाममात्र वोल्टेज पर काम करने का समर्थन करती है	25	3.60
(iii)	स्टील या प्रबलित कंक्रीट का समर्थन करता है पर लाइनें	25	3.60
(iv)	उपचारित लकड़ी समर्थित लाइनें	25	3.60
(झ)	मीटर		
	इलेक्ट्रो मैकेनिकल	15	6.00
	इलेक्ट्रॉनिक/स्मार्ट मीटर	10	9.00
(ञ)	स्व चालित वाहन	5	18.00
(ट)	एयर कंडीशनिंग संयंत्र :		
(i)	स्थिर	15	6.00
(ii)	सुवाह्य	5	18.00
(ठ)	अन्य		
(i)	कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग	15	6.00
(ii)	कार्यालय उपकरण	15	6.00
(iii)	फिटिंग और उपकरण सहित आंतरिक तारे	15	6.00
(iv)	स्ट्रीट लाइट फिटिंग	15	6.00
(ड)	भाड़े पर लिए गए उपकरण:		
(i)	मोटर के अलावा अन्य	5	18.00
(ii)	मोटर	15	6.00
(ढ)	संचार उपकरण		
(i)	रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली	15	6.00
(ii)	टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन	15	6.00
(ण)	एल.टी. उपकरण और सॉफ्टवेयर	6.67	15.00
(त)	सेकेंड हैंड खरीदी गई परिसंपत्तियां और अन्यथा अनुसूची में उपलब्ध नहीं कराई गई संपत्तियां	ऐसी उचित अवधि के रूप में आयोग प्रत्येक मामले में वर्तमान मालिक द्वारा अपने अधिग्रहण की प्रकृति, आयु और परिसंपत्तियों की शर्तों का निर्धारण करता है	

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For State of Goa and UTs)****NOTIFICATION**

Gurugram, the 22nd March, 2021

No. JERC: 28/2021.— In exercise of the powers conferred on it by sub-Section (2) of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi), after previous publications, hereby makes the following Regulations, namely:

Chapter 1: Preliminary**1. Short Title, Commencement and Extent**

- 1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2021.
- 1.2. These Regulations shall be applicable for determination of tariff in all matters covered under these Regulations from FY 2022-23 onwards and upto FY 2024-25, i.e. from April 1, 2022 to March 31, 2025, unless otherwise reviewed/modified/extended.
- 1.3. These Regulations shall extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

1. **“Accounting Statements”** shall mean for each Financial Year, the balance sheet, the profit and loss statement, the cash flow statement and the report of the statutory auditors together with notes thereto:

Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local authority;

Provided that once the Commission notifies the Regulations for submission of Regulatory Accounts, the applications for tariff determination and truing up shall be based on the Regulatory Account;

2. **“Act”** shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
3. **“Aggregate Revenue Requirement” or “ARR”** shall mean the annual revenue requirement comprising of allowable expenses and return on capital pertaining to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, for recovery through tariff, in accordance with these Regulations;
4. **“Allocation Statement”** shall mean for each Financial Year, a statement showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc. determined by apportionment or allocation between Distribution Wires Business and Retail Supply Business of a Distribution Licensee;
5. **“Allotted Transmission Capacity”** shall mean the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a Long-term Consumer or a Medium-term Consumer on the intra-State transmission system under the normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;

6. **“Applicant”** shall mean a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee who has made an application for determination of Aggregate Revenue Requirement and tariff in accordance with the Act and these Regulations and shall include a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee whose tariff is being determined by the Commission on Suo- motu basis or as part of a Truing-up exercise;
7. **“Area of Supply”** shall mean the area within which a Distribution Licensee is authorised by its licence to supply electricity;
8. **“Authority”** shall mean the Central Electricity Authority referred to in Section 70 of the Act;
9. **“Auxiliary Energy Consumption”** or **“AUX”** in relation to a period in case of a Generating Station means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the Generating Station, such as the equipment being used for the purpose of operating plant and machinery including switchyard of the Generating Station and the transformer losses within the Generating Station, expressed as a percentage of the sum of gross energy generated at the generator terminals of all the units of the Generating Station:

Provided that Auxiliary Energy Consumption shall not include energy consumed for supply of power to housing colony and other facilities at the Generating Station and the power consumed for construction works at the Generating Station:

Provided further that auxiliary energy consumption for compliance of revised emission standards shall be considered separately by the Commission;
10. **“Availability”** in relation to a transmission system for a given period shall mean the time in hours during the period the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated voltage expressed in percentage of total hours in the given period;
11. **“Bank Rate”** shall mean the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India from time to time;
12. **“Base Year”** shall mean the Year immediately preceding the first Year of the Control Period;
13. **“Bulk Power Transmission Agreement”** shall mean an executed Agreement that contains the terms and conditions under which a Transmission System User is entitled to access the intra-State transmission system of a Transmission Licensee;
14. **“Carrying Cost”** shall mean one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points;
15. **“Change in Law”** shall mean the occurrence of any of the following events:
 - a) enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law: or
 - b) adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law: or
 - c) change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application: or
 - d) change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent or clearances or approval or licence available or obtained for the project: or
 - e) coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for the Generating Station or the transmission system regulated under these Regulations;
16. **“Central Commission”** or **“CERC”** shall mean the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
17. **“Commission”** shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories referred to in Section 83 of the Act;
18. **“Control Period”** shall mean the period of three (3) Years from April 1, 2022 to March 31, 2025;

19. **“Central Transmission Utility” or “CTU”** shall mean any Government company which the Central Government may notify under sub-section (1) of Section 38 of the Act;
20. **“Cut-off Date”** shall mean the last day of the calendar month after thirty-six months from the date of commercial operation of the project:

Provided that the Cut-off Date may be extended by the Commission if it is proved on the basis of documentary evidence that the capitalisation could not be made within the Cut-off Date for reasons beyond the control of the project developer;

21. **“Consumer”** shall mean any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Licensee, the Government or such other person, as the case may be, but shall be restricted to such Consumers within the State;
22. **“Contracted Capacity”** shall mean the capacity in MW contracted by a Transmission System User;
23. **“Day”** shall mean a day starting at 00:00 hours and ending at 24:00 hours;
24. **“Date of Commercial Operation” or “COD”** in case of a transmission system shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 00:00 hours for which an element of the transmission system is in regular service after successful trial operation for transmitting electricity, and communication signal from sending end to receiving end:

Provided that where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular Generating Station, the Generating Company and Transmission Licensee shall endeavour to commission the Generating Station and the transmission system simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement:

Provided also that in case a transmission system or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of the delay in commissioning of the concerned Generating Station or in commissioning of the upstream or downstream transmission system, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the Date of Commercial Operation of such transmission system or an element thereof:

Provided further that the Date of Commercial Operation for a Generating Station shall be as defined in the prevalent CERC Tariff Regulations;

25. **“De-capitalisation”** shall mean reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the removal of assets as approved by the Commission;
26. **“Distribution Business”** shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for supplying electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
27. **“Distribution Licensee”** shall mean a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the Consumers in its Area of Supply;
28. **“Distribution Wires Business”** shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for wheeling of electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
29. **“Expected Revenue from Tariff and Charges”** shall mean the revenue estimated to accrue to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee from the regulated business at the prevailing tariff;
30. **“Electricity Supply Code”** shall mean the Electricity Supply Code specified under Section 50 of the Act;
31. **“Existing Project”** shall mean a project declared under commercial operation prior to April 1, 2022;

32. **“Force Majeure Event”** shall mean, with respect to any party, any event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which is not within the reasonable control of, and is not due to an act of omission or commission of that party and which, by the exercise of reasonable care and diligence, could not have been avoided, and without limiting the generality of the foregoing, would include the following events:
 - a) An Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last hundred Years: or
 - b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action: or
 - c) Industry-wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
33. **“Generation Company”** shall mean any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a Generating Station and for the purpose of these Regulations, shall exclude a company generating electricity from renewable sources;
34. **“Generating Station”** shall mean any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switchgear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a Generating Station, and any building used for housing the operating staff of a Generating Station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tail works, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station and for the purpose of these Regulations shall exclude stations generating electricity from renewable sources;
35. **“Grid”** shall mean the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations and generating plants;
36. **“Gross Station Heat Rate”** or **“GHR”** means the heat energy input in kCal required to generate one kWh of electrical energy at generator terminals of a thermal Generating Station;
37. **“Integrated Utility”** means the Department of Power in the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry, in its present form or the successor entities performing more than one of the functions of generation, transmission and distribution after restructuring thereof;
38. **“Licensed Business”** shall mean as defined in Regulation 2 of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009 as amended from time to time;
39. **“Licensee”** shall mean a person who has been granted licence under Section 14 of the Act and for the purpose of these Regulations shall also include an Integrated Utility;
40. **“MCLR”** shall mean One Year (1) State Bank of India Marginal Cost of Funds based Lending Rate;
41. **“Mid-term Review”** shall mean a review to be undertaken in accordance with the Regulation 11 of these Regulations;
42. **“Month”** shall mean a calendar month as per the Gregorian calendar;
43. **“New Project”** shall mean a project declared under commercial operation on or after April 1, 2022;
44. **“Non-Tariff Income”** shall mean income relating to the Licensed Business other than from tariff, excluding any income from Other Business and, in case of the Retail Supply Business of a Distribution Licensee, excluding income from wheeling and receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge on charges of wheeling;

45. **“Operation and Maintenance expenses”** or **“O&M expenses”** in relation to a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall mean the expenditure incurred on operation and maintenance of the system by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads etc.;
 46. **“Original Project Cost”** means the capital expenditure incurred by the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, within the original scope of the project up to the Cut-off Date as admitted by the Commission;
 47. **“Other Business”** shall mean as defined in Regulation 2(i)(f) of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time;
 48. **“Prudence Check”** shall mean scrutiny of the reasonableness of expenditure incurred or proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff;
 49. **“Rated Voltage”** shall mean the manufacturer’s design voltage at which the transmission system is designed to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time being, in consultation with Transmission System Users;
 50. **“Retail Supply Business”** shall mean the business of sale of electricity by a Distribution Licensee to its Consumers in accordance with the terms of its license;
 51. **“State”** shall mean the State of Goa, and includes the Union Territories under the jurisdiction of JERC;
 52. **“State Grid Code”** shall mean the State Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
 53. **“State Load Despatch Centre”** or **“SLDC”** shall mean the Centre established under sub-section (1) of Section 31 of the Act;
 54. **“Transmission Licensee”** shall mean a Licensee authorised to establish or operate transmission lines;
 55. **“Transmission System User”** shall mean the Distribution Licensee or Open Access User, as the case may be, who uses the intra-State transmission network for the purpose of transmission of electricity;
 56. **“Useful life”** in relation to a unit of a transmission system and distribution system from the Date of Commercial Operation shall be as defined in Appendix I of these Regulations;
 57. **“Working Day”** shall mean a Day on which banks are open for business;
 58. **“Year”** or **“Financial Year”** shall mean a Financial Year (FY), beginning from 1st April of calendar Year and ending on 31st March of the next calendar Year.
- 2.2 Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act or Grid Code or CERC Tariff Regulations or State Grid Code shall have the meanings generally assigned to them in the electricity industry.
- 2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
- a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;
 - b) The terms “include” or “including” shall be deemed to be followed by “but not limited to” regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import;

- c) References herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations or as may be amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
- d) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with the text below for the purpose of interpretation of these Regulations;
- e) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
- f) In case of inconsistency between any provision of these Regulations and any other Regulations or Orders passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall prevail.

3. Scope of Regulation and extent of application

3.1 The Commission shall determine tariff within the Multi Year Tariff framework, for all matters for which the Commission has jurisdiction under the Act, including in the following cases:

- a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:

Provided that where the Commission believes that there is a shortage of supply of electricity exists, it may fix the minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into between a Generating Company and a Distribution Licensee or between Distribution Licensees, for a period not exceeding one year to ensure reasonable prices of electricity;

- b) Intra-State transmission of electricity;
- c) Intra-State wheeling of electricity;
- d) Retail supply of electricity:

Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution Licensees, the Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix only the maximum ceiling of tariff for retail sale of electricity:

Provided further that where the Commission has allowed Open Access to certain Consumers under sub-section (2) of Section 42 of the Act, such Consumers, notwithstanding the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62 of the Act, may enter into an agreement with any person for supply or purchase of electricity on such terms and conditions (including tariff) as may be agreed between them. Such Open Access shall be regulated by provisions of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time.

3.2 In accordance with the principles laid out in the Regulation 49, Regulation 51 and Regulation 58, the Commission shall determine Aggregate Revenue Requirement for:

- a) Distribution Wires Business; and
- b) Retail Supply Business.

3.3 The Distribution Licensee shall file an application containing separate details for determination of Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business and Retail Supply Business, in accordance with Regulation 49 specified in these Regulations.

3.4 The wheeling charges shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Distribution Wires Business.

3.5 The Retail Supply tariff for retail sale of electricity shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Retail Supply Business.

3.6 The Commission shall also determine Cross-Subsidy Surcharge in addition to the charges for wheeling under the first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity

and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

- 3.7 The Commission shall also determine Additional Surcharge under sub-section (4) of Section 42 of the Act, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.
- 3.8 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government pursuant to Section 63 of the Act.

4. Norms of operation to be ceiling norms

- 4.1 For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the ceiling norms and this shall not preclude the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, and the beneficiaries from accepting improved norms of operation as determined by the Commission and such improved norms shall be applicable for determination of tariff.

Chapter 2: General Principles

5. Guiding Principles for MYT Framework

- 5.1 The Commission shall determine the tariff for matters covered under clauses (a), (b), (c) and (d) of Regulation 3.1, under a Multi Year Tariff framework with effect from April 1, 2022.
- 5.2 The Multi Year Tariff framework for determination of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges for Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall include the following:

- a) Business Plan for the Licensee, for the entire Control Period as submitted to the Commission for approval, prior to the start of the Control Period;
- b) A detailed Multi Year tariff application comprising of the year-wise forecast of Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period and determination of Expected Revenue from Tariff and Charges for the first Year of the Control Period submitted by the Applicant, in formats specified by the Commission from time to time:

Provided that the performance parameters, whose trajectories have been specified in these Regulations or the Business Plan or the Multi Year Tariff Order approved by the Commission, shall form the basis for projection of these performance parameters in the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period:

- c) Determination of year-wise Aggregate Revenue Requirement by the Commission for the entire Control Period and the tariff for the first Year of the Control Period for the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business;
- d) Annual review of performance which shall be conducted vis-à-vis the approved forecast and categorisation of variations in performance into controllable and uncontrollable factors;
- e) Annual determination of tariff for the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business, for each Financial Year within the Control Period, based on the approved forecast, the annual performance review, Mid-term Review and truing up exercise;
- f) Truing up of previous Year/(s) expenses and revenue by the Commission based on audited accounts vis-à-vis the approved forecast and categorisation of variation in performance as those caused by factors within the control of the Applicant (controllable factors) and those caused by factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors);
- g) The mechanism for pass-through of approved gains or losses on account of uncontrollable factors as specified by the Commission in these Regulations;
- h) The mechanism for sharing of approved gains or losses on account of controllable factors as specified by the Commission in these Regulations.

6. Values for Base Year

6.1 The values for the Base Year of the Control Period shall be determined on the basis of the audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, and other factors considered relevant by the Commission:

Provided that, in absence of availability of audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, the Commission may benchmark the parameters with other similar utilities to establish the values for Base Year:

Provided further that the Commission may change the values for Base Year and consequently the trajectory of parameters for Control Period, considering the actual figures from audited accounts.

6.2 The Commission may revisit the performance targets for the Control Period during the Mid-term Review, carried out in accordance with the Regulation 11.

7. Segregation of Retail Supply and Distribution Wires Business

7.1 The Distribution Licensee shall segregate the accounts of the Licensed Business into Distribution Wires Business and Retail Supply Business. The ARR for Distribution Wires Business shall be used to determine wheeling charges. The ARR for Retail Supply Business, which shall include the ARR for Distribution Wires Business, in accordance with Regulation 58, shall be used to determine retail supply tariff.

7.2 For such period until accounts are segregated, the Licensees shall use the Allocation Statement provided in the Regulation 49 to apportion costs and revenues to respective businesses.

8 Business Plan

8.1 The Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file a petition, duly approved by the competent authority, for approval of Business Plan by the Commission for the entire Control Period, latest by May 15, 2021:

Provided that the Generation Company shall not be required to file a Business Plan for the Control Period.

8.2 The Business Plan filed by the Distribution Licensee shall contain separate sections on Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

8.3 The Business Plan filed by the **Transmission Licensee** shall inter-alia contain:

- a) Projections for the growth of load in the transmission network;
- b) **Capital Investment Plan** for each Year of the Control Period commensurate with load growth, transmission loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
- c) **Capital structure** of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;
- d) **Performance targets** items such as transmission loss, availability of transmission system, transformer failure rate, and any other parameters for quality of supply for each year of the Control Period, consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee;
- e) **Projections for number of employees** during each Year of the Control Period based on proposed recruitments and retirement;
- f) **Proposals in respect of income from Other Business** for each Year of the Control Period.

8.4 The Business Plan filed by **Distribution Licensee** shall inter-alia contain:

- a) **Capital Investment Plan** for each Year of the Control Period commensurate with load growth, distribution loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
- b) **Capital Structure** of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;

- c) **Sales Forecast** for each Consumer category and sub-categories for each Year of the Control Period in accordance with Regulation 8.6;
- d) **Power Procurement Plan** based on the Sales Forecast and distribution loss trajectory for each Year of the Control Period in accordance with the Regulation 8.7;
- e) **Targets** for distribution loss for each Year of the Control Period consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Licensee;
- f) **Projections for number of employees** during each Year of the Control Period based on proposed recruitments and retirement;
- g) **Proposals in respect of income from Other Business** for each Year of the Control Period.

8.5 Capital Investment Plan

- a) The Capital Investment Plan to be submitted as part of Business Plan shall include details of New Projects planned during the Control Period, purpose of investment, capital structure, implementation schedule, quarter-wise capital expenditure and capitalisation schedule, financing plan, cost-benefit analysis, improvement in operational efficiency envisaged in the Control Period owing to proposed investment and such details for ongoing projects that will spill over into the Control Period under review along with justification;
- b) The Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee shall be in conformity with the plans made by the Authority/Central Transmission Utility and with the Capital Investment Plan of the Distribution Licensee;
- c) During the Annual Performance Review, the Commission shall monitor the progress of the actual capital expenditure incurred by the Licensee vis-à-vis the approved capital expenditure. The Licensees shall submit the actual capital expenditure incurred along with the annual performance review, true-up and determination of tariff filing;
- d) The truing up of the capital cost incurred for the new projects and additional capital cost for the existing projects shall be done on yearly basis based on the actual capital cost incurred.:

Provided if the actual capital cost incurred on year to year basis is lesser than the capital cost approved for determination of tariff by the Commission on the basis of the projected capital cost as on the date of commercial operation or on the basis of the projected additional capital cost, by twenty (20) percent or more, the excess tariff/revenue realized corresponding to excess capital cost as approved by the Commission, along with interest at 1.10 times of the Carrying Cost, as prevalent on the first day of April of the respective financial year, shall be adjusted from the annual revenue requirement of the respective year at the time of true-up.

Provided if the actual capital cost incurred on year to year basis is higher than the capital cost approved for determination of tariff by the Commission on the basis of the projected capital cost as on the date of commercial operation or on the basis of the projected additional capital cost, by twenty (20) percent or more, the shortfall in tariff/revenue realized corresponding to excess capital cost as incurred by the licensee vis-à-vis approved by the Commission, along with interest at 0.9 times of the Carrying Cost, as prevalent on the first day of April of the respective financial year, shall be allowed in the annual revenue requirement of the respective year at the time of true-up.

- e) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved in the Capital Investment Plan, the Licensee shall submit an application containing all relevant information along with reasons justifying emergency nature of the proposed work seeking approval of the Commission:

Provided that in case capital expenditure is required for emergency work or unforeseen situation to mitigate threat to life and property and if prior intimation thereof to the Commission shall cause any irreparable loss or injury, the Licensee may undertake that capital expenditure and submit the details along with adequate justification for post facto approval of the Commission:

Provided further that for the purpose of Regulation 8.5(e) above, such approved capital expenditure shall be treated as a part of both the actual capital expenditure incurred by the Licensee and approved capital expenditure by the Commission;

- f) The Licensee shall **submit a report for every quarter** detailing the progress of the capital expenditure and capitalisation undertaken against that proposed in the Capital Investment Plan, on or before the last Day of the month succeeding the respective quarter for review by the Commission.

8.6 Sales Forecast

- a) The Distribution Licensee shall forecast sales for each Consumer category and sub-categories, at different voltage levels, for each Year of the Control Period in their Business Plan filings, for the Commission's review and approval;
- b) The forecast shall be based on the actual demand of electricity in previous Years, anticipated growth in demand in coming Years, expected growth in the number of Consumers, load growth, changes in the pattern of consumption, target distribution losses and other relevant factors;
- c) The Licensee shall indicate separately the sale of electricity to traders or another Licensee and category wise sales to Open Access Consumers.

8.7 Power Procurement Plan

- a) The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the Commission for approval as a part of Business Plan:

Provided further that such power procurement plan may include long-term (~5 to 25 years), medium-term (~1 to 5 years) and short-term (up to 1 year) sources of power procurement, in accordance with these Regulations;

- b) The power procurement plan of the Distribution Licensee shall comprise of the following:
- (i) A quantitative forecast of the unrestricted base load and peak load for electricity within its Area of Supply;
 - (ii) An estimate of the quantity of electricity supply from the identified sources of power purchase, including own generation, if any;
 - (iii) Measures proposed for energy conservation, energy efficiency, and demand side management;
 - (iv) An estimate of availability of power to meet the base load and peak load requirement:
Provided that such estimate of demand and supply shall be on month-wise basis in Megawatt (MW) as well as expressed in Million Units (MU);
 - (v) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations of the Commission;
 - (vi) The requirement for new sources of power procurement, including augmentation of own generation capacity, if any, and identified new sources of supply, based on (i) to (v) above;
 - (vii) The sources of power, quantity and cost estimates for such procurement:

Provided that the forecast or estimates contained in the long-term procurement plan shall be separately stated for peak and off-peak periods, in terms of quantities of power to be procured (in MU) and maximum demand (in MW):

Provided that the forecast or estimates for the Control Period shall be prepared for each month over the Control Period:

Provided further that the long-term procurement plan shall be a cost-effective plan based on available information regarding costs of various sources of supply;

- c) The forecast or estimate shall be prepared using forecasting techniques based on past data, sales forecast, impact of loss reduction initiatives, improvement in Generating Station Plant Load Factors, overall economic growth, consumption growth of electricity-intensive sectors, advent of competition in the electricity sector and other relevant factors;
- d) Where the Commission has specified a percentage of the total consumption of electricity in the area of a Distribution Licensee to be purchased from co-generation or renewable sources of energy including solar power, the power procurement plan shall include the plan for procurement from such sources at least up to the specified level;
- e) The Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of preparation of the power procurement plan, and shall forward a copy of its power procurement plan to the State Transmission Utility to ensure consistency of such plan with the transmission system plan;
- f) Every long-term/medium-term agreement or arrangement for power procurement, including on a Standby basis, by a Distribution Licensee from a Generating Company or Licensee or from another source of supply, and any change to an existing agreement or arrangement shall come into effect only with the prior approval of the Commission:

Provided that the prior approval of the Commission shall not be required for purchase of power from Renewable Energy sources at the generic/preferential tariff determined by the Commission for meeting its Renewable Purchase Obligation (RPO).

- g) The Distribution Licensee may, as a result of additional information not previously known or available to it at the time of submission of the procurement plan under these Regulations, apply for modification in the power procurement plan for the remaining Control Period, as part of its Petition for Mid-term Review;
- h) The Commission may, as a result of additional information not previously known or available to the Commission at the time of approval of the procurement plan, if it deems appropriate, Suo motu or on a Petition filed by the Distribution Licensee, modify the procurement plan of the Distribution Licensee for the remaining Control Period, as part of the Mid-term Review;
- i) The Distribution Licensee may undertake additional power procurement during the year, over and above the power procurement plan for the Control Period approved by the Commission, where there has been an unanticipated increase in the demand for electricity or a shortfall or failure in the supply of electricity from any approved source of supply during the Year or when the sourcing of power from existing tied-up sources becomes costlier than other available alternative sources, the Distribution Licensee may enter into additional agreement or arrangement for procurement of power:

Provided that any variation, during the first or second block of six months of a Year, in the quantum or cost of power procured, including from a source other than a previously approved source, that is expected to be in excess of five per cent of that approved by the Commission, shall require its prior approval:

Provided that the five per cent limit shall not apply to variation in the cost of power procured on account of changes in the price of fuel for own generation or the fixed or variable cost of power purchase that is allowed to be recovered through FPPCA mechanism;

- j) The Distribution Licensee may enter into a short-term arrangement or agreement for procurement of power without the prior approval of the Commission when faced with emergency conditions that threaten the stability of the distribution system:

Provided that within thirty days from the date of entering into an agreement or arrangement for short-term power procurement for which prior approval is not required, the Distribution Licensee shall submit to the Commission its details, including the quantum, Tariff computations, duration, supplier particulars, method of supplier selection and such other details as the Commission may require so to assess that the conditions specified in this Regulation have been complied with;

- k) Where the Commission has reasonable grounds to believe that the agreement or arrangement entered into by the Distribution Licensee does not meet the criteria specified in Regulations 8.7(i) and 8.7(j), it may disallow any increase in the total cost of power procurement over the approved level arising therefrom or any loss incurred by the Distribution Licensee as a result, from being passed through to consumers.

9 Multi Year Tariff Application

- 9.1 The Applicant shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement for each year of the Control Period and tariff proposal for the first Year of the Control Period, in a manner as provided in these Regulations and in formats specified by the Commission from time to time. The application shall be accompanied by such fee payable, as may be specified by the Commission in the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time, by November 30, 2021:

Provided that the application shall also be accompanied by the true-up Petition based on the latest available audited accounts and the Annual Performance Review for the current Year based on the actual performance during the first six Months of the Year and estimates for the subsequent six Months.

- 9.2 The Applicant shall develop the forecast of Aggregate Revenue Requirement using the assumptions relating to the behaviour of individual variables that comprise the Aggregate Revenue Requirement during each year of the Control Period, including inter-alia detailed category-wise sales and demand projections, power procurement plan, Capital Investment Plan, trajectories of parameters specified in these Regulations and Business Plan, in accordance with guidelines and formats, as may be specified by the Commission from time to time.
- 9.3 The Applicant shall develop the forecast of Expected Revenue from Tariff and Charges based on the following:
- a) In the case of a Generating Company, estimates of the quantum of electricity to be generated by each unit/station for ensuing Financial Year within the Control Period;
 - b) In the case of a Transmission Licensee, estimates of the transmission capacity allocated to Transmission System Users for ensuing Financial Year within the Control Period;
 - c) In the case of a Distribution Licensee, estimates of the quantum of electricity to be supplied to Consumers and to be wheeled on behalf of distribution system users for the ensuing Financial Year within the Control Period;
 - d) Prevailing tariff as on the date of making the application.
 - e) Proposed Tariff

- 9.4 Based on the forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges for the first Year of the Control Period, the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business, shall propose the tariff for the first Year of Control Period:

Provided that the tariff proposed by Distribution Licensee shall be in accordance with Regulation 68 and these Regulations.

- 9.5 The Applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and/or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.
- 9.6 On receipt of the application, the Commission shall either:

- a) issue an Order approving the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period and the tariff for the first Year of the Control Period; or
- b) reject the application for reasons to be recorded in writing, as the Commission may deem appropriate:

Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

10 Trajectory for Specific Variables

- 10.1 The Commission, while approving the Business Plan and/or Multi Year Tariff Petition, may stipulate a trajectory for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption, Station Heat Rate, O&M expenses, T&D losses etc.:

Provided that the utilities shall adhere to the norms as specified in the Order on Multi Year tariff petition:

Provided further that the Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, may seek a review at the time of Mid-term Review of Aggregate Revenue Requirement for the balance Control Period.

11 Mid-term Review

- 11.1 A Petition for Mid-term Review may be filed by the licensees along with the application for true-up of the First year, i.e., FY 2022-23 and tariff determination for the Third Year of the Control Period, i.e., FY 2024-25:

Provided that the Petition shall include information in such form as may be stipulated by the Commission, together with the Accounting Statements, extracts of books of account and other details, as it may be required to assess the reasons for and extent of any difference in operational and financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and expected revenue from Tariff and charges.

- 11.2 The scope of the Mid-term Review shall be a comparison of the actual operational and financial performance vis-à-vis the approved forecast for the first three years of the Control Period; and revised forecast of Aggregate Revenue Requirement, expected revenue from existing Tariff, expected revenue gap, and proposed trajectory for specific variable for the fourth and fifth year of the Control Period:

Provided that as part of the Mid-term Review, the Commission may inter-alia modify the category-wise sales, power purchase expenses, O&M expenses, capital expenditure related expenses, as considered appropriate based on the data made available for the first three years of the Control Period:

Provided further that necessary justification for the modifications made in the Mid-term Review shall be elaborated in the Mid-term Review Order.

- 11.3 Upon completion of the Review under Regulation 11.2, the Commission shall attribute any variations or expected variations in performance, for variables specified under Regulation 13, to factors within the control of the Petitioner (controllable factors) or to factors beyond its control (uncontrollable factors):

Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those specified under Regulation 13.1, shall not ordinarily be reviewed by the Commission during the Control Period and shall be attributed entirely to controllable factors:

Provided further that, where the Petitioner believes, for any variable not specified under Regulation 13.1, that there is a material variation or expected variation in performance for any year on account of uncontrollable factors, it may apply to the Commission for inclusion of such variable.

12 Annual Performance Review, Truing-up and tariff determination during the Control Period

- 12.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall be subject to annual performance review and truing up of expenses and revenue during the Control Period in accordance with these Regulations.

- 12.2 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an application for the annual performance review of the current year, truing up of the previous Year or the Year for which the audited accounts are available and determination of tariff for the ensuing Year on or before 30th November of each Year, in formats specified by the Commission from time to time :

Provided that the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, shall submit to the Commission information in such form as may be specified by the Commission, together with the audited accounts, extracts of books of account and such other details as the Commission may require to assess the reasons for and extent of any variation in financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges.

12.3 The scope of the annual performance review, truing up and tariff determination shall be a comparison of the performance of the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee with the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges and shall comprise of the following:

- a) **True-up:** a comparison of the audited financial and actual operational performance of the Applicant for the Financial Year for which the true up is being carried out with the approved forecast for such previous Financial Year, subject to the prudence check;
- b) **Annual Performance Review:** a comparison of the revised estimates of performance targets of the Applicant for the current Financial Year with the approved forecast in the Tariff Order corresponding to the Control Period for the current Financial Year subject to prudence check;
- c) **Tariff determination** for the ensuing Year of the Control Period based on the revised forecast of the Aggregate Revenue Requirement for the Year;
- d) Review of compliance with directives issued by the Commission from time to time;
- e) Other relevant details, if any.

12.4 Upon completion of the exercise, the Commission shall attribute any variations or expected variations in performance for variables specified under Regulation 13 below, to factors within the control of the Applicant (controllable factors) or to factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors):

Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those specified under Regulation 13.1 below shall not ordinarily be reviewed by the Commission during the Control Period and shall be attributed entirely to controllable factors:

Provided further that, where the Petitioner believes, for any variable not specified under Regulation 13.1, that there is a material variation or expected variation in performance for any year on account of uncontrollable factors, it may apply to the Commission for inclusion of such variable.

12.5 Upon completion of the exercise, the Commission shall pass an order recording:

- a) Components of approved cost pertaining to the uncontrollable factors, which were not recovered during the previous Year, to be passed through in tariff as per Regulation 14 of these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

- b) Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors, and the amount of such gains or such losses that may be shared in accordance with Regulation 15 of these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

- c) Carrying Cost shall be allowed for a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee on the amount of revenue gap for the period from the date on which such gap has become due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is addressed, on the basis of actual rate of loan taken by the Licensee to fund the deficit in revenue:

Provided that Carrying Cost on the amount of revenue gap shall be allowed subject to prudence check and submission of documentary evidence for having incurred the carrying cost in the years prior to the year in which the revenue gap is addressed:

Provided also that if no loan has been taken to fund revenue deficit, the Commission shall allow Carrying Cost on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR /any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points;

Provided further that in case of revenue surplus, the Commission shall charge the Licensee a Carrying Cost from the date on which such surplus has become due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is addressed on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points.

- d) Revision of estimates and tariff for the ensuing Financial Year.

13 Uncontrollable and Controllable factors

13.1 For the purpose of these Regulations, the term “uncontrollable factors” for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the following factors, which were beyond the control of the Licensee, and could not be mitigated by the Licensee:

- a) Force Majeure events;
- b) Change in Law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, State Government or Commission;
- c) Variation in the number or mix of Consumers or quantities of electricity supplied to Consumers;
- d) Interstate Transmission loss;
- e) Variation in the cost of power purchase due to variation in the rate of power purchase from approved sources, subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement approved by the Commission;
- f) Variation in fuel cost;
- g) Change in power purchase mix;
- h) Inflation;
- i) Transmission Charges for a Distribution Licensee;
- j) Variation in market interest rates for long-term loans;
- k) Employee expenses limited to one time payment owing requirements of a pay commission and terminal liability of employees;
- l) Taxes and Statutory levies;
- m) Taxes on income;
- n) Income from the realisation of bad debts written off;

Provided that where the Applicant believes, for any variable not specified above, that there is a material variation or expected variation in performance for any Financial Year on account of uncontrollable factors, such Applicant may apply to the Commission for inclusion of such variable at the Commission’s discretion, under this Regulation for such Financial Year:

Provided further that the uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

13.2 For the purpose of these Regulations, the term “controllable factors” for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the factors which were within the control of the Licensee, shall inter-alia include:

- a) Variations in capitalisation on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;

- b) Variation in Interest and Finance Charges, Return on Equity, and Depreciation on account of variation in capitalisation, as specified in clause (a) above;
- c) Variations in technical and commercial losses of Distribution Licensee;
- d) Intrastate Transmission loss for transmission licensee;
- e) Availability of transmission system;
- f) Variations in performance parameters;
- g) Failure to meet the standards specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UTs (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulation, 2015, as amended from time to time;
- h) Variations in labour productivity;
- i) Variation in O&M Expenses, except to the extent of inflation;
- j) Bad debts written off, in accordance with the provisions of Regulation 63:

Provided further that the controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

14 Mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors

- 14.1 Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of uncontrollable factors shall be pass-through as an adjustment in the tariff of the Transmission Licensee or Distribution Licensee over such period as may be specified in the Order of the Commission passed under these Regulations:

Provided that the mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

- 14.2 The Transmission Licensee or Distribution Licensee shall submit such details of the variation between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in the specified format to the Commission, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.

15 Mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors

- 15.1 Approved aggregate gain to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be shared equally between Licensee and Consumers:
- 15.2 Approved aggregate loss, if any to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be on account of the Licensee, and shall not be passed to the Consumers.
- 15.3 The mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

16 Determination of Tariff

- 16.1 The proceedings to be held by the Commission for determination of tariff shall be in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time.
- 16.2 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall at all times have the authority, either on Suo motu basis or on a Petition filed by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, to determine the tariff, including terms and conditions thereof:

Provided that such determination of tariff may be pursuant to an agreement or arrangement or otherwise whether or not previously approved by the Commission and entered into at any time before or after the applicability of these Regulations.

- 16.3 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government:

Provided that the Applicant shall provide such information as the Commission may require for satisfying itself that the guidelines issued by the Central Government in this regard have been duly followed.

16.4 Determination of Tariff for an existing Generation Station:

- a) Where the Commission has, at any time prior to the date of effectiveness of these Regulations, approved a power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee or has adopted the tariff contained therein for supply of electricity from an existing generating unit/station, the tariff for supply of electricity by the Generating Company to the Distribution Licensee shall be in accordance with tariff mentioned in such power purchase agreement or arrangement for such period as may be so approved or adopted by the Commission;
- b) Where, as on the date of effectiveness of these Regulations, the power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee for supply of electricity from an existing Generating Station has not been approved by the Commission or the tariff contained therein has not been adopted by the Commission or where there is no power purchase agreement or arrangement, the supply of electricity by such Generating Company to such Distribution Licensee after the date of effectiveness of these Regulations shall be in accordance with a power purchase agreement approved by the Commission:

Provided that an application for approval of such power purchase agreement or arrangement shall be made by the Distribution Licensee to the Commission within a period of three (3) months from the date of notification of these Regulations:

Provided further that the supply of electricity shall be allowed to continue under the present agreement or arrangement, as the case may be, until such time as the Commission approves of such power purchase agreement and shall be discontinued forthwith if the Commission rejects, for reasons recorded in writing, such power purchase agreement or arrangement.

16.5 Determination of Tariff for a new Generating Station:

- a) The tariff for the supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee from a new generating unit/station shall be in accordance with tariff as per power purchase agreement approved by the Commission.

16.6 Determination of Tariff for Transmission, Distribution Wires Business and Retail Supply Business:

- a) The Commission shall, based on an application made by the Transmission or Distribution Licensees in accordance with the Regulations 17 determine the tariff for:
- (i) Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 5 of these Regulations;
 - (ii) Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 6 of these Regulations; and
 - (iii) Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 7 of these Regulations.

17 Filing Procedure

- 17.1 The Applicant shall provide, as part of its Petition to the Commission, in such formats as specified by the Commission from time to time, full details of its calculation of the Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges, and thereafter, shall furnish such further information or particulars or documents as the Commission may reasonably require to assess such calculation:

Provided that the Petition shall be accompanied by, where relevant, tariff and charges revision proposal showing category-wise tariff for recovery of Aggregate Revenue Requirement for the respective Year of the Control Period:

Provided further that the Commission may specify additional/alternative formats for details to be submitted by the Applicant, from time to time, as it may reasonably require for assessing the Aggregate Revenue Requirement and for determining the tariff.

- 17.2 Upon receipt of a complete Petition accompanied by all requisite information, particulars and documents in compliance with all the requirements specified in these Regulations, the Petition shall be deemed to be received and the Commission shall intimate to the Applicant regarding the acceptance of Petition.
- 17.3 The Petition shall be supported by an affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.
- 17.4 The Applicant shall, within seven (7) Days after acceptance of the Petition by the Commission, publish a notice of its Petition in at least two English and two Vernacular language daily newspapers having wide circulation in the relevant area:

Provided that the notice of the Petition shall include the following parameters:

- i. Category wise Quantum of Sales;
- ii. Power Purchase Quantum and Cost;
- iii. Distribution Losses;
- iv. Auxiliary Consumption;
- v. Transmission/Generation System Availability;
- vi. Annual Revenue Requirement;
- vii. Annual Tariff Proposal;
- viii. Any other parameter as notified by the Commission from time to time;

Provided that the Applicant shall make available a hard copy of the complete Petition to any person, at such locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Applicant shall also provide on its internet website, in text searchable format or in downloadable spreadsheet format furnishing detailed computations, the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that the web link to such information mentioned shall be easily accessible, archived for downloading and be prominently displayed on the Applicant's internet website:

Provided further that the Applicant may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents, which are confidential in nature.

- 17.5 The suggestions and objections, if any, on the proposal for determination of tariff, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission (for the State of Goa and Union Territories), by any person within the timeline specified in the notice so published, with a copy to the Applicant.
- 17.6 The Applicant shall within seven (7) Days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file copies of the newspapers wherein the notice has been published.
- 17.7 The Applicant shall file its comments on the suggestions and objections, if any, received in response to its application within the time limit specified by the Commission.

18 Tariff Order

18.1 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) Days from the date of acceptance of the complete Petition, subject to petitioner providing information subsequently sought by the Commission in a timely manner and after considering all suggestions and objections received from the various stakeholders:

- a) issue a Tariff Order; or
- b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the Act and Regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force:

Provided that an Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

18.2 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

18.3 The Applicant shall publish the tariff approved by the Commission in at least two English and two vernacular language daily newspapers having wide circulation in the State of location of Generating Company or Transmission Licensee or Area of Supply of Distribution Licensee, as the case may be, display the approved tariff schedule on its internet website, and make available for sale a booklet containing such tariff to any person upon payment of reasonable reproduction charges.

19 Adherence to Tariff Order

19.1 No tariff or part of any tariff may ordinarily be amended more frequently than once in a Year, except in respect of any changes expressly permitted under the terms of any fuel surcharge formula as may be specified.

19.2 If any Generating Company or Licensee recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the Commission under Section 62 of the Act and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be payable to the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the Bank Rate prevailing during the relevant period, without prejudice to any other liability to which such Generating Company or Licensee may be subject:

Provided that such interest payable to any party shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided further that the Licensee shall maintain separate details of such interest paid or payable by it, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

20 Annual determination of tariff

20.1 The Commission shall determine the tariff of a Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee covered under a Multi Year Tariff framework for each Year during the Control Period, in accordance with timelines specified in Regulation 18, having regard to the following:

- a) The approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges of the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee for such Financial Year, including modifications approved at the time of Mid-term Review, if any; and
- b) Approved gains and losses, including the incentive available, to be passed through in tariff, following the truing up of previous Year.

21 Subsidy Mechanism

21.1 If the Government requires to grant any subsidy to any Consumer or class of Consumers in the tariff determined by the Commission, the Government shall, notwithstanding any direction which may be given under Section 108 of the Act, pay in advance the amount to compensate the Distribution Licensee/person affected by the grant of subsidy, as a condition for the Licensee or any other person concerned to implement the subsidy provided for by the Government, in the manner specified in these Regulations:

Provided that no such direction of the Government shall be operative if the payment is not made in accordance with the provisions contained in these Regulations, and the tariff fixed by the Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard.

Chapter 3: Financial Principles

22 Financial Principles for a Generating Company

- 22.1 The Capital Cost for a Generating Company shall be determined by the Commission, guided by the relevant provisions of the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity, subject to prudence check. The Capital Cost so determined shall form the basis of determination of tariff for Existing Projects and New Projects.
- 22.2 The norms for Additional Capitalisation and Renovation and Modernisation for a Generating Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.
- 22.3 The financial principles including principles governing Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Interest on Loan, Foreign Exchange Risk Variation, Interest on Working Capital, treatment of Tax on Income, norms for working capital etc. for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.

23 Financial Principles for Transmission and Distribution Business

- 23.1 The financial principles specified in the subsequent sections of this Chapter of these Regulations shall be applicable to the Transmission and Distribution Licensee.

24 Capital Cost

- 24.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:
 - (a) the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check;
 - (b) capitalised initial spares subject to the ceiling rates specified in this Regulation;
 - (c) the expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;
 - (d) additional capitalisation determined in accordance with Regulation 25;
 - (e) any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation, as admitted by the Commission after prudence check:

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:

Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use, shall be excluded from the capital cost:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use.

- 24.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of tariff:

Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan including the choice and manner of funding, interest during construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff.

- 24.3 The approved capital cost shall be considered for determination of tariff and if sufficient justification is provided for any escalation in the capital cost, the same may be considered by the Commission subject to prudence check:

Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then the actual capital cost shall be considered for determination of tariff of the Licensee.

- 24.4 The actual capital expenditure on Date of Commercial Operation for the original scope of work based on audited accounts of the Transmission Licensee and Distribution Licensee, limited to original cost may be considered subject to prudence check by the Commission.
- 24.5 Where the Bulk Power Transmission Agreement provides for a ceiling of capital cost, the capital cost to be considered shall not exceed such ceiling.
- 24.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost upto Cut-off Date, subject to the following ceiling norms:
- | | |
|--|------|
| a) Transmission Line & Distribution Line | 1.0% |
| b) Transmission Sub-station & Distribution Sub-station (Green Field) | 4.0% |
| c) Transmission Sub-station (Brown Field) | 6.0% |
| d) Series Compensation devices and HVDC Station | 4.0% |
| e) Gas Insulated Sub-station (GIS) | 5.0% |
| f) Communication System | 3.5% |
- 24.7 Any expenditure on the replacement, renovation and modernization or extension of life of old fixed assets, as applicable to the Transmission Licensee and Distribution Licensee, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost and shall be calculated as follows:

Net Value of Replaced Assets = OCFA – AD – CC

Where;

OCFA: Original capital cost of Replaced Assets

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets

CC: Total Consumer Contribution pertaining to the Replaced Assets:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

25 Additional Capitalisation

- 25.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, in respect of New Project or an Existing Project, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation and up to the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:
- Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;
 - Works deferred for execution;
 - Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with the provisions of Regulation 24.6;
 - Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court of law; and
 - Change in law or compliance with any existing law:

Provided that the details of works asset wise/work wise included in the original scope of work along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and the works deferred for execution shall be submitted along with the application for determination of tariff.

- 25.2 The capital expenditure incurred or projected to be incurred in respect of the New Project on the following counts within the original scope of work and after the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:
- (i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court of law;
 - (ii) Change in law or compliance with any existing law;
 - (iii) Liability for works admitted by the Commission after the cut-off date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;
 - (iv) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments, etc.
- 25.3 The capital expenditure, in respect of Existing Project, incurred or projected to be incurred on the following counts beyond the original scope of work and after the Cut-off Date, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:
- (i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a court of law;
 - (ii) Change in law or compliance of any existing law;
 - (iii) Any expenses to be incurred on account of need for higher security and safety of the capital asset as advised or directed by appropriate Government agencies or statutory authorities responsible for national security/internal security;
 - (iv) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments etc.;
 - (v) Any liability for works admitted by the Commission after the Cut-off Date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;
 - (vi) Any additional capital expenditure, which has become necessary for efficient operation of the transmission system. The claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by the documentary evidence like test results carried out by an independent agency in case of deterioration of assets, report of an independent agency in case of damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity for the technical reason such as increase in fault level; and
 - (vii) In case of transmission system, any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement due to obsolescence of technology, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, tower strengthening, communication equipment, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of porcelain insulator with polymer insulators, replacement of damaged equipment not covered by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation of transmission system:
- Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets including tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, computers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets, etc., bought after the Cut-off Date shall not be considered for additional capitalization for determination of tariff:
- Provided further that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation (R&M) or repairs and maintenance under O&M Expenses, the same expenditure cannot be claimed under this Regulation.
- 25.4 Impact of variation in additional capitalization on the tariff, as the case may be, shall be considered during truing up of each Financial Year of the Control Period.
- 25.5 In case of de-capitalisation of assets of a Generating Company or Transmission Licensee or Distribution licensee, as the case may be, the original cost of such asset as on the date of

decapitalisation shall be deducted from the value of gross fixed asset and corresponding loan as well as equity shall be deducted from outstanding loan and the equity respectively in the year such de-capitalisation takes place with corresponding adjustments in cumulative depreciation and cumulative repayment of loan, duly taking into consideration the year in which it was capitalised.

26 Consumer Contribution, Deposit Work, Grant and Capital Subsidy

- 26.1 The works carried out by the Transmission Licensee and Distribution Licensee after obtaining a part or all of the funds from the users shall be classified as Deposit Works;
- 26.2 Capital works undertaken by the Transmission Licensee and Distribution Licensee utilising grants received from the State and Central Governments, including funds under various schemes shall be classified under the category of Grants;
- 26.3 The works carried out with any other grant of similar nature or such amount received without any obligation to return the same and with no interest costs attached to such subvention shall also be classified as works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.
- 26.4 The expenses on such capital expenditure shall be treated as follows:
- a) normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed;
 - b) the debt to equity ratio shall be considered in accordance with Regulation 27, after deducting the amount of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;
 - c) depreciation to the extent of works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant shall not be allowed as specified in Regulation 31;
 - d) provisions related to return on equity, as specified in Regulation 28, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;
 - e) provisions related to interest on loan capital, as specified in Regulation 29, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

27 Debt to Equity Ratio

- 27.1 In case of Existing Projects, debt to equity ratio allowed by the Commission for determination of tariff for the period ending March 31, 2022 shall be considered:

Provided that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the equity capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

- 27.2 For New Projects, the debt-equity ratio as on the Date of Commercial Operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 24, after prudence check for determination of tariff:

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of tariff:

Provided also that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as a normative loan for the Licensee for determination of tariff:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment:

Provided further that the premium, if any, raised by the Licensee while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserves, for the funding of the scheme, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources are actually utilised for meeting the capital expenditure of the transmission system or the distribution system, and are within the ceiling of 30% of capital cost approved by the Commission.

- 27.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2022, as may be admitted by the Commission, as additional capital expenditure for determination of tariff, and renovation and modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in these Regulations.

28 Return on Equity

- 28.1 Return on equity shall be computed on the paid up equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use for the Transmission Licensee and shall be allowed in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
- 28.2 The return on equity for the Distribution Wires Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use at post-tax rate of return on equity specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
- 28.3 The return on equity for the Retail Supply Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 27 for the assets put to use, at the rate of sixteen (16) per cent per annum.
- 28.4 The return on equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of Year.

29 Interest on Loan

- 29.1 The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 27 on the assets put to use, shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on the loan:

Provided that interest and finance charges on capital works in progress shall be excluded:

Provided further that in case of De-capitalisation or retirement or replacement of assets, the loan capital shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of the de-capitalised or retired or replaced assets, based on documentary evidence.

- 29.2 The normative loan outstanding as on April 1, 2022, shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to March 31, 2021, from the gross normative loan.
- 29.3 Notwithstanding any moratorium period availed by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, the repayment of loan shall be considered from the first Year of commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed in accordance with Regulation 31.
- 29.4 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each Year applicable to the Transmission Licensee or the Distribution Licensee:

Provided that at the time of truing up, the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio during the Year applicable to the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be considered as the rate of interest after prudence check:

Provided also that if there is no actual loan for a particular Year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest for the actual loan shall be considered:

Provided further that if the Transmission Licensee or the Distribution Licensee does not have actual loan, then one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative loan.

- 29.5 The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying the weighted average rate of interest:

Provided that at the time of truing up, the normative average loan of the Year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the Year.

- 29.6 For new loans proposed for each Financial Year of the Control Period, interest rate shall be considered as lower of (i) one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points, and (ii) weighted average rate of interest proposed by the Distribution Licensee.

- 29.7 The above interest computation shall exclude the interest on loan amount, normative or otherwise, to the extent of capital cost funded by consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant, carried out by Transmission Licensee or Distribution Licensee.

- 29.8 The finance charges incurred for obtaining loans from financial institutions for any Year shall be allowed by the Commission at the time of Truing-up, subject to prudence check.

- 29.9 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to the approved completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt funds disproportionate to the actual requirement based on Scheme completion status, shall be allowed or disallowed partly or fully on a case to case basis, after prudence check by the Commission:

Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the Transmission or Distribution Licensee, any liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into account for computation of capital cost:

Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the amount of excess interest during construction that has been allowed by the Commission.

- 29.10 The Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings shall be shared between the equally between the beneficiaries; i.e., the Transmission Licensee and the Distribution Licensee or the Distribution Licensee and the Consumers of Distribution Licensee.

- 29.11 Interest shall be allowed on the amount held as security deposit held in cash from Retail Consumers at the Bank Rate as on 1st April of the Financial Year in which the Petition is filed:

Provided that at the time of truing-up, the interest on the amount of security deposit for the Year shall be considered on the basis of the actual interest paid by the Licensee during the Year, subject to prudence check by the Commission.

30 Foreign Exchange Rate Variation

- 30.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the transmission system or distribution system, in part or in full at its discretion.

- 30.2 The Licensee shall be permitted to recover the cost of hedging of foreign exchange rate variation corresponding to the foreign debt, in the relevant Year as an expense, subject to prudence check by the Commission, and extra rupee liability corresponding to such variation shall not be allowed against the hedged foreign debt.

- 30.3 To the extent that the foreign exchange exposure is not hedged, any extra rupee liability towards interest payment and loan repayment corresponding to the foreign currency loan in the relevant Year shall be allowed subject to prudence check by the Commission.

31 Depreciation

- 31.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission:

Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the retired or replaced or decapitalized assets:

Provided also that the no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

- 31.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the capital cost of the asset.

Provided further that the salvage value of Information Technology equipment and computer software shall be considered at zero (0) per cent of the allowable capital cost.

- 31.3 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets.

- 31.4 In case of existing assets, the balance depreciable value as on April 1, 2022, shall be worked out by deducting the cumulative depreciation as admitted by the Commission up to March 31, 2021, from the gross depreciable value of the assets.

- 31.5 The depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operations. In case of projected commercial operation of the assets during the Year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets:

Provided that depreciation shall be re-calculated during truing-up for assets capitalised at the time of truing up of each Year of the Control Period, based on documentary evidence of asset capitalised by the Applicant, subject to the prudence check of the Commission.

- 31.6 For Transmission Licensee, the depreciation shall be calculated at rates and norms specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.

- 31.7 The depreciation for a Distribution Licensee shall be calculated annually, based on the Straight Line Method, over the Useful Life of the asset at rates specified in Appendix I of these Regulations.

- 31.8 In addition to allowable depreciation, the Distribution Licensee shall be entitled to advance against depreciation (AAD), computed in the manner given hereunder:

AAD = Loan (raised for capital expenditure) repayment amount based on loan repayment tenure, subject to a ceiling of 1/10th of loan amount minus depreciation as calculated on the basis of these Regulations:

Provided that advance against depreciation shall be permitted only if the cumulative repayment upto a particular Year exceeds the cumulative depreciation upto that Year:

Provided further that advance against depreciation in a Year shall be restricted to the extent of difference between cumulative repayment and cumulative depreciation upto that Year.

- 31.9 The Distribution Licensee shall provide the list of assets added during each Year of Control Period and list of assets completing 90% of depreciation in the Year along with Petition for annual performance review, true-up and tariff determination for ensuing Year.

- 31.10 The remaining depreciable value for a Distribution Licensee shall be spread over the balance useful life of the asset, on repayment of the entire loan.

32 Interest on Working Capital

- 32.1 The norms for working capital for Transmission Licensee shall be as specified in Chapter 5 of these Regulations.

- 32.2 The norms for working capital for Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall be as specified in Chapter 6 and Chapter 7 of these Regulations respectively.

- 32.3 The interest on working capital shall be payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures.

- 32.4 The rate of interest on working capital shall be equal one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for

one (1) Year period, as may be applicable as on 1st April of the Financial Year in which the Petition is filed plus 200 basis points.

33 Tax on Income

- 33.1 The treatment of tax on income for a Transmission Licensee shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 33.2 The Commission in its MYT Order shall provisionally approve Income Tax payable for each Year of the Control Period, if any, based on the actual income tax paid, including cess and surcharge on the same, if any, as per latest audited accounts available for the Distribution Licensee, subject to prudence check.
- 33.3 Variation between Income Tax actually paid, including cess and surcharge on the same, if any, and approved, if any, on the income stream of the Licensed business of the Distribution Licensees shall be reimbursed to/recovered from the Distribution Licensees, based on the documentary evidence submitted at the time of truing up of each Year of the Control Period, subject to prudence check.
- 33.4 Under-recovery or over-recovery of any amount from the Consumers on account of such tax having been passed on to them shall be adjusted every Year on the basis of income-tax assessment under the Income-Tax Act, 1961, as certified by the statutory auditors. The Distribution Licensee may include this variation in its truing up Petition:

Provided that tax on any income stream other than the core business shall not be a pass-through component in tariff and tax on such other income shall be borne by the Distribution Licensee.

34 Rebate

- 34.1 The rebate to be provided by a Generating Company or Transmission Licensee to a Distribution Licensee for early payment of bills shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 34.2 Such rebate earned by the Distribution Licensee shall be considered under Non-Tariff Income for the Distribution Licensee.
- 34.3 Any rebate provided by the Generating Company or Transmission Licensee to the beneficiaries shall not be allowed as an expense for the Generating Company or Transmission Licensee, as the case may be.

35 Late Payment Surcharge

- 35.1 In case the payment of bills of transmission charges by a beneficiary is delayed beyond a period as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, a late payment surcharge shall be levied on the billed amount in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 35.2 The delayed payment charge earned by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall not be considered under its Non-Tariff Income.
- 35.3 The delayed payment charge paid or payable by the Distribution Licensee to the Generating Company or the Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for such Distribution Licensee.

36 Income from Other Business

- 36.1 Where the Transmission Licensee or Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the transmission or distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission along with its application for determination of tariff:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.

Chapter 4: Generation

37 Applicability

- 37.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for supply of electricity to Distribution Licensee from a Generating Station located in the State.
- 37.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Chapter in determining the tariff for supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee in the following cases:
- (a) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into subsequent to the date of effectiveness of these Regulations; or
 - (b) where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into prior to the date of effectiveness of these Regulations and either the Commission has not previously approved such agreement/arrangement or the agreement/arrangement envisages that the tariff shall be based on the Tariff Regulations notified by the Commission; or
 - (c) where the Distribution Licensee is engaged in the business of generation of electricity, in determining the price at which electricity is supplied by the Generating Station of the Distribution Licensee to its Retail Supply Business.
- 37.3 Notwithstanding anything contained in this Chapter 4, the Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

38 Components of Tariff

- 38.1 The Aggregate Revenue Requirement for a Generation Company shall comprise of the following components:
- a) Return on Equity;
 - b) Interest and finance charges on Loan;
 - c) Depreciation;
 - d) Interest on Working Capital;
 - e) Operation and maintenance expenses;
 - f) Income tax.
- 38.2 The treatment of each of the above components shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity.
- 38.3 The recovery of Aggregate Revenue Requirement and fuel cost for a Generation Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity.

39 Norms of Operation

- 39.1 The norms of operation for a Generating Station including Normative annual plant availability factor (NAPAF), Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF), Gross Station heat Rate, Auxiliary Consumption etc. shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity.

Chapter 5: Intra-State Transmission

40 Applicability

- 40.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for access and use of the intra-State transmission system in the States.

41 Components of Tariff

- 41.1 The annual transmission charges for each Financial Year of the Control Period shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the respective Financial Year of the Control Period, as reduced by the amount of Non-Tariff Income, income from Other Business and short-term transmission charges of the previous Year in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time:

Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of Section 63 of the Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission, the annual transmission charges shall be as per the annual Transmission Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded transmission projects.

- 41.2 The annual transmission charges of the Transmission Licensee shall be determined by the Commission on the basis of an application for determination of Aggregate Revenue Requirement made by the Transmission Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations.

- 41.3 The Aggregate Revenue Requirement for a Transmission Licensee shall comprise of the following components:

- a) Return on Equity;
- b) Depreciation;
- c) Interest and Finance Charges on Loan Capital;
- d) Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users;
- e) Operation and maintenance expenses;
- f) Income Tax

Less:

- g) Income from Open Access Charges, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time;
- h) Non-Tariff Income;
- i) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users and Income Tax for Transmission Licensees shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check.

42 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Transmission Licensees

- 42.1 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:

- a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
- b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
- c) Repairs and Maintenance expenses.

- 42.2 The Transmission Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the transmission Licensee, estimates of the actuals for the base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

- 42.3 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (1+WPI_{inflation})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI_{inflation})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+CPI_{inflation})$$

‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{inflation}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{inflation}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the $n-1^{th}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate.

42.4 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

42.5 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

42.6 For New Transmission Licensee, the Year-wise O&M norms shall be determined on case to case basis:

Provided that the same shall not apply to those New Projects, which are awarded on a competitive bidding basis.

Note: The term “New Transmission Licensee” shall mean the Transmission Licensee(s) for which transmission licence is granted by the Commission after the date of effectiveness of these Regulations, and whose transmission project assets are commissioned on or after April 1, 2022.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

43 Norms of Working Capital for Transmission Licensee

43.1 The Transmission Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Financial Year computed in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

44 Non-Tariff Income

44.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the transmission business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining annual transmission charges of the Transmission Licensee:

Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of Aggregate Revenue Requirement.

44.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

- a) Income from rent on land or buildings;
- b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
- c) Income from statutory investments;
- d) Interest on advances to suppliers/contractors;
- e) Rental from staff quarters;
- f) Rental from contractors;
- g) Income from hire charges from contractors and others;
- h) Income from advertisements, etc.;
- i) Miscellaneous receipts like parallel operation charges;
- j) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- k) Excess found on physical verification;
- l) Interest on investments, fixed and call deposits and bank balances;
- m) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Licensed Business of the Transmission Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

45 Norms of Operations for Transmission Licensee

45.1 The norms of operations for a Transmission Licensee shall be applicable as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

Provided that sharing of incentive, if any with the beneficiaries for exceeding the norms of operations shall be in accordance with provisions of prevalent CERC Tariff Regulations.

46 Transmission Loss

46.1 The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by the State Load Despatch Centre, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the intra-State transmission system.

47 Sharing of charges for Intra-State Transmission Network

47.1 The Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, as approved by the Commission, shall be shared by all long-term users and medium-term users of the transmission system on a monthly basis in the ratio of their respective Allotted Transmission Capacity to the total Allotted Transmission Capacity, in accordance with the following formula:

$$ATC_n = (\text{Transmission ARR} / 12) \times (CC_n / SCC)$$

Where,

ATC_n = annual transmission charges payable by the n_{th} long-term user or medium-term user of the transmission system;

Transmission ARR = Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, determined in accordance with these Regulations;

CC_n = Allotted Transmission Capacity by the n^{th} long-term user or medium-term user of the transmission system;

SCC = sum of Allotted Transmission Capacity by all long-term users and medium-term users of the transmission system:

Provided that the ATC_n shall be payable on a monthly basis by each long-term user or medium-term user of the transmission system and shall be collected by the State Transmission Utility (STU).

47.2 The short-term Open Access Consumers shall pay transmission charges on Rs/MW/day basis determined in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

47.3 75% of charges collected from the short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the long-term and medium-term Open Access Consumers. The remaining 25% of the charges collected from short-term Open Access users shall be retained by the Transmission Licensee.

48 Consequential Impact of any Government of India Scheme

48.1 The consequential impact of any Government of India scheme for waiver/reduction of transmission charges, incentives, and losses for any entity/ies, on the transmission charges payable by the other entities, shall be addressed through separate Orders to be issued by the Commission from time to time.

Chapter 6: Distribution Wires Business

49 Separation of Accounts of Distribution Licensee

49.1 Every Distribution Licensee shall segregate accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business and shall prepare an Allocation Statement. The wheeling charges pertaining to Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of these segregated accounts:

Provided that in case complete accounting segregation has not been done, the following Allocation Statement shall be applicable:

Table 1: Allocation Statement for segregation of Distribution Wires Business and Retail Supply Business

Particulars	Wires Business (%)	Retail Supply Business (%)
Power Purchase Expenses	0%	100%
Inter-State Transmission Charges	0%	100%
Intra-State Transmission Charges	0%	100%
Employee Expenses	40%	60%
Administration & General Expenses	50%	50%
Repair & Maintenance Expenses	90%	10%
Capital Cost	90%	10%
Depreciation	90%	10%
Interest on Long-term Loan Capital	90%	10%
Interest on working capital and on consumer security deposits	10%	90%
Bad Debts Written off	0%	100%
Income Tax	90%	10%
Non-Tariff Income	10%	90%
Income from Other Business	50%	50%

Provided further that the above Allocation Statement shall be applied for all or any of the heads of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

50 Applicability

- 50.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply to the determination of wheeling charges for usage of distribution wires of a Distribution Licensee by a distribution system user, other than retail supply Consumers.

51 Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business

- 51.1 The wheeling charges for Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement, which shall comprise of the following:

- a) Return on Equity;
- b) Interest and finance charges on Loan;
- c) Depreciation;
- d) Interest on Working Capital and deposits from distribution system users;
- e) Operation and maintenance expenses;
- f) Income Tax;

Less:

- g) Non-Tariff Income;
- h) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan Capital, Depreciation, Interest on Working Capital, Interest on deposits from Consumers and distribution system users, and Income Tax for Distribution Wires Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

52 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Distribution Wires Business

- 52.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Wires Business shall be computed in accordance with this Regulation.
- 52.2 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:
- a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
 - b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
 - c) Repairs and Maintenance expenses.
- 52.3 The Distribution Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the distribution Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.
- 52.4 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (1+WPI_{inflation})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (1+CPI_{inflation})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1+CPI_{inflation})$$

‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{inflation}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{inflation}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the $n-1^{th}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee’s filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate;

Provided that in case the Distribution Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, O&M Expenses shall be determined on case to case basis.

52.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

52.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

53 Norms of Working Capital for Distribution Wires Business

53.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Distribution Wires Business for the Financial Year, computed as follows:

- O&M Expenses for one (1) month; plus
- Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
- Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from charges for use of distribution wires at the prevailing tariff;

Less

- Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from distribution system users except the security deposits held in the form of Bank Guarantees;

Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

54 Non-Tariff Income

- 54.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Wires Business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining the wheeling charges of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of wheeling charges.

- 54.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

- a) Income from rent of land or buildings;
- b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
- c) Income from statutory investments;
- d) Income from interest on contingency reserve investment;
- e) Interest on advances to suppliers/contractors;
- f) Rental from staff quarters;
- g) Rental from contractors;
- h) Income from hire charges from contractors and others;
- i) Income from advertisements, etc.;
- j) Miscellaneous receipts;
- k) Excess found on physical verification;
- l) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- m) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

55 Determination of Wheeling Charges

- 55.1 The Commission shall specify the Wheeling Charge of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:

Provided that the revenue from wheeling charges paid by the distribution system users other than the retail Consumers under the above proviso shall be used to reduce the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Wires Business to be recovered from the retail Consumers of the concerned Distribution Licensee, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

56 Wheeling Losses

- 56.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the approved level of wheeling losses arising from the operation of the distribution system, as stipulated in the respective Tariff Order.

Chapter 7: Retail Supply of Electricity

57 Applicability

- 57.1 These Regulations shall apply to determination of tariff for retail supply of electricity by a Distribution Licensee to its Consumers.

58 Aggregate Revenue Requirement for Retail Supply Business

58.1 The tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Retail Supply Business for the respective Years of the Control Period, as approved by the Commission and comprising the following components:

- a) Cost of own power generation and power purchase expenses from other sources;
- b) Inter-State transmission charges;
- c) Intra-State transmission charges;
- d) SLDC fees and charges;
- e) Balance Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business, as determined under Chapter 6 of these Regulations, after deducting income from wheeling charges payable by distribution system users other than the retail Consumers getting electricity supply from the same Distribution Licensee in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time;
- f) Provision for bad and doubtful debts;
- g) Return on Equity capital;
- h) Operation and Maintenance Expenses;
- i) Depreciation;
- j) Interest and finance charges on Loan Capital;
- k) Interest on Working Capital;
- l) Interest on consumer security deposits;
- m) Income Tax;

Less

- n) Non-Tariff income;
- o) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations;
- p) Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge;
- q) Receipts on account of Additional Surcharge:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Interest on consumer security deposits, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and Income Tax for Retail Supply Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc. or penalty imposed by Commission on Licensee for non-compliance with Renewable Purchase Obligations in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010, as amended from time to time shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

58.2 The tariff for retail supply by the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of tariff filed by the Distribution Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations:

Provided that the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee shall be allocated or apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with the Table 1 in Regulation 49, till the accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business are not separated:

Provided further that the tariff for retail supply may comprise of any combination of fixed/demand charges, energy charges, and any other charges, for the purpose of recovery from the Consumers, as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Commission may determine the area-wise tariff for Distribution Licensee based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission.

59 Cost of Power Purchase

- 59.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover the cost of power generated by the Generating Stations owned by it or purchased from approved sources for supply to Consumers based on the power procurement plan of the Distribution Licensee, approved by the Commission.
- 59.2 The Distribution Licensee shall recover the incremental cost on account of Fuel and Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA) in accordance with the formula and related terms and conditions as may be prescribed by the Commission in its Orders from time to time. The Commission shall also specify the categories of Consumers for recovery of the FPPCA charge.

60 Transmission Charges

- 60.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover transmission charges payable for access to and use of the inter-state and intra-State transmission system in accordance with the tariff approved by the Commission under Chapter 5 of these Regulations.

61 Operation and Maintenance (O&M) expenses for Retail Supply Business

- 61.1 The Operation and Maintenance Expenses for the Retail Supply Business shall be computed in accordance with this Regulation.
- 61.2 O&M Expenses shall comprise of the following:
- Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
 - Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
 - Repairs and Maintenance expenses.
- 61.3 The Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the Distribution Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.
- 61.4 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (1 + WPI_{\text{inflation}})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1 + G_n) \times (1 + CPI_{\text{inflation}})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (1 + CPI_{\text{inflation}})$$

‘K’ is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee’s filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{\text{inflation}}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{inflation}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the Distribution Licensee for the $n-1^{th}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee's filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate:

Provided that in case the Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, the O&M Expenses shall be determined on a case to case basis.

61.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

61.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

Provided that at the time of truing up, the variation in the normative and actual O&M expenses shall be dealt in accordance with Regulation 15.

62 SLDC Fees & Charges

62.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover SLDC fees and charges payable to SLDC in accordance with the tariff approved by the Commission.

63 Provision for bad and doubtful debts

63.1 The Commission may allow bad debts written off as a pass through in the Aggregate Revenue Requirement, based on the trend of bad debts written off in the previous years, subject to prudence check:

Provided that the Commission shall true up the bad debts written off in the Aggregate Revenue Requirement, based on the actual write off of bad debts excluding delayed payment charges waived off, if any, during the year, subject to prudence check:

Provided also that the provision for bad and doubtful debts shall be limited to 1% of the annual Revenue Requirement of the Distribution Licensee:

Provided further that if subsequent to the write off of a particular bad debt, revenue is realised from such bad debt, the same shall be included as an uncontrollable item under the Non-Tariff Income of the year in which such revenue is realised.

64 Norms of Working Capital for Retail Supply Business

64.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Retail Supply Business for the Financial Year, computed as follows:

- O&M Expenses for one (1) month; plus
- Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
- Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from Consumers at the prevailing tariff;

Less

- d) Power Purchase cost for one (1) month; plus
- e) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from Consumers except the security deposits held in the form of Bank Guarantees:

Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

65 Non-Tariff Income

- 65.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the retail supply of electricity as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the tariff for retail supply of electricity by the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of tariff.

- 65.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

- a) Income from rent of land or buildings;
- b) Income from sale of scrap in excess of 10% of the salvage value;
- c) Income from statutory investments;
- d) Interest on advances to suppliers/contractors;
- e) Rental from staff quarters;
- f) Rental from contractors;
- g) Income from hire charges from contractors and others;
- h) Income from advertisements, etc.;
- i) Meter/metering equipment/service line rentals;
- j) Service charges;
- k) Consumer charges;
- l) Recovery for theft and pilferage of energy;
- m) Rebate availed on account of timely payment of bills;
- n) Miscellaneous receipts;
- o) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- p) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Retail Supply Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income:

Provided further that any income earned by a Distribution Licensee by sale of power to other Distribution Licensees or to Consumers as per Section 49 of the Act using the existing power purchase agreements or bulk supply capacity allocated to the Distribution Licensee's Area of Supply shall be reduced from the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee for the purpose of determination of tariff. Such reduction shall be carried out in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

66 Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge

- 66.1 The Cross-Subsidy Surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.

- 66.2 The Additional surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.

67 Distribution Losses

- 67.1 The Distribution Licensee shall recover the approved level of distribution losses arising from the Retail Supply of electricity.
- 67.2 The Commission may stipulate a trajectory for distribution losses for the Control Period in accordance with these Regulations, as part of the Multi Year Tariff Order.
- 67.3 Any variation between the actual level of distribution losses and the approved level shall be dealt with, as part of the Truing up exercise in accordance with Regulation 15.

68 Determination of Tariff

- 68.1 The Commission may categorize Consumers on the basis of their load factor, power factor, voltage, total consumption of electricity during any specified period or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required and any other factor as considered appropriate by the Commission.
- 68.2 The Commission shall endeavour to determine cost of supply for each category/ sub-category of Consumers.
- 68.3 The Commission shall endeavour to reduce gradually the cross-subsidy between Consumer categories with respect to the cost of supply in accordance with the provisions of the Act.
- 68.4 The tariff proposal by Licensee and the tariff determination by the Commission shall be based on the following principles:
- (a) The tariff for all categories shall preferably be two part, consisting of fixed and variable charges.
 - (b) The fixed charges in tariff shall progressively reflect actual fixed cost incurred by Distribution Licensee;
 - (c) The overall retail supply tariff for different Consumer categories shall progressively reflect the cost of supply for respective categories of Consumers;
 - (d) The tariff for residential Consumers shall be set considering the affordability of tariff for various class of Consumers;
 - (e) The tariff shall be set in such a manner that it may not present a tariff shock to any category of Consumers.

Chapter 8: Miscellaneous

69 Saving of Inherent Power of the Commission

- 69.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- 69.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 69.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

70 Issue of Orders and Practice Directions

70.1 Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and Practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters.

71 Power to amend

71.1 The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations following the due process of law.

72 Power to remove difficulties

72.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

73 Power of Relaxation

73.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

74 Interpretation

74.1 If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./549/2020-21]

Appendix –I: Depreciation Schedule and Useful Life for assets**(a) Generation and Transmission Assets**

The Useful Life and depreciation rates for generation and transmission assets shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

(b) Distribution Assets

S. No	Asset Class	Useful Life (Years)	Rate (%)
1	Land owned under full title	Infinity	0
2	Land held under lease		
(A)	For investment in land	Period of lease or the period remaining unexpired on the assignment of the lease	0
(B)	For cost of clearing site	Period of lease remaining unexpired at the date of clearing the site	0
3	Assets purchased new		
(A)	Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above:		
(i)	Offices and showrooms	50	1.80
(ii)	Temporary erection such as wooden structures	5	18.00
(iii)	Roads other than kutchha roads	50	1.80

S. No	Asset Class	Useful Life (Years)	Rate (%)
(iv)	Others	50	1.80
(B)	Transformers, transformer (kiosk) substation equipment & other fixed apparatus (including plant foundations)		
(i)	Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes (kVA) and over	25	3.60
(ii)	Others	25	3.60
(C)	Switchgear, including cable connections	25	3.60
(D)	Lightning arrestors:		
(i)	Station type	25	3.60
(ii)	Pole type	15	6.00
(iii)	Synchronous condenser	35	2.57
(E)	Batteries	5	18.00
(F)	Underground cable including joint boxes and disconnected boxes	35	2.57
(G)	Cable duct system	50	1.80
(H)	Overhead lines including supports:		
(i)	Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV	35	2.57
(ii)	Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 11 kV but not exceeding 66 kV	25	3.60
(iii)	Lines on steel or reinforced concrete supports	25	3.60
(iv)	Lines on treated wood supports	25	3.60
(I)	Meters		
	Electro Mechanical	15	6.00
	Electronic/Smart Meters	10	9.00
(J)	Self propelled vehicles	5	18.00
(K)	Air conditioning plants:		
(i)	Static	15	6.00
(ii)	Portable	5	18.00
(L)	Others		
(i)	Office furniture and fittings	15	6.00

S. No	Asset Class	Useful Life (Years)	Rate (%)
(ii)	Office equipment	15	6.00
(iii)	Internal wirings including fittings and apparatus	15	6.00
(iv)	Street Light fittings	15	6.00
(M)	Apparatus let on hire:		
(i)	Other than motors	5	18.00
(ii)	Motors	15	6.00
(N)	Communication equipment		
(i)	Radio and higher frequency carrier systems	15	6.00
(ii)	Telephone lines and telephones	15	6.00
(O)	I.T. Equipment and Software	6.67	15.00
(P)	Assets purchased in second hand and assets not otherwise provided for in the schedule	such reasonable period as the Commission determines in each case having regard to the nature, age and conditions of assets at the time of its acquisition by the current owner	